सूर्योदय 5:50 सूर्यास्त 6:59

आज का तापमान

शिमला	17.0 न्यू	24.5 अधि
धर्मशाला	20.1 न्यू	28.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	76,909
निफ्टी	24,078

सोना 1,53,000 चांदी 2,27,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | वीरवार, 20 अगस्त 2026 | 4 भाद्रपद, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 115, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

जम्मू-कश्मीर भारत का अहम हिस्सा : अमेरिकी राजदूत

एजेंसी, श्रीनगर। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को कहा जम्मू-कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। गोर ने जम्मू-कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान कहा, मैं पहली बार इस जगह का दौरा कर रहा हूं। यह एक अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत जगह है। गोर ने सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका जम्मू-कश्मीर की यात्रा को लेकर जारी अपनी एडवाइजरी पर फिर से विचार करेगा। गोर ने कहा, अमेरिका यात्रा चेतावनियां जारी करता है और समय-समय पर उनकी समीक्षा भी करता है।

दिल्ली में सीएनजी स्टेशन पर गैस टैंक फटा, तीन की मौत

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली के टिकरी कलां इलाके में बुधवार को एक सीएनजी स्टेशन पर वाहन में गैस भरते समय उसके गैस टैंक में जोरदार विस्फोट हो गया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट की चपेट में आने से पास में खड़े छह लोग घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा को घटना की सूचना अपराह्न 3.37 बजे मिली, जिसके बाद छह दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। अधिकारी ने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।

फिल्म 'काला हिरण' का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

एजेंसी, नई दिल्ली। फिल्म 'काला हिरण-द बैटल फॉर लीगेसी' का मामला उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। फिल्म के निर्माता अमित जानी ने फिल्म पर दिल्ली उच्च न्यायालय के रोक के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। फिल्म के निर्माता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 27 जुलाई के फिल्म के टीजर और उससे जुड़े प्रमोशनल कंटेंट को हटाने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश फिल्म निर्माता की अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाता है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म बनाना और किसी सार्वजनिक घटना को अपनी कहानी के नजरिये से दिखाना अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आता है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में भी फिल्म के निर्माता की ओर से यही दलील दी गई थी कि टीजर में कहीं सीधे तौर पर सलमान खान का नाम नहीं लिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में सलमान खान ने अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा की मांग की थी।

बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं माता-पिता

बढ़ती उम्र का मतलब असुरक्षा या अपमान नहीं, हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकारः सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सीनियर सिटीजन्स अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं।

कोर्ट ने कहा कि बढ़ती उम्र का मतलब असुरक्षा या अपमान नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवनभर गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी पलट दिया, जिसमें बेटे और बहू को मकान से बेदखल करने के ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश को रद्द किया गया था। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों की गरिमा के लिए ट्रिब्यूनल के पास बच्चों को संपत्ति से निकालने का आदेश देने का अधिकार है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा व जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि कानून का मकसद बुजुर्गों की गरिमा और सुरक्षा तय करना है। सभ्य समाज का स्तर अक्सर इस बात से तय होता है कि वह अपने

◆ कानून का मकसद बुजुर्गों की गरिमा और सुरक्षा तय करना

बुजुर्गों को कितनी गरिमा, सम्मान और सुरक्षा देता है।

यह मामला लखनऊ के विकास नगर निवासी रवि कांत गुप्ता की अपील से जुड़ा था। गुप्ता ने 5 जून 2022 को अपने बेटे को मकान से निकालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दिया था। यह मकान उनकी खुद की खरीदी हुई संपत्ति थी। मामला तब सामने आया, जब गुप्ता की 81 साल की मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। एसडीएम ने 15 नवंबर 2022 को बेटे की बेदखली का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने 9 अगस्त 2023 को इसे बरकरार रखते हुए बेटे और बहू को मकान खाली करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश में दखल देकर गलती की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण और सुरक्षा के लिए जरूरी होने पर ट्रिब्यूनल बेदखली का आदेश दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि एक्ट की धारा 7 के तहत ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं और धारा 8 उन्हें सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां देती है। वहीं, धारा 27 सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है। इसलिए ट्रिब्यूनल को कानून के उद्देश्य को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने की शक्ति भी है।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली- नीट का सिस्टम सुरक्षित, तोड़ना मुश्किल

एजेंसी, नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नीट परीक्षा सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें सेंध लगाना मुश्किल है। पेपर तैयार करने से लेकर एग्जाम सेंटर में पहुंचने तक पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीयता रखा जाता है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से यूपीएससी जैसा मजबूत परीक्षा सिस्टम बनाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी समझने वाले अधिकारियों को शामिल करना चाहिए। साथ ही अनुभवी अधिकारियों के बार-बार ट्रांसफर से बचने की सलाह दी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट, एफएआईएमए और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें एनटीए को भंग करने और पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत निगरानी सिस्टम की मांग की गई है।

यूपीएससी जैसा सिस्टम बनाएं

सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने बाद दोबारा कहा कि एनटीए को यूपीएससी की तरह ऐसा मजबूत सिस्टम बनाना चाहिए, जिसमें परीक्षा कराने का अनुभव अधिकारियों के ट्रांसफर होने के बाद भी संस्था के पास बना रहे। कोर्ट ने कहा कि कागज पर प्रक्रिया बेहतर दिख सकती है, लेकिन असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि एक परीक्षा के बाद अगली परीक्षा तक व्यवस्था में वही कमजोरियां दोबारा न लौटें।

कोलकाता की पांच मंजिला बिल्डिंग में आग, 9 की मौत

एजेंसी, कोलकाता। कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित पांच मंजिला बिल्डिंग में मंगलवार रात करीब 1:45 बजे आग लग गई। बिल्डिंग के अंदर कई होटल थे। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, इनमें 2 महिलाएं और एक 4 साल का बच्चा शामिल है। सभी बेहोशी की हालत में मिले थे। 6 लोग घायल हुए हैं। अब तक 80 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।

आग लगने के समय होटलों में ज्यादातर लोग सो रहे थे। बिल्डिंग में धुआं भरने के कारण उनका दम घुटने लगा। मरने वालों में भारतीय और बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां, पुलिस व डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें मौके पर पहुंचीं। घने धुएं के कारण दमकलकर्मियों को ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। पश्चिम बंगाल

◆ मंत्री बोले- अंदर की व्यवस्था देखकर हैरान हूं

के फायर डिपार्टमेंट मंत्री कौशिक चौधरी ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद बताया कि शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है, लेकिन इसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद होगी। मंत्री ने कहा कि इमारत के अंदर की स्थिति बेहद खराब थी और यहां कई होटल चल रहे थे। उन्होंने कहा कि वहां की व्यवस्था देखकर वे हैरान हैं। मंत्री के मुताबिक, बिल्डिंग मैनेजमेंट ने बुनियादी सुरक्षा और निर्माण नियमों का पालन नहीं किया था।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा में पढ़ रहे 14 देशों के विद्यार्थियों से किया संवाद

'गो ग्लोबल' सोच के साथ बढ़ें युवा : नायब सैनी

एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा को 'गो ग्लोबल' अप्रोच के साथ दुनिया से जोड़ने और युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थियों के साथ संवाद किया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपस्थित विदेशी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और अन्य आधुनिक तकनीकों ने शिक्षा, चिकित्सा, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर पैदा किए हैं। ऐसे में युवाओं को लगातार सीखते रहने, नई तकनीकों को अपनाने और बदलती दुनिया के साथ कदम

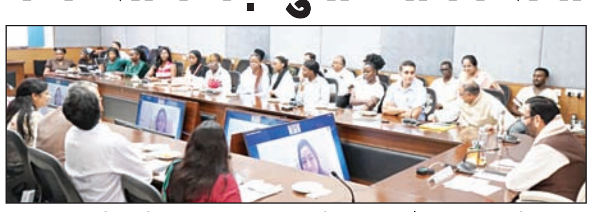

मिलाकर आगे बढने् की आवश्यकता है। 'गो ग्लोबल' अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए युवाओं को वैश्विक अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र और महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना में पढ़ रहे 14 देशों के विद्यार्थी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से उनके अध्ययन और शोध कार्य को लेकर सीधा संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि वे जिस विषय पर शोध कर रहे हैं, उसमें उन्हें क्या नया सीखने को मिला और हरियाणा में उनका अनुभव कैसा रहा।

विद्यार्थियों ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपने अनुभव साझा किए और हरियाणा में शिक्षा, शोध, विश्वविद्यालयों के वातावरण, यहां की संस्कृति और लोगों से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में विश्वविद्यालय का समय केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं होता। इस दौरान प्राप्त शिक्षा, अनुभव और यादें जीवनभर साथ रहती हैं।

तमिलनाडु के विधायकों को मिलेगी नई कार

एजेंसी, चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सभी विधायकों को सरकारी कार देने और वाहन के रखरखाव, ईंधन व ड्राइवर के खर्च के लिए हर महीने 75 हजार रुपए का भत्ता देने का ऐलान किया। इसके अलावा, विधायकों को असिस्टेंट रखने के लिए 25 हजार रुपए मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। विधानसभा में विधायकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। इसी दौरान टीवीके विधायक सिंधु ने तमिल सुपरस्टार और पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन की फिल्म 'पड़गोट्टी' का मशहूर गीत 'कोडुत्तदेलाम कोडुत्तान' गाकर मुख्यमंत्री विजय का आभार जताया। इस गीत का भावार्थ है- 'उसने सब कुछ दिया, किसके लिए दिया? किसी एक के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए।' इसे टीएम सौंदरराजन ने गाया था।

रक्षाबंधन पर महिलाओं को धामी सरकार की सौगात 28-29 अगस्त को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा

एजेंसी, देहरादून। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने 28 और 29 अगस्त को उत्तराखंड की महिलाओं के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में शत-प्रतिशत किराया छूट के साथ निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर परिवहन निगम को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शासनादेश के अनुसार 28 और 29 अगस्त को प्रदेश की महिलाएं उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में बिना कोई किराया दिए यात्रा कर सकेंगी। रक्षाबंधन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मायके और अन्य परिजनों से मिलने के लिए यात्रा

◆ यात्रा से होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी सरकार

◆ महिलाओं के आवागमन को सुगम बनाने की पहल

करती हैं। ऐसे में सरकार की इस पहल से उन्हें सुरक्षित, सुगम और निशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी।

सरकार का उद्देश्य त्योहार के दौरान महिलाओं के आवागमन को आसान बनाने के साथ उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करना है। अपर सचिव शासन रीना जोशी की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि निशुल्क यात्रा सुविधा के कारण उत्तराखंड परिवहन निगम पर पड़ने वाले अतिरिक्त व्ययभार की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। परिवहन विभाग ने निगम को शासनादेश के अनुरूप तत्काल आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

इस निर्णय से रक्षाबंधन के अवसर पर अपने परिवार और मायके जाने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से राहत मिलने के साथ सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों को योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

मराठी नहीं जानने वाले महाराष्ट्र में नहीं चला पाएंगे ऑटो-टैक्सी

एजेंसी, मुंबई। मराठी भाषा नहीं जानने वाले ड्राइवर अब महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी नहीं चला पाएंगे। राज्य में 20 अगस्त से उन ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ अभियान शुरू होगा, जिनके पास मराठी का 'वर्किंग नॉलेज' यानी कामचलाऊ भाषा का ज्ञान नहीं है। यह अभियान पूरे राज्य में एक महीने तक चलेगा। ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने इसका ऐलान किया।

उन्होंने कहा कि ड्राइवरों को पहले नोटिस देकर 3 महीने में मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी मराठी नहीं सीखने पर लाइसेंस और बैज सस्पेंड किया जाएगा। मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवि गायकवाड़ पूरे महाराष्ट्र में इस एक महीने के अभियान की निगरानी करेंगे। आरटीओ की फ्लाइंग स्क्वॉड ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की जांच करेंगी और नए नियमों का पालन हो

◆ पहले नोटिस देंगे, 3 महीने में नहीं सीखे, तो लाइसेंस होगा रद्द : ट्रांसपोर्ट मंत्री

रहा है या नहीं, यह देखेंगी। जांच के दौरान वेरिफिकेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। सेवा सारथी ऑटो-रिक्शा टैक्सी एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन के नेता डीएम गोसावी ने कहा कि सरकार ने मराठी का वर्किंग नॉलेज होना जरूरी कर दिया है, लेकिन यह साफ नहीं किया कि आखिर कितनी मराठी जानना जरूरी होगी। उनका कहना है कि नियम स्पष्ट नहीं होने पर आरटीओ में भ्रष्टाचार और ड्राइवरों के आर्थिक शोषण की आशंका बढ़ सकती है।

छात्रों के समर्थन में आरजेडी ने किया लोकभवन मार्च

वाटर कैनन चलाई, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस पर बोतलें फेंकी

एजेंसी, पटना। बिहार के सीवान में छात्र आंदोलन के दौरान एके-47 से फायरिंग के मामले को लेकर तेजस्वी यादव बुधवार को सड़क पर उतरे। उन्होंने पटना में जेपी गोलंबर से लोकभवन तक मार्च निकाला। करीब 5 किलोमीटर लंबे मार्च में उनके साथ करीब 5 हजार समर्थक मौजूद रहे।

समर्थकों के साथ तेजस्वी डाकबंगले पर लगाई बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गए। इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। इसके बाद तेजस्वी को हिरासत में लिया गया। हालांकि, एक घंटा बाद उन्हें छोड़ दिया। तेजस्वी ने कहा कि मैं जेल से डरने वाला नहीं हूं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ था। जो सत्ता में आया है, उसका जाना तय है। कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस के ऊपर पानी की बोतलें भी फेंकीं। कुछ कार्यकर्ता लकड़ी की एके-47

लेकर पहुंचे थे। एएसपी लॉ एंड आर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने जवानों को निर्देश दिया कि झंडे का सम्मान और लाठी का इस्तेमाल समझदारी से करें। तेजस्वी यादव 5 साल बाद सड़क पर संघर्ष करने उतरे। इससे पहले 2021 में बिहार सरकार के एक प्रस्ताव के खिलाफ तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे थे। लोकभवन मार्च के दौरान पुलिस ने तेजस्वी यादव और आरजेडी सांसद मीसा भारती को डिटेन कर लिया। दोनों को सचिवालय थाना ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मीसा भारती ने कहा, 'पुलिस मुझे यहां हिरासत में लेकर आई थी। सभी का नाम, पता और बायोडाटा लिया गया और उसके बाद हमें छोड़ दिया गया है।' वहीं, तेजस्वी यादव ने कहा, 'छात्रों पर एके-47 चलाने का आदेश किसने दिया, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जब तक मुख्यमंत्री जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे पूरी घटना का वक्तव्य नहीं देंगे और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।'

सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर पंजाब सीएम मान बोले-

चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को जेल भेजना एंटी-डेमोक्रेटिक

एजेंसी, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पूर्व मंत्री और पंजाब के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सीएम भगवंत मान ने भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि ईडी पार्टी का काम ही यही है।

पंजाब में इनके पैर नहीं लग रहे हैं, वह जिस केस की वे बात कर रहे हैं, उस समय जैन जेल में थे। हमें उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा। एक तरीका चल पड़ा है कि जहां इलेक्शन हो रहा है, वहां पर विरोधी पार्टियों के बड़े नेताओं को दो-तीन महीने के लिए जेल में डाल दो, फिर बाद में देखते रहो। भाजपा का काम करने का तरीका एंटी-डेमोक्रेटिक है। भाजपा घटिया हथकंडे अपना रही है। पंजाब में उनके पैर नहीं लग रहे हैं इसलिए पंजाब के सह-प्रभारी को

◆ पंजाब में पैर नहीं लग रहे इसलिए सह-प्रभारी को पकड़ा

पकड़ लिया। हमें उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, जैसे अरविंद केजरीवाल का केस ही कोर्ट ने नहीं

माना। भाजपा घटिया हथकंडे अपना रही है। दिल्ली इलेक्शन के समय संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था। ईडी के पत्रों पर सीएम ने कहा कि वह किसी भी चीज का पुलिंदा लिखकर भेज देते हैं। किसी चीज में कोई सच्चाई नहीं है। विरोधी पार्टियों को कोई मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वे हम पर उंगली उठा रहे हैं। विरोधी पार्टी वालों को मेरी सलाह है कि पहले अपनी लड़ाई ठीक कर लें, बाकी बाद में देख लेंगे।

यमुना सिटी में 5,145 करोड़ के दो औद्योगिक प्लांट का मुख्यमंत्री योगी ने किया शिलान्यास

एजेंसी, नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ट्रैक्टर निर्माण व ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए हार्नेस वायर बनाने के दो प्लांट का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से दिल्ली में आयोजित एक जापानी निवेश कार्यक्रम के दौरान किया।

इन दोनों प्लांट में करीब 5145 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। पहले मुख्यमंत्री को यमुना सिटी आना था। अधिकारियों के मुताबिक बाद में कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ। मुख्यमंत्री ने बुधवार सुबह नौ बजे वर्चुअल जुड़कर शिलान्यास किया। यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरके सिंह ने बताया कि सेक्टर-10 में जापान और भारतीय कंपनी के संयुक्त उपक्रम एस्कॉर्ट-कुबोता का प्लांट लगाया

◆ सेक्टर-10 में बनेगा ट्रैक्टर निर्माण प्लांट, 4,500 करोड़ रुपए का निवेश

जाना है। यहां ट्रैक्टर और खेती में उपयोग होने वाले दूसरे उपकरण बनाए जाने हैं। इस प्लांट के लिए यमुना प्राधिकरण ने पूर्व में करीब 190 एकड़ जमीन आवंटित की थी, अब शिलान्यास के बाद कंपनी यहां निर्माण शुरू करेगी, जिससे उत्पादन भी जल्दी शुरू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि करीब 4500 करोड़ रुपए का निवेश इस प्रोजेक्ट में कंपनी करेगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा स्पार्क मिंडा समूह की कंपनी मिंडा कॉरपोरेशन का सेक्टर-24 में प्लांट का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने बुधवार को किया। करीब 23 एकड़ जमीन कंपनी को यमुना प्राधिकरण ने आवंटित की है।

कोरियन कंपनी डेसुंग और भारतीय कंपनी लोकोनाव के साथ साझेदारी में यहां करीब 645 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इस प्लांट में हार्नेस वायर के अलावा इग्निशन स्विच कम स्टीयरिंग लॉक और मेकाट्रोनिक्स कंपोनेंट का निर्माण किया जाना है। इस यूनिट से लगभग 2270 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि यह कंपनी इसके अलावा सेक्टर-10 में भी एक प्लांट लगाने की योजना पर काम कर रही है।

उद्घाटन उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री रेखा ने 200 ईवी बसों, 'लेडीज स्पेशल बस सेवा' को दिखाई हरी झंडी

महिलाओं की सुरक्षा के लिए लेडीज स्पेशल बसें शुरू

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को 200 नई इलेक्ट्रिक बसों, दिल्ली-करनाल अंतरराज्यीय ईवी-बस सेवा और लेडीज स्पेशल बस सेवा का हरी झंडी दिखाई।

इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के राजघाट डिपो-I में ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन भी किया। यह ईवी चार्जिंग स्टेशन लगभग 5.50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस मौके पर दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, स्थानीय विधायक सूर्य प्रकाश खत्री मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'शक्ति की सप्त-धारा' की सोच से

प्रेरित ये पहल सस्टेनेबल मोबिलिटी को मजबूत करती हैं और साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा को भी बढ़ावा देती हैं।

उन्होंने कहा कि पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित इन 'लेडीज स्पेशल बसों' में पैनिक बटन भी होंगे जो सीधे दिल्ली पुलिस की 112 पीसीआर सेवा से जुड़े होंगे, जिससे आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद मिल सकेगी। उपराज्यपाल ने कहा कि 'ईज ऑफ लिविंग', सस्टेनेबल मोबिलिटी और 'विकसित भारत 2047' की राह पर एक साफ-सुथरे, हरे-भरे और सुरक्षित विकसित दिल्ली की दिशा में यह एक अहम कदम है।

200 नई ईवी बसों के डीटीसी के बेड़े में शामिल होने से बसों की कुल संख्या लगभग 6800 हो गई है, जिसमें 4938 इलेक्ट्रिक बसें और 1750 सीएनजी बसें शामिल है। इसे साथ ही डीटीसी ने दिल्ली-करनाल रूट पर पांच पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, एयर-कंडीशन्ड बसें शुरू की है। यह बस सेवा लगभग 133 किलोमीटर लंबे वन-वे कॉरिडोर पर दोनों दिशाओं में रोजाना 10 ट्रिप की सुविधाएं देगी। यह रूट महाराणा प्रताप आईएसबीटी कश्मीरी गेट को सीधे हरियाणा के करनाल से जोड़ेगा, जिसमें सिंघू बॉर्डर, राय, भालगढ़, मुरथल, गन्नौर, समालखा, पानीपत, घरौंदा व मधुबन समेत कई महत्वपूर्ण स्थान शामिल है। ये बसें दिल्ली को बरौत, सोनीपत, धारूहेड़ा, पानीपत और रोहतक से जोड़ती हैं, जिससे जीरो-एमिशन वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क राजधानी दिल्ली की सीमाओं से बाहर तक फैल रहा है।

यूनिवर्सिटी जाने वाली छात्राओं को बड़ी राहत

महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और पहुंच को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए डीटीसी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर 56 इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू की हैं। इनमें ज्यादा डिमांड वाले 15 रूटों पर 'लेडीज स्पेशल' की 30 ट्रिप और 13 रूट पर 'यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल' (यू-एसपीएल) की 26 ट्रिप शामिल हैं। यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल बस सेवा हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, श्रीराम कॉलेज, एलएसआर, गार्गी कॉलेज, एआरएसडी, हंसराज कॉलेज, एसपीएम कॉलेज, देशबंधु कॉलेज और एजीजीएससीसी जैसे कई प्रमुख संस्थानों के लिए विशेष कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

शिमला में एचपी ने उतारा हल्का और जंगरोधी नव्या गैस सिलेंडर

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शिमला के मॉल रोड स्थित रोटरी टाउन हॉल टैरेस पर अपने आधुनिक और सुरक्षित एलपीजी कम्पोजिट सिलेंडर एचपी नव्या का शुभारंभ किया। कंपनी के इस नए उत्पाद को विशेष रूप से सुविधा, सुरक्षा और उपयोग में आसानी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कार्यक्रम में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक बिक्री रोहित शर्मा, हिमाचल प्रदेश के बिक्री प्रबंधक सुरजंन शर्मा तथा शिमला खुदरा क्षेत्र के सहायक प्रबंधक एवं क्षेत्रीय समन्वयक राहुल यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सोलन, कसौली और आसपास के क्षेत्रों से एचपी गैस के अधिकृत वितरक और डीलर भी शामिल हुए। समारोह के दौरान बेस्ट गैस सर्विस के मालिक आदर्श सूद ने मुख्य अतिथि रोहित शर्मा का हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद रोहित शर्मा और आदर्श सूद ने संयुक्त रूप से एचपी नव्या कम्पोजिट सिलेंडर का अनावरण किया।

इस अवसर पर करीब 10 से 12 उपभोक्ताओं को नए एचपी नव्या गैस कनेक्शन से संबंधित दस्तावेज भी सौंपे गए। शिमला में यह नया कम्पोजिट सिलेंडर एचपी गैस के अधिकृत वितरक बेस्ट गैस सर्विस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक रोहित शर्मा ने उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए एचपी नव्या सिलेंडर की विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह सिलेंडर पारंपरिक सिलेंडरों की तुलना में हल्का, पारदर्शी और पूरी तरह जंगरोधी है।

छोटे कोल्ड स्टोर से बागवानों को मिलेगी बेहतर कीमत और सुरक्षित भंडारण सुविधा

छोटे कोल्ड स्टोर से फसल सुरक्षित रहेगी, बागवानों को मिलेगा बेहतर बाजार मूल्य

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के बागवानों को अपनी उपज के बेहतर भंडारण, उचित बाजार मूल्य और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के उद्देश्य से शिमला स्थित हॉलिडे होम में 'कोल्ड स्टोर क्रांति' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन ईईएसएल के सौजन्य से किया गया। इसमें बागवानों के अलावा बागवानी विभाग के अधिकारी, विशेषज्ञ और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक बागवानी डॉ. विद्या प्रकाश बैंस ने की।

डॉ. बैंस ने कहा कि छोटे कोल्ड स्टोर हिमाचल के बागवानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आधुनिक भंडारण सुविधा उपलब्ध होने से बागवानों को तुड़ान के तुरंत बाद अपनी उपज कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। वे अपनी फसल को सुरक्षित तरीके से कुछ समय तक संरक्षित रख सकेंगे और बाजार में मांग तथा कीमतों के अनुसार बिक्री का समय तय कर सकेंगे। इससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि कार्यशाला का आयोजन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और सचिव बागवानी डॉ. सी. पॉल रासु के मार्गदर्शन में किया गया। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक अनिल कुमार चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश के बागवानी क्षेत्र को आधुनिक, टिकाऊ और बाजारोन्मुख बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्यशाला में सेब और स्टोन फ्रूट जैसी फसलों के वैज्ञानिक भंडारण की आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने आधुनिक एवं टिकाऊ कूलिंग सिस्टम, सौर ऊर्जा आधारित कूलिंग व्यवस्था तथा विद्युत और थर्मल बैकअप जैसी तकनीकों की उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी दी। इन तकनीकों के माध्यम से कम मात्रा में उत्पादन करने वाले बागवान भी अपनी उपज को वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित रख सकेंगे। एचपी-शिवा परियोजना निदेशक डॉ. समीर सिंह राणा, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक विवेक पठानिया तथा विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी कार्यशाला में भाग लिया।

सौर ऊर्जा से चलेंगे कोल्ड स्टोर

अधिकारियों के अनुसार एकीकृत बागवानी मिशन के तहत 5 और 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले छोटे कोल्ड स्टोर स्थापित किए जा सकेंगे। इन पर 50 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम बागवानों तक आधुनिक भंडारण तकनीक पहुंचाना है। विशेषज्ञों ने कहा कि छोटे कोल्ड स्टोर की सुविधा से बागवानों को फसल बेचने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। वे बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए अपनी उपज बेच सकेंगे। इससे बागवानों की आय बढ़ने के साथ प्रदेश की बागवानी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है। कार्यशाला में इस बात पर जोर दिया गया कि खेत से बाजार तक उपज को सुरक्षित रखने की व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है।

दूध से मसालों तक जांच, मोबाइल लैब से मिलावटखोरों पर होगी सख्ती

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में दूध और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदेशालय ने मोबाइल खाद्य जांच प्रयोगशाला वैन का विशेष कार्यक्रम जारी किया है। अगस्त से यह मोबाइल प्रयोगशाला प्रदेश के विभिन्न बाजारों में पहुंचेगी और दूध, पनीर, घी, मसालों सहित रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों की औचक जांच करेगी।

मोबाइल प्रयोगशाला के माध्यम से मौके पर ही खाद्य पदार्थों की प्राथमिक जांच की जाएगी। जांच के दौरान किसी उत्पाद में मिलावट या गुणवत्ता संबंधी गड़बड़ी पाए जाने पर विभाग आगे की कार्रवाई के लिए नमूने भी ले सकेगा। औचक जांच का उद्देश्य ऐसे कारोबारियों पर कार्रवाई करना है जो उपभोक्ताओं को मिलावटी या घटिया गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं।

त्योहारी सीजन से पहले निगरानी तेज : त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले विभाग ने दूध और दूध से बने उत्पादों पर विशेष निगरानी रखने का फैसला किया है। त्योहारों के दौरान खोया, पनीर, घी और दूध की मांग बढ़ जाती है। इसी दौरान मिलावट की आशंका भी बढ़ती है। इसलिए मोबाइल जांच वैन को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बाजारों में भेजा जाएगा। विभाग का मानना है कि औचक जांच से दुकानदारों और डेयरी संचालकों को पहले से तैयारी करने का अवसर नहीं मिलेगा। इससे वास्तविक स्थिति सामने लाने और मिलावट करने वालों की पहचान करने में मदद मिलेगी। दुधारू पशुओं से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए आक्सीटोसिन के अनधिकृत इस्तेमाल पर भी स्वास्थ्य विभाग निगरानी बढ़ा रहा है।

कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर, 2027 के टिकट की लड़ाई अभी से शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने हिमाचल कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल के बजाय पांच से अधिक गुटों का समूह बनकर रह गई है। कांग्रेस भवन से लेकर प्रदेश, जिला और खंड स्तर तक पार्टी में गुटबाजी दिखाई दे रही है और नेता जनता की समस्याओं के बजाय एक-दूसरे को कमजोर करने में जुटे हैं।

संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि ठियोग विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची और विधायक कुलदीप सिंह राठौर के बीच सामने आई बयानबाजी ने पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले गुटबाजी बंद कमरों तक सीमित रहती थी, लेकिन अब कांग्रेस नेता सार्वजनिक मंचों और सामाजिक माध्यमों पर भी एक-दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि खाची की टिप्पणी के बाद लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का राठौर के समर्थन में सामने आना कांग्रेस के भीतर सक्रिय अलग-अलग राजनीतिक खेमों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ नेताओं के अलग-अलग गुट बने हुए हैं।

आपदा प्रभावित योजनाओं की मरम्मत के प्रस्ताव जल्द भेजने के लिए उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में जिले में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के तहत उपलब्ध बजट तथा आपदा से प्रभावित विकास कार्यों की मरम्मत को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने सभी उपमंडल अधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों, स्कूलों, पेयजल योजनाओं और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत के प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर जल्द भेजने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने कहा कि क्षेत्र स्तर पर प्रभावित कार्यों के प्रस्ताव तुरंत तैयार कर संबंधित उपमंडल अधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन को भेजे जाएं, ताकि पात्र मरम्मत कार्यों के लिए बजट का शीघ्र प्रावधान किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक प्रस्ताव के साथ क्षति रिपोर्ट, विस्तृत अनुमान और वसूली पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अधूरे प्रस्तावों के कारण बजट जारी करने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित योजनाओं की मरम्मत के लिए जिला स्तर पर बजट का प्रावधान किया है, लेकिन क्षेत्र स्तर से अपेक्षित संख्या में पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता से चिन्हित कर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि जिन विकास कार्यों के लिए ऋण-पत्र जारी किए जाने हैं, उनकी प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाए, ताकि स्वीकृत कार्य समयबद्ध तरीके से शुरू हो सकें। बैठक में सांसद निधि के तहत स्वीकृत कार्यों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने लंबे समय से लंबित कार्यों को जल्द शुरू करवाने तथा उनकी व्यक्तिगत निगरानी करने के निर्देश दिए।

जल शक्ति विभाग में 40 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जल शक्ति मंडल कसुम्पटी में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टी टास्क वर्कर के कुल 40 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 25 अगस्त तक अपने आवेदन मंडल कार्यालय कसुम्पटी में जमा करवा सकते हैं।

अधिशासी अभियंता जल शक्ति मंडल कसुम्पटी विनोद शर्मा ने बताया कि पहले आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 20 अगस्त निर्धारित की गई थी। इसे अब पांच दिन बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया गया है। विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर के 12, पैरा फिटर के तीन और मल्टी टास्क वर्कर के 25 पद भरे जाने हैं। उन्होंने बताया कि तिथि बढ़ाने का उद्देश्य पात्र युवाओं को आवेदन का अतिरिक्त अवसर देना है, ताकि कोई भी योग्य अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित न रहे। जानकारी के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों को मिडिल स्कूल प्रमाणपत्र प्राप्त करने में देरी हो रही थी।

27 साल बाद हिमाचल में लौटेगी लॉटरी दिवाली पर लोगों को मिल सकते हैं बड़े इनाम

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में करीब 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर लॉटरी शुरू होने जा रही है। सरकार ने लॉटरी संचालन से जुड़ी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। यदि योजना के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ी तो इस वर्ष दिवाली के अवसर पर प्रदेशवासी लॉटरी के जरिए अपनी किस्मत आजमा सकेंगे। सरकार अगले एक-दो दिनों में निविदा प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है।

इस बार लॉटरी व्यवस्था को पारंपरिक तरीके के साथ आधुनिक डिजिटल माध्यम से भी जोड़ा जाएगा। प्रदेशवासी अधिकृत बिक्री केंद्रों से टिकट खरीदने के साथ घर बैठे डिजिटल माध्यम से भी टिकट लेने की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है।

आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लिए लॉटरी को राजस्व जुटाने के एक अतिरिक्त माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का अनुमान है कि लॉटरी के संचालन से राज्य के राजकोष में प्रतिवर्ष करीब 50 करोड़ रुपये का राजस्व आ सकता है। इस राशि का उपयोग विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकेगा।

नई व्यवस्था के तहत नियमित लॉटरी के अलावा दिवाली, नववर्ष और अन्य प्रमुख त्योहारों पर विशेष बंपर ड्रा आयोजित किए जाएंगे। इनमें बड़े पुरस्कार रखे जाने की योजना है, जिससे लोगों की रुचि बढ़ने की उम्मीद है।

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1999 में लॉटरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस समय लॉटरी से जुड़े सामाजिक दुष्प्रभावों, आर्थिक शोषण और धोखाधड़ी की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया था। विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई थी।

अब करीब 27 वर्ष बाद सरकार ने बदलती परिस्थितियों और राज्य की आर्थिक जरूरतों को देखते हुए लॉटरी को दोबारा शुरू करने की तैयारी की है।

भूस्खलन से मार्ग बंद, चार घरों पर खतरा, जनजीवन प्रभावित

शिमला में बारिश से भूस्खलन, सड़क बंद

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में रात से लगातार हो रही बारिश के कारण शिमला में जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के बीच अपर लंबिधार-इंद्रनगर एंबुलेंस रोड पर भूस्खलन होने से सड़क पूरी तरह बंद हो गई। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर आ गिरने के कारण वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। भूस्खलन की चपेट में एक वाहन भी आ गया।

सड़क बंद होने से बुधवार सुबह स्कूल और कार्यालय जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार भूस्खलन वाले स्थान के ऊपर बने चार घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी की मिट्टी में नमी बढ़ने से स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। लोगों ने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्र में तत्काल सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है।

भट्ठाकुफर क्षेत्र में भी भूस्खलन के कारण दो वाहन क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। छोटा शिमला, समरहिल सहित अन्य क्षेत्रों में छह पेड़ गिर चुके हैं। इनमें से कुछ पेड़ों की चपेट में वाहन आए, जबकि कुछ स्थानों पर भवनों को खतरा पैदा हो गया।

राज्य सचिवालय परिसर में भी एक पेड़ गिर गया, जबकि दूसरा पेड़ गिरने की स्थिति में है। इसे हटाने के लिए काम शुरू किया गया है। छोटा शिमला में पेड़ गिरने से सड़क किनारे खड़ा वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।

रामनगर वेलफेयर सोसाइटी लंबिधार-इंद्रनगर ने प्रशासन से सड़क पर जमा मलबा जल्द हटाने और भूस्खलन वाले स्थान पर सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि समय रहते ठोस सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो बारिश के दौरान ऊपर बने घरों को गंभीर खतरा हो सकता है। प्रशासन और संबंधित विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

शिमला में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाओं से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपर लंबिधार-इंद्रनगर एंबुलेंस रोड पर मलबा आने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। भूस्खलन के कारण चार घरों पर खतरा मंडरा रहा है। भट्ठाकुफर में भी दो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। शहर के कई क्षेत्रों में छह पेड़ गिरने से वाहनों और भवनों को नुकसान का खतरा पैदा हुआ। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मलबा हटाने और प्रभावित स्थानों पर सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है।

दो सौ साल पुराने देवता जुन्गा मंदिर के जीर्णोद्धार को मांगा सरकारी अनुदान

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जुन्गा तहसील की ग्राम पंचायत धाली के ठूंड गांव स्थित करीब दो सौ वर्ष पुराने देवता जुन्गा देवचंद मंदिर के जीर्णोद्धार और निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए मंदिर निर्माण समिति ने प्रदेश सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। बुधवार को समिति के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से शिमला स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर मंदिर निर्माण सहित अन्य आवश्यक कार्यों को लेकर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद और उपाध्यक्ष मनोहर सिंह ठाकुर ने किया।

समिति के उपाध्यक्ष मनोहर सिंह ठाकुर ने मंत्री को बताया कि प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य वर्तमान में जारी है। मंदिर निर्माण के लिए ग्रामीणों ने अपनी ओर से अब तक करीब 30 लाख रुपये का योगदान दिया है। इसके बावजूद निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए लगभग 25 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। समिति ने सरकार से इस राशि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए एक सराय का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके निर्माण पर करीब पांच लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। समिति ने मंदिर के साथ सराय निर्माण के लिए भी सरकार से सहयोग मांगा।

मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि मंदिर निर्माण के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग से अनुदान उपलब्ध करवाने के संबंध में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के समक्ष मामला उठाया जाएगा।

जुखाला-कुठेड़ा में सहकारी बैंक की नई शाखाओं का शुभारंभ

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने शाखाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बिलासपुर जिले के जुखाला और कुठेड़ा में नए शाखा भवनों का उद्घाटन किया। बैंक अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने दोनों भवनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बैंक निदेशक डॉ. जगदीश चंद्र शर्मा, संजय शर्मा और सुनील कुमार शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

बैंक अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की शाखाओं का चरणबद्ध तरीके से उन्नयन और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ग्राहकों की सुविधा के लिए बेहतर बैठने की व्यवस्था और आधुनिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बैंक ने अपने पुराने कोर बैंकिंग तंत्र को आधुनिक फिनैकल सॉफ्टवेयर पर स्थानांतरित किया है, जिससे लेन-देन अधिक तेज और सुरक्षित हुआ है।

फीस वृद्धि के विरोध में विश्वविद्यालय परिसर में गरजे सैकड़ों विद्यार्थी

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालय इकाई ने बुधवार को सैकड़ों छात्रों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। परिषद ने फीस वृद्धि वापस लेने सहित छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर परिसर में आक्रोश रैली निकाली और धरना दिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों की क्रमिक भूख हड़ताल का 17वां दिन भी जारी रहा।

इकाई अध्यक्ष अक्षय ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद पहले ही प्रशासन को फीस वृद्धि का निर्णय वापस लेने की चेतावनी दे चुकी है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन बिना पर्याप्त सुविधाएं बढ़ाए छात्रों पर आर्थिक बोझ डाल रहा है।

अक्षय ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रदेश के ग्रामीण, किसान, बागवान और मध्यमवर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। फीस में बढ़ोतरी से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्रों के सामने आर्थिक कठिनाइयां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय में पढ़ाई आम विद्यार्थियों की पहुंच में रहनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय में छात्र सुविधाओं का मुद्दा भी उठाया। परिषद का कहना है कि विद्यार्थियों को पर्याप्त छात्रावास, आधुनिक पुस्तकालय और बेहतर परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में सुविधाओं में अपेक्षित सुधार किए बिना फीस बढ़ाना छात्र हितों के खिलाफ है।

मशोबरा स्कूल ने लगातार दूसरी बार जीता कबड्डी का जिला खिताब

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्रिएटिव फाउंडेशन की ओर से एसपीएम स्कूल संजौली में आयोजित जिला स्तरीय अंडर-19 कबड्डी प्रतियोगिता में राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मशोबरा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार विजेता बनने का गौरव हासिल किया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों की टीमों ने भाग लेकर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मशोबरा स्कूल के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल कौशल, अनुशासन और टीम भावना का परिचय देते हुए प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

प्रतियोगिता के समापन अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन गेयटी थिएटर शिमला में किया गया। समारोह में नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। लगातार दूसरी बार जिला स्तर पर खिताब अपने नाम करने पर खिलाड़ियों और विद्यालय प्रबंधन की सराहना की गई।

◆ **लगातार दूसरी जीत से मशोबरा स्कूल के खिलाड़ियों ने बढ़ाया क्षेत्र का गौरव**

विद्यालय परिसर पहुंचने पर प्रधानाचार्य बनवारी लाल केशव ने विजेता खिलाड़ियों का स्वागत एवं सम्मान किया। उन्होंने खिलाड़ियों को शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की इस सफलता से विद्यालय परिवार गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार की उपलब्धियां अन्य विद्यार्थियों को भी खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। विद्यालय के डीपी मोहन लाल शर्मा और टीम कोच नंद लाल शर्मा ने भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।

संकल्प अनुराधा राणा के नेतृत्व में आदिवासी कांग्रेस उठाएगी विकास और अधिकारों से जुड़े प्रमुख मुद्दे

अनुराधा राणा ने संभाली आदिवासी कांग्रेस की कमान

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बुधवार को लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस आदिवासी विभाग की अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने अनुराधा राणा को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

डॉ. विक्रांत भूरिया ने भाजपा पर आदिवासी समाज के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने कई कानून बनाए हैं लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने इन कानूनों का अपेक्षित लाभ आदिवासी समाज तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों के साथ हो रहे कथित अत्याचार चिंता का विषय हैं।

भूरिया ने कहा कि कांग्रेस आदिवासी क्षेत्रों के विकास और वहां रहने वाले लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में आदिवासी समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में आदिवासी समाज से अधिक संख्या में नेतृत्व तैयार किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही एक बड़े आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसमें राहुल गांधी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में 47 लोकसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल हैं और इनमें 15 सीटों पर कांग्रेस की मजबूत स्थिति है। उन्होंने दावा किया कि 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाने के लिए अभी से जुटने का आह्वान किया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अनुराधा राणा को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी विभाग को कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए।

21 अगस्त से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र, दस बैठकें होंगी आयोजित

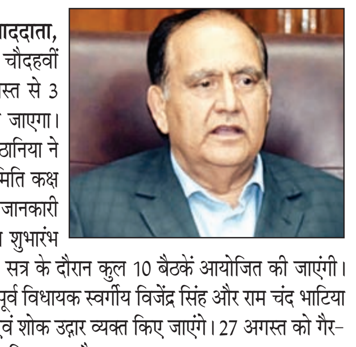

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधानसभा का 12वां सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में सत्र की जानकारी देते हुए बताया कि मानसून सत्र का शुभारंभ 21 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा। सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सत्र के पहले दिन पूर्व विधायक स्वर्गीय विजेंद्र सिंह और राम चंद भाटिया के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव एवं शोक उद्गार व्यक्त किए जाएंगे। 27 अगस्त को गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस वर्ष बजट सत्र में अब तक 16 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। मानसून सत्र के लिए विधायकों की ओर से प्रश्नों से संबंधित कुल 1036 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। सभी प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं और नियमानुसार आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को भेज दिए गए हैं।

पठानिया के अनुसार सदस्यों की ओर से प्राप्त प्रश्न मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भारी वर्षा, केंद्र से आपदा राहत के लिए सहायता, सड़कों और पुलों के निर्माण, स्वीकृत सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, स्कूलों के विलय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन तथा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों से संबंधित हैं। इसके अलावा पर्यटन, बागवानी, पेयजल आपूर्ति, युवाओं में बढ़ते नशे की रोकथाम, अपराध और परिवहन व्यवस्था जैसे मुद्दे भी सदन में उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नियम 62 के तहत 13, नियम 63 के तहत दो, नियम 101 के तहत पांच और नियम 130 के तहत 15 सूचनाएं भी सरकार को भेजी गई हैं।

अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सदन के समय का सदुपयोग जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए किया जाना चाहिए।

एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर

दून में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा, एशियन ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन

अनिल थपलियाल

देहरादून में आयोजित एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 के दूसरे दिन भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हिमाद्री आइस रिंक में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के 14 देशों के शीर्ष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तेज रफ्तार, जबरदस्त प्रतिस्पर्धा और रोमांच से भरपूर मुकाबलों के बीच भारतीय शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटर्स ने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

पहले दिन के शानदार प्रदर्शन के बाद दूसरे दिन भी भारतीय खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में पोडियम फिनिश हासिल किए। जूनियर एफ बालिका 222 मीटर में भारत की जी.एस. ब्रधिशा ने 28.91 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में समायरा त्यागी ने रजत और अमायरा शाह ने कांस्य पदक हासिल कर भारत का दबदबा कायम रखा। जूनियर एफ बालक 222 मीटर में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इवान अरोड़ा ने स्वर्ण, युवराज मेहता ने रजत और शिवांश आहेर ने कांस्य पदक अपने नाम किया।

जूनियर ई बालक 333 मीटर स्पर्धा में आर्यन सुजीत बाविस्कर ने 35.47 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि भारत के राघव चौधरी ने कांस्य पदक जीता।

भारतीय खिलाड़ियों ने बिखेरा खेल कौशल

हालांकि कुछ स्पर्धाओं में चीन, थाईलैंड, हांगकांग, चीनी ताइपे, इंडोनेशिया और अन्य देशों के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। जूनियर ई बालिका 333 मीटर में चीन की रुइलिन यांग ने स्वर्ण पदक जीता। जूनियर डी बालिका 777 मीटर में चीन की खिलाड़ियों ने तीनों पदक अपने नाम किए। जूनियर डी बालक 777 मीटर में भी चीन का दबदबा देखने को मिला। इससे प्रतियोगिता में एशियाई देशों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा का अंदाजा लगाया जा सकता है। सीनियर वर्ग में भी मुकाबले बेहद रोमांचक रहे। सीनियर महिला 1500 मीटर में भारत की साई सहाना ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। रिले स्पर्धाओं में चीन और थाईलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। मिश्रित सी-डी 2000 मीटर रिले में चीन की टीम ने स्वर्ण और थाईलैंड की टीम ने रजत पदक जीता।

दर्शकों का बढ़ा उत्साह

प्रतियोगिता के दौरान हिमाद्री आइस रिंक में दर्शकों का उत्साह भी देखते ही बना। घरेलू दर्शकों ने भारतीय खिलाड़ियों का जोरदार समर्थन किया और हर रोमांचक मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। बर्फ पर खिलाड़ियों की तेज गति, शानदार मोड़, संतुलन और रणनीतिक रेसिंग ने दर्शकों को रोमांचित किया। दूसरे दिन के परिणाम भारतीय शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग के लिए उत्साहजनक रहे। युवा खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता साबित की, वहीं सीनियर खिलाड़ियों ने भी मजबूत प्रदर्शन किया। देहरादून में आयोजित यह प्रतियोगिता भारतीय खिलाड़ियों को एशियाई स्तर के शीर्ष स्केटर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रही है। भारत का प्रदर्शन यह संकेत देता है कि देश में शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग की प्रतिभा लगातार मजबूत हो रही है और आने वाले समय में भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।

टनल हादसे के मृतकों के आश्रितों के हक में सड़क पर उतरे श्रमिक

अनिल थपलियाल। चमोली के पीपलकोटी में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद मृत श्रमिकों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग तेज हो गई है। बुधवार को ऑल इंडिया फेडरेशन के महासचिव सोहन कुमार के नेतृत्व में एचसीसी मायापुर के श्रमिकों ने रैली निकाली। श्रमिक एचसीसी कार्यालय से टीएचडीसी गेट तक पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मृत श्रमिक अपने परिवारों के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे और उनके निधन से आश्रितों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने टीएचडीसी प्रबंधन से जल्द वार्ता कर सम्मानजनक मुआवजा सुनिश्चित करने की मांग की। श्रमिकों ने चेतावनी दी कि ठोस पहल होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

सौंग नदी पर बाढ़ सुरक्षा को मिली मंजूरी

विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के प्रयासों से बाढ़ सुरक्षा कार्य स्वीकृत

अनिल थपलियाल

ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के साहब नगर डांडी गांव में सौंग नदी से संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रास्ता साफ हो गया है। सिंचाई विभाग उत्तराखंड को इन कार्यों के लिए 244.27 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही 144 लाख रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। धनराशि स्वीकृत होने पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जताते हुए ऋषिकेश विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल का आभार व्यक्त किया।

इसी क्रम में ग्राम प्रधान भावना गुरुंग के नेतृत्व में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने ऋषिकेश स्थित कैंप कार्यालय पहुंचकर विधायक को गुलदस्ता भेंट किया और धन्यवाद दिया। ग्रामीणों ने कहा कि सौंग नदी के किनारे बसे होने के कारण बरसात के मौसम में उन्हें नदी के बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ से नुकसान की चिंता रहती है। बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए धनराशि मिलने से अब इस समस्या से काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

ग्राम प्रधान भावना गुरुंग ने कहा कि विधायक डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल के प्रयासों से क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों को गति मिल रही है।

डांडी गांव में सौंग नदी से बाढ़ का खतरा होगा कम।

क्षेत्र का समग्र विकास हमारी प्राथमिकता : डॉ. अग्रवाल

डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सौंग नदी के किनारे बसे इलाकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाढ़ सुरक्षा कार्यों की स्वीकृति के लिए लगातार प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि 244.27 लाख रुपये की स्वीकृति और 144 लाख रुपये की पहली किस्त जारी होना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी रहे मौजूद

संबंधित विभाग को कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि स्थानीय लोगों को जल्द इसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर उप प्रधान अमर खत्री, पंचायत सदस्य अर्जुन रावत, विशाल क्षेत्री, मायाराम पैन्यूली, शोभा रावत, सुरेंद्र रावत, रन बहादुर, सोहन नेगी, अंबर गुरुंग, सोबन कैंतुरा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि कार्य जल्द शुरू होने से सौंग नदी के किनारे रहने वाले परिवारों की सुरक्षा मजबूत होगी।

नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के नव नियुक्त उप वन संरक्षक ने एसपी से की शिष्टाचार भेंट

उदित नैनवाल

◆ चमोली की प्राकृतिक विरासत बचाने को वन विभाग और पुलिस साथ-साथ

चमोली में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के नव नियुक्त उप वन संरक्षक यश ढोबले ने पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार से पुलिस कार्यालय गोपेश्वर में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने जिले की समृद्ध वन संपदा, जैव विविधता और वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर चर्चा की। उप वन संरक्षक ने पुलिस अधीक्षक को जैव विविधता का पौधा भेंट किया। पुलिस अधीक्षक ने नव नियुक्त अधिकारी का स्वागत करते हुए कहा कि चमोली की पहचान यहां के जंगलों, वन्यजीवों और प्राकृतिक संपदा से है। इनका संरक्षण केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी संबंधित विभागों और समाज के सामूहिक प्रयास से ही इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। दोनों अधिकारियों ने प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई। साथ ही भविष्य में वन्यजीवों की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े मामलों में आपसी सहयोग एवं समन्वय के साथ कार्य करने का निर्णय लिया।

टनल हादसे के बाद मुआवजे को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन

गिरीश चंदोला। चमोली के पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद मृत श्रमिकों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग तेज हो गई है। बुधवार को ऑल इंडिया फेडरेशन के महासचिव सोहन कुमार के नेतृत्व में एचसीसी मायापुर के श्रमिकों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। श्रमिक एचसीसी कार्यालय से टीएचडीसी गेट तक पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिक अपने परिवारों के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे।

मोरेवियन इंस्टीट्यूट ने जीती 11वीं आईएलजी मैन स्मृति फुटसल प्रतियोगिता

अनिल थपलियाल

देहरादून के कारमन रेजिडेंशियल एंड डे स्कूल डालनवाला में आयोजित 11वीं आईएलजी मैन मेमोरियल जूनियर बॉयज फुटसल प्रतियोगिता का निर्णायक मुकाबला रोमांचक रहा। इस वर्ष प्रतियोगिता में 15 स्कूलों की टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला द ओसिस स्कूल और मोरेवियन इंस्टीट्यूट स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें मोरेवियन इंस्टीट्यूट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की।

मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष अशोक वर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनका उत्साहवर्धन किया। मैच के पहले हाफ में मोरेवियन इंस्टीट्यूट की टीम पूरी तरह हावी रही और पांच गोल कर मजबूत बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी। अंततः मोरेवियन इंस्टीट्यूट ने खिताब अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता में समरवेली स्कूल के आर्यन सुंदरियाल को होनहार गोलकीपर का पुरस्कार मिला, जबकि द ओसिस स्कूल के शिवाय को होनहार खिलाड़ी के सम्मान से नवाजा गया।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर में सुनीं जनसमस्याएं

अल्मोड़ा। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री एवं सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या ने बुधवार को सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के स्याहीदेवी मंडल अंतर्गत नौला, सल्ला रौतेला एवं बड़गल भट्ट गांवों में आयोजित जन मिलन कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं एवं विकास संबंधी मांगों से कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया गया। जनसमस्याओं को सुनते हुए कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर विधायक निधि से प्राथमिक विद्यालय में रेलिंग निर्माण, पेयजल लाइन बिछाने, सार्वजनिक स्थलों पर टीन शेड लगाने तथा गांव में भंडार कक्ष एवं पेयजल टैंक के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सड़क, पेयजल, शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान एवं विकास योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र से संबंधित जनहित की समस्याओं एवं आवश्यक विकास कार्यों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

न्यूज ब्रीफ

नारायणबगड़ बाजार में कुत्तों का आतंक 12 से अधिक लोगों को काटा

उदित नैनवाल। चमोली जिले के नारायणबगड़ बाजार में बुधवार को आवारा और आक्रामक कुत्तों के झुंड ने आतंक मचा दिया। कुत्तों ने दिनदहाड़े राह चलते लोगों और स्कूली बच्चों को निशाना बनाया, जिसमें 12 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के बाद बाजार में दहशत का माहौल है और लोग डंडे लेकर आने-जाने को मजबूर हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल अभियान चलाकर आक्रामक कुत्तों को पकड़ने और प्रभावित लोगों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।

बद्रीनाथ धाम में खोया पर्स और मोबाइल पुलिस ने श्रद्धालु को लौटाया

उदित नैनवाल। बद्रीनाथ धाम में राजस्थान के बाड़ा जिले से दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु लकी प्रजापति का पर्स मंदिर परिसर में कहीं खो गया। पर्स में नकदी और मोबाइल फोन था। पर्स मिलने पर पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात हेड कांस्टेबल दिवाकर सती ने मोबाइल और अन्य सामान के आधार पर उसके स्वामी की तलाश की। पहचान होने के बाद उन्होंने पूरा सामान सुरक्षित श्रद्धालु को सौंप दिया। खोया सामान वापस पाकर लकी प्रजापति काफी खुश हुए और उन्होंने चमोली पुलिस तथा हेड कांस्टेबल का आभार जताया।

हल्द्वानी में बीआईएस का राज्य स्तरीय संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित

अनिल थपलियाल। हल्द्वानी स्थित निदेशालय में भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा कार्यालय और समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के करीब 80 अधिकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शामिल हुए। विभाग के प्रमुख राजेश कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। बीआईएस के निदेशक एवं प्रमुख हेमंत बी. आड़े ने गुणवत्ता मानकों उपभोक्ता हितों और प्रमाणित उत्पादों के महत्व की जानकारी दी। संयुक्त निदेशक सचिन चौधरी ने हॉलमार्किंग मानकीकरण और संबंधित प्रक्रियाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया। अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया में बीआईएस प्रमाणित उत्पादों को प्राथमिकता देने के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को गुणवत्ता मानकों बीआईएस प्रक्रियाओं और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े प्रावधानों के प्रति जागरूक करना रहा। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को उपयोगी और ज्ञानवर्धक बताया।

टिहरी झील में 15 दिवसीय जल क्रीड़ा प्रशिक्षण का समापन

अनिल थपलियाल। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से टिहरी झील में आयोजित 15 दिवसीय जल क्रीड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम का बुधवार को विधिवत समापन हुआ। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण में उत्तराखंड के सभी जिलों से चयनित 20 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। पांच-पांच दिनों के तीन चरणों में प्रतिभागियों को जीवन रक्षक तकनीक, पावर बोट संचालन और टिलर तथा वाटर स्कीइंग का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रतिभागियों को राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा की ओर से प्रमाणित लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

एसबीआई कार्ड और गूगल पे ने लॉन्च किया को-ब्रांडेड फ्लेक्स एसबीआई कार्ड

अनिल थपलियाल

◆ रोजमर्रा की खरीदारी को फायदेमंद बनाएगा गूगल पे फ्लेक्स एसबीआई कार्ड

एसबीआई कार्ड और गूगल ने मिलकर 'गूगल पे फ्लेक्स एसबीआई कार्ड' लॉन्च किया है। यह कार्ड रोजमर्रा के भुगतान को आसान बनाने के साथ ग्राहकों को खरीदारी पर आकर्षक पुरस्कार, सुविधाजनक भुगतान और सुरक्षा प्रदान करता है। कार्ड के जरिये ग्राहक किराना सामान, बिल भुगतान, यात्रा बुकिंग, खरीदारी और ऑनलाइन व दुकानों पर होने वाले अन्य खर्चों पर स्टार्स अर्जित कर सकते हैं।

ग्राहकों को हर 500 रुपये के खर्च पर अधिकतम आठ स्टार्स अर्जित करने का अवसर मिलेगा और एक वर्ष में 18,000 स्टार्स तक जमा किए जा सकेंगे। इन स्टार्स को भुगतान के समय भुनाया जा सकता है। इसके अलावा, ग्राहक अपने अंतिम बकाया बिल को आसान मासिक किस्तों में बदलने की सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे।

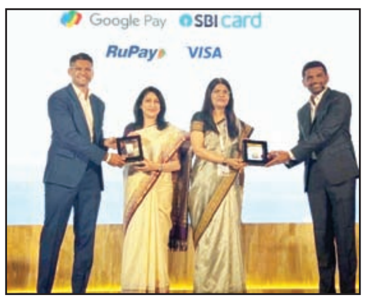

यह संपर्करहित क्रेडिट कार्ड रुपे और वीजा, दोनों भुगतान नेटवर्क पर उपलब्ध है। रुपे संस्करण को यूपीआई से जोड़कर देशभर में लाखों दुकानदारों को सीधे भुगतान किया जा सकता है।

दोनों संस्करणों को गूगल पे पर सुरक्षित रूप से जोड़ा जा सकता है, जिससे ग्राहकों को टैप-टू-पे सुविधा मिलेगी कार्डधारकों को 1,000 रुपये मूल्य का स्वागत उपहार मिलेगा। यदि ग्राहक एक बिलिंग चक्र में 15,000 रुपये तक खर्च करते हैं तो हर 500 रुपये पर चार स्टार्स और 30,000 रुपये से अधिक खर्च करने पर आठ स्टार्स तक मिलेंगे। कार्ड लेने और वार्षिक नवीनीकरण का शुल्क 499 रुपये है, जिस पर लागू कर अलग से लगेगा। सालाना एक लाख रुपये खर्च करने पर नवीनीकरण शुल्क माफ किया जाएगा।

उत्तराखंड बोर्ड सुधार परीक्षा का परिणाम जारी

इंटरमीडिएट सुधार परीक्षा में 73.35 प्रतिशत विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण

विकास बलोनी

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। सुधार परीक्षा के परिणाम के बाद बोर्ड के कुल परीक्षा परिणाम में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। हाईस्कूल सुधार परीक्षा में कुल 83.13 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इनमें बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.61 और बालिकाओं का 84.34 प्रतिशत रहा। वहीं इंटरमीडिएट में कुल 73.35 प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए, जिसमें बालकों का प्रतिशत 71.20 और बालिकाओं का 76.07 प्रतिशत रहा।

सुधार परीक्षा के बाद हाईस्कूल का कुल बोर्ड परिणाम 92.10 प्रतिशत से बढ़कर 96.07 प्रतिशत हो गया है। इसमें 93.94 प्रतिशत बालक और 98.14 प्रतिशत बालिकाएं शामिल हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट का परिणाम भी 85.11 प्रतिशत से बढ़कर 91.80 प्रतिशत हो गया है। इसमें बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.26 और बालिकाओं का 94.16 प्रतिशत रहा।

हाईस्कूल-इंटर सुधार परीक्षा में हजारों विद्यार्थी पास, आगे बढ़ने का मिला अवसर

इस तरह सुधार परीक्षा से बोर्ड के परिणाम में करीब छह प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

परिषद ने परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2025 के तीसरे चरण का परिणाम भी जारी किया। इसमें हाईस्कूल का कुल परिणाम 66.67 प्रतिशत और इंटरमीडिएट का 58.70 प्रतिशत रहा। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सफल विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुधार परीक्षा विद्यार्थियों को अपनी कमियों को दूर कर बेहतर परिणाम हासिल करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।

उत्तराखंड का भूस्खलन मॉडल दूसरे राज्यों में बना पहचान

तकनीकी सेवाओं से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा यूएलएमएमसी

अनिल थपलियाल

उत्तराखंड में भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में विकसित तकनीकी विशेषज्ञता अब राज्य की सीमाओं से बाहर भी अपनी पहचान बना रही है। उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र ने बाहरी राज्य की परियोजना के लिए तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्र को पहली बार अपनी तकनीकी सेवाओं के बदले 4 लाख 21 हजार रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। यह राशि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बादशाही बाग क्षेत्र स्थित खारा जलविद्युत परियोजना के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और तकनीकी परामर्श के एवज में मिली है।

परियोजना के भवन परिसर के समीप भूस्खलन की सक्रियता बढ़ने से सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था। इसके समाधान के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने उत्तराखंड के भूस्खलन प्रबंधन केंद्र से संपर्क किया। केंद्र को भूस्खलन रोकथाम कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी गई।

तकनीकी टीम ने जनवरी 2025 में परियोजना स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। स्थल की भौगोलिक और तकनीकी परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद आवश्यक जांच और विश्लेषण के आधार पर परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई।

डॉ. शांतनु सरकार का मार्गदर्शन सफल

निदेशक डॉ. शांतनु सरकार के मार्गदर्शन में टीम ने रिपोर्ट तैयार करने से लेकर स्थल पर्यवेक्षण तक विभिन्न तकनीकी कार्य पूरे किए। केंद्र की तकनीकी संस्तुतियों के आधार पर भूस्खलन रोकथाम का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 19 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की ओर से तकनीकी सेवाओं के लिए भुगतान का चेक सौंपा गया। यह केंद्र की स्थापना के बाद तकनीकी सेवाओं से अर्जित पहली राजस्व राशि है।

देवदार और बांज के जंगल बचाने सड़क पर उतरे स्थानीय लोग

उदित नैनवाल । पौड़ी जिले में बुआखाल से टेका तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पेड़ों के संभावित कटान का विरोध शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि नागदेवता रेंज क्षेत्र में देवदार, बांज, बुरांश और काफल समेत कई प्रजातियों के पेड़ों पर कटान के निशान लगाए गए हैं। 18 अगस्त को क्षेत्र का निरीक्षण कर लोगों ने कटान के निशान वाले पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधे और जंगल बचाने का संकल्प लिया। इसके बाद जिला वनाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कटान पर तत्काल रोक लगाने तथा पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जंगल पौड़ी के जलस्रोतों, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

रुद्रप्रयाग में सेना और राहत एजेंसियों ने परखी तैयारियां

अनिल थपलियाल

◆ सेना, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ ने मिलकर परखी आपदा तैयारी

रुद्रप्रयाग जिले में संभावित आपदा की स्थिति से निपटने के लिए बुधवार को जिला प्रशासन के निर्देशन में संयुक्त मॉक अभ्यास आयोजित किया गया। अभ्यास में सेना की 8 सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस बल और 108 एंबुलेंस की टीमों ने हिस्सा लिया। मॉक अभ्यास के जरिए विभिन्न राहत एवं बचाव एजेंसियों की तत्परता, आपसी समन्वय और उपलब्ध संसाधनों की कार्यक्षमता को परखा गया।

अभ्यास के दौरान सुबह 11:50 बजे जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को सूचना दी गई कि जीएमवीएन लाटा बाबा के समीप पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आने से नुकसान की आशंका है। सूचना मिलते ही संबंधित टीमों को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुंचकर टीमों ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था, लोगों को सुरक्षित निकालने, प्राथमिक उपचार और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई का अभ्यास किया।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि ऐसे अभ्यासों का उद्देश्य वास्तविक आपदा के समय त्वरित और प्रभावी राहत-बचाव सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि मॉक अभ्यास से व्यवस्थाओं में मौजूद कमियों की पहचान कर समय रहते सुधार किया जा सकता है। इससे भविष्य में संभावित जनहानि और नुकसान को न्यूनतम करने में मदद मिलेगी।

मद्महेश्वर धाम यात्रा फिर शुरू

उदित नैनवाल

रुद्रप्रयाग जिले में जनसुरक्षा और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से स्थगित की गई श्री मद्महेश्वर धाम यात्रा-2026 बुधवार, 19 अगस्त से फिर शुरू हो गई। यात्रा संचालन से पहले प्रशासन ने मार्ग, ट्रॉली स्थल और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी इंतजामों की समीक्षा की। उप जिलाधिकारी ऊखीमठ ने पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी, लोक निर्माण विभाग, तहसील प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट तथा स्थलीय निरीक्षण के आधार पर यात्रा मार्ग को सुरक्षित पाए जाने के बाद संचालन की अनुमति दी। यात्रा के दौरान ट्रॉली स्थल पर भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। महिला और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सहायता के साथ किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। यात्रा मार्ग पर दुर्घटना या आपदा की स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और खोज एवं बचाव दलों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। संबंधित विभागों को मार्ग, पुल-पुलिया और ट्रॉली स्थल की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रॉली का संचालन सुबह 6:30 से 9 बजे, 10:30 से दोपहर 1 बजे और दोपहर 2:30 से शाम 6 बजे तक होगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए ही यात्रा करने की अपील की है।

◆ एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की निगरानी में शुरू हुई धाम यात्रा

साढ़े चार साल में बदली पंजाब की स्कूली शिक्षा की तस्वीर

सरकार ने शिक्षा ढांचे पर 2300 करोड़ किए खर्च, 3.64 लाख विद्यार्थियों ने छोड़े निजी स्कूल

भारतेन्दु संवाददाता, संगरूर

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था का साढ़े चार साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 2,300 करोड़ रुपये का निवेश किया है। उनके अनुसार इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पंजाब ने नीति आयोग की वर्ष 2026-27 की रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है और केरल को भी पीछे छोड़ा है।

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बैंस ने कहा कि वर्ष 2022 से अब तक करीब 3.64 लाख विद्यार्थी निजी स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में दाखिल हुए हैं। उन्होंने इसे सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों और विद्यार्थियों के बढ़ते भरोसे का संकेत बताया। मंत्री ने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने और उन्हें बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया है।

बुनियादी सुविधाओं में सुधार का दावा : शिक्षा मंत्री के अनुसार सरकार के सत्ता संभालने के समय कई सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। उन्होंने दावा किया कि उस समय 5,000 से अधिक स्कूलों में उपयोग योग्य शौचालय नहीं थे, लगभग चार लाख विद्यार्थी फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर थे और करीब 500 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें मिलने में कई महीनों की देरी होती थी।

बैंस ने बताया कि पिछले साढ़े चार वर्षों में 13,920 नए शौचालय बनाए गए हैं और सभी सरकारी स्कूलों में उपयोग योग्य शौचालय उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। विद्यार्थियों के लिए करीब दो लाख बेंच उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा 9,000 से अधिक नए कक्ष और प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं तथा 10,000 से अधिक कक्षाओं में संवादात्मक पटल लगाए गए हैं। करीब 5,012 स्कूलों को आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशालाओं से उन्नत किया गया है और सभी सरकारी स्कूलों को वाई-फाई सुविधा से जोड़ने की बात कही गई है।

खेल सुविधाओं और शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर : मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में अब ऐसी खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जो पहले मुख्य रूप से निजी संस्थानों में देखने को मिलती थीं। इनमें तैराकी तालाब, निशानेबाजी केंद्र, बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट, कबड्डी मैट तथा कुश्ती और मुक्केबाजी के लिए सुविधाएं शामिल हैं।

शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर उन्होंने बताया कि अलग-अलग चरणों में प्रधानाचार्यों को सिंगापुर, प्राथमिक शिक्षकों को फिनलैंड और मुख्य अध्यापकों को भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। स्कूलों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पूर्व सैनिकों को परिसर प्रबंधक के रूप में तैनात करने तथा अधिक विद्यार्थी संख्या वाले स्कूलों में सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था का भी दावा किया गया।

हड़ताल से जालंधर में ड्राइविंग टेस्ट और रजिस्ट्री का काम फिर हुआ ठप

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर

पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर 21 अगस्त तक हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। बुधवार को हड़ताल के दौरान यूनियन सदस्यों ने बस स्टैंड के पास स्थित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर पहुंचकर काम बंद करवा दिया। इससे ड्राइविंग टेस्ट और अन्य जरूरी कार्यों के लिए पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

बुधवार को कई लोग अपने दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर पहुंचे थे। लोगों को उम्मीद थी कि पिछले कई दिनों से बंद पड़ा काम दोबारा शुरू होगा और उनके ड्राइविंग टेस्ट हो सकेंगे। हालांकि यूनियन सदस्यों के पहुंचने के बाद काम फिर बंद करवा दिया गया। इससे वहां मौजूद वाहन चालकों में नाराजगी देखने को मिली।

लोगों ने कहा कि ड्राइविंग टेस्ट से संबंधित काम पहले ही कई दिनों से प्रभावित है। ऐसे में दोबारा काम बंद होने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। कई लोग दूर-दराज के इलाकों से अपने वाहन लेकर पहुंचे थे, लेकिन काम नहीं होने के कारण उन्हें बिना टेस्ट करवाए वापस लौटना पड़ा। लोगों का कहना था कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन आम जनता से जुड़े जरूरी काम लगातार प्रभावित नहीं होने चाहिए।

यूनियन नेताओं ने जालंधर तहसील परिसर में संपत्तियों की रजिस्ट्री से संबंधित काम भी बंद करवा दिया। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। उन्होंने सभी विभागों के कर्मचारियों से आंदोलन में सहयोग करने की अपील की।

रजिस्ट्री करवाने पहुंचे लोगों को भी काम नहीं होने के कारण वापस लौटना पड़ा। लोगों का कहना है कि संपत्ति से जुड़े काम समयबद्ध होते हैं और काम बंद होने से उन्हें आर्थिक तथा प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

न्यूज ब्रीफ

लुधियाना रेलवे स्टेशन पुनर्विकास की धीमी रफ्तार से बढ़ा यात्रियों का इंतजार

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। महानगर के व्यस्त रेलवे स्टेशन के विश्वस्तरीय पुनर्विकास की रफ्तार धीमी बनी हुई है। करीब 528.95 करोड़ रुपये की लागत वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का अब तक केवल 58 प्रतिशत काम पूरा हो पाया है, जबकि 42 प्रतिशत निर्माण कार्य अभी बाकी है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार परियोजना अब जून 2027 तक पूरी होने की संभावना है। परियोजना की समयसीमा पहले अगस्त 2025 थी, जिसे बढ़ाकर अप्रैल 2026 और फिर दिसंबर 2026 किया गया। अब धीमी प्रगति के कारण इसे जून 2027 तक बढ़ाए जाने की संभावना है। फरवरी 2025 में परियोजना का 44 प्रतिशत काम पूरा हुआ था और 17 महीनों में केवल 14 प्रतिशत प्रगति हुई। अधिकारियों के अनुसार चालू स्टेशन पर निर्माण होने के कारण यातायात और सुरक्षा बड़ी चुनौती हैं। इस बीच यात्रियों को राहत देते हुए स्टेशन की पार्किंग सुविधा दोबारा शुरू कर दी गई है।

मेयर विदेश रवाना, सीनियर डिप्टी मेयर ने संभाली निगम की कमान

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। नगर निगम लुधियाना में मेयर इंद्रजीत कौर के बिना पूर्व सूचना विदेश जाने के बाद प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। मेयर ने निगम कमिश्नर और सीनियर डिप्टी मेयर को अपना कार्यभार सौंपने संबंधी कोई जानकारी नहीं दी। उनकी विदेश यात्रा कितने दिनों की है, यह भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर ने नगर निगम अधिनियम 1976 की धारा 40(2) के तहत मेयर कार्यालय का प्रभार संभाल लिया। पराशर ने कमिश्नर और सभी पार्षदों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेयर की वापसी तक प्रशासनिक फाइलों, विकास कार्यों और वित्तीय मंजूरियों से जुड़े जरूरी मामलों का संचालन उनके कार्यालय से किया जाएगा। मानसून के दौरान जलभराव, सीवरेज, सफाई और सड़कों से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए उन्होंने शहर का कामकाज प्रभावित न होने देने की बात कही।

रावी में उफान से आधा दर्जन गांवों का टूटा संपर्क

भारतेन्दु संवाददाता, गुरदासपुर। रावी दरिया में लगातार बढ़ रहे जलस्तर और तेज बहाव के कारण मकोड़ा पत्तन से दूसरी तरफ जाने वाली किश्ती सेवा बंद कर दी गई है। इससे दरिया पार बसे करीब आधा दर्जन गांवों का मुख्य इलाकों से संपर्क प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों को रोजमर्रा के काम, बच्चों की पढ़ाई और जरूरी कार्यों के लिए आवाजाही में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जलस्तर की लगातार निगरानी करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पानी और बढ़ा तो स्थिति गंभीर हो सकती है। ग्रामीणों ने बहाव सामान्य होते ही किश्ती सेवा दोबारा शुरू करने की मांग की है। प्रशासन ने लोगों से दरिया के पास जाने से बचने और सावधानी बरतने की अपील की है।

नियुक्तियों पर घमासान, 200 से अधिक कर्मचारी निलंबित

भारतेन्दु संवाददाता, पटियाला। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पूर्व कुलपति डॉ. राजीव सूद के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों को लेकर विवाद गहरा गया है। विश्वविद्यालय ने हाल ही में नियुक्त किए गए 200 से अधिक कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं, सामान्य पूल में पदोन्नत करीब दो दर्जन डॉक्टरों को उनके मूल विभागों में वापस भेज दिया गया है। यह कार्रवाई 11 अगस्त को हुई प्रबंधन मंडल की बैठक के बाद की गई। मंडल ने कई नियुक्तियों में निर्धारित नियमों और पदों की मंजूरी का पालन नहीं होने पर आपत्ति जताई। कुछ पदों के लिए बजट स्वीकृति नहीं लेने और ऐसे विभागों में पद सृजित करने के आरोप भी लगे हैं, जो मौजूद नहीं थे। मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई है। पूर्व कुलपति डॉ. राजीव सूद ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में नियुक्तियां प्रबंधन मंडल की मंजूरी के बाद हुई थीं। वहीं, वर्तमान प्रबंधन नियुक्तियों और पदोन्नतियों की जांच कर रहा है।

चंडीगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, चार वरिष्ठ अधिकारी 21 अगस्त से होंगे कार्यमुक्त

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़ पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। पुलिस महानिदेशक डॉ. सागर प्रीत हुड्डा की ओर से जारी आदेश के अनुसार दो आईपीएस अधिकारियों समेत चार वरिष्ठ अधिकारियों को 21 अगस्त 2026 की सुबह से चंडीगढ़ पुलिस से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय और चंडीगढ़ के प्रशासक की ओर से जारी आदेशों के अनुपालन में की जा रही है।

पुलिस मुख्यालय के आदेश के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने 9 जुलाई 2026 को अधिकारियों से संबंधित आदेश जारी किए थे। इसके बाद चंडीगढ़ के प्रशासक की ओर से 3 अगस्त 2026 को आवश्यक आदेश जारी किए गए। इन्हीं आदेशों के आधार पर चारों अधिकारियों को उनके नए कार्यभार पर योगदान देने के लिए चंडीगढ़ पुलिस से कार्यमुक्त किया जा रहा है।

चंडीगढ़ पुलिस से कार्यमुक्त होने वाले अधिकारियों में मंजीत, आईपीएस, एजीएमयूटी 2015 बैच और गीतांजलि खंडेलवाल, आईपीएस, एजीएमयूटी 2015 बैच शामिल हैं। इनके अलावा विकास श्योकंद, दानिप्स 2014 बैच और ए. वेंकटेश, दानिप्स 2014 बैच को भी कार्यमुक्त किया जाएगा।

आदेश के अनुसार चारों अधिकारी 21 अगस्त 2026 को पूर्वाह्न से चंडीगढ़ पुलिस का कार्यभार छोड़ेंगे। इसके बाद उन्हें अपने नए संबंधित पदों और जिम्मेदारियों पर योगदान देना होगा।

चार वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ कार्यमुक्त किए जाने को चंडीगढ़ पुलिस में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती हैं और उनके स्थानांतरण अथवा नई नियुक्ति के बाद कई विभागों के कामकाज में बदलाव की संभावना रहती है।

मलेशिया से लौटे बंबीहा गैंग के तीन आरोपी, पंजाब पुलिस ने कसा शिकंजा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब पुलिस ने विदेश में छिपकर आपराधिक गतिविधियां चला रहे आरोपितों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दविंदर बंबीहा गैंग से जुड़े तीन वांछित आरोपितों को मलेशिया से भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग की विदेश में छिपे आरोपितों को पकड़ने वाली विशेष टीम ने केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से तीनों का प्रत्यर्पण कराया।

मलेशिया से भारत लाए गए आरोपितों की पहचान जसप्रीत सिंह उर्फ जस बेहबल, अजय सिंह और पवंदीप सिंह के रूप में हुई है। तीनों को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पंजाब पुलिस उन्हें राज्य में लेकर आई और अब उनसे विभिन्न मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के अनुसार तीनों आरोपित हत्या, रंगदारी और विस्फोटक से जुड़े कई मामलों में वांछित थे। इसके अलावा लुधियाना में हथगोले से विस्फोट करने की साजिश के मामले में भी पुलिस को उनकी तलाश थी। जांच में यह बात सामने आई है कि पंजाब में आपराधिक गतिविधियों के बाद तीनों विदेश भाग गए थे और मलेशिया में छिपकर रह रहे थे।

पुलिस के अनुसार तीनों आरोपितों के खिलाफ पंजाब में दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी है। जांच एजेंसियां अब उनसे पुराने मामलों में उनकी भूमिका के साथ-साथ विदेश में बैठकर संचालित किए जा रहे आपराधिक नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही हैं।

पुलिस जांच में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े संपर्कों की आशंका भी सामने आई है। हथियारों और विस्फोटकों की व्यवस्था, रंगदारी तथा हिंसक वारदातों में उनकी भूमिका को लेकर भी पूछताछ की जा रही है।

ग्रामीण और सीमावर्ती स्कूलों में बच्चों की भागीदारी पर उठे सवाल, आयोग ने मांगा जवाब

पंजाब के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर एनएचआरसी सख्त, मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना

पंजाब के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन और विद्यार्थियों की भागीदारी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीर रुख अपनाया है। आयोग ने विशेष रूप से सीमावर्ती, ग्रामीण, दूरदराज और कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों को राष्ट्रीय दिवस से जुड़ी गतिविधियों में समान अवसर नहीं मिलने के आरोपों पर संज्ञान लिया है। आयोग ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहायक रजिस्ट्रार कानून बृजवी सिंह की ओर से 18 अगस्त 2026 को जारी पत्र में मामले का उल्लेख किया गया है। शिकायत 17 अगस्त को आयोग के समक्ष रखी गई थी और अगले ही दिन इस पर आदेश जारी कर दिए गए। आयोग ने पंजाब सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि यदि स्कूलों में विद्यार्थियों की भागीदारी में किसी तरह की असमानता पाई गई तो इसके पीछे क्या कारण रहे और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए।

झंडारोहण और राष्ट्रगान को लेकर शिकायत : आयोग के समक्ष दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि पंजाब के कई सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह सरकारी निर्देशों के अनुरूप आयोजित नहीं किए गए। खासकर सीमावर्ती, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के स्कूलों में विद्यार्थियों को झंडारोहण, राष्ट्रगान, स्वतंत्रता संग्राम, संवैधानिक मूल्यों, मौलिक कर्तव्यों और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों से जुड़ी गतिविधियों में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया।

शिकायत में यह भी आशंका जताई गई कि संसाधन संपन्न शहरी स्कूलों और ग्रामीण अथवा दूरदराज क्षेत्रों के स्कूलों के बच्चों को राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अलग-अलग शैक्षिक और नागरिक अनुभव मिल रहे हैं। आयोग ने हालांकि स्पष्ट किया कि किसी स्कूल में समारोह का अलग तरीके से आयोजित होना अपने आप में मानवाधिकार उल्लंघन नहीं माना जा सकता। लेकिन यदि प्रशासनिक लापरवाही या सरकारी निर्देशों के पालन में कमी के कारण बच्चों के किसी वर्ग को व्यवस्थित रूप से समान अवसरों से वंचित किया गया है तो इसकी जांच आवश्यक है।

संविधान और शिक्षा के अधिकार का हवाला : आयोग ने मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लेख करते हुए समानता और समान संरक्षण के अधिकार पर जोर दिया है। इसके अलावा अनुच्छेद 21-ए के तहत बच्चों के निश्शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का भी हवाला दिया गया है। आयोग ने अनुच्छेद 51-ए के तहत संविधान, उसके आदर्शों और संस्थाओं के सम्मान तथा स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित मूल्यों को आगे बढ़ाने की नागरिक जिम्मेदारी का भी उल्लेख किया।

अमृतसर में नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, हथियारों संग नौ गिरफ्तार

◆ विदेशी हैंडलरों से जुड़े गिरोह का पर्दाफाश, हेरोइन, पिस्तौल और नकदी बरामद

भारतेन्दु संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशे और हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से आठ विदेशी पिस्तौल, साढ़े आठ किलो हेरोइन और 12.95 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। बरामद हेरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपये बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार बरामद नकदी कथित तौर पर पिछले एक सप्ताह के दौरान नशे की बिक्री से जुटाई गई थी।

प्रारंभिक जांच में गिरोह के तार विदेश में बैठे कुछ कथित हैंडलरों से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि विदेश से गिरोह को निर्देश कौन दे रहा था और हथियार तथा नशीले पदार्थों की खेप पंजाब तक किस माध्यम से पहुंचाई जाती थी। जांच में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ और हथियारों की खेप पहुंचाए जाने की आशंका भी सामने आई है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और उनकी भूमिका का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही हथियारों और हेरोइन की तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय नशा और हथियार तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

परीक्षा के चलते चन्नी ने कांग्रेस बैठक से बनाई दूरी

चन्नी की गैरमौजूदगी पर सियासी चर्चाएं तेज, पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी फिर आई सामने

भारतेन्दु संवाददाता, संगरूर

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी बुधवार को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शामिल नहीं होंगे। चन्नी कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य हैं और बैठक में पंजाब से जुड़े राजनीतिक एवं संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। हालांकि, उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है। उनकी अनुपस्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब पंजाब कांग्रेस में संगठन को लेकर अंदरूनी खींचतान और नेताओं के बीच मतभेद की चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं।

जानकारी के अनुसार चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं और गुरुवार को उनकी अंतिम परीक्षा है। इसी वजह से वह दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि, चन्नी की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार परीक्षा उनके कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी कारण उन्होंने बैठक से दूरी बनाने का निर्णय लिया है।

दिल्ली में होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक में देश और विभिन्न राज्यों की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के साथ-साथ संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारियों पर चर्चा होने की संभावना है। पंजाब से जुड़े राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दे भी बैठक के एजेंडे में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

चन्नी की गैरमौजूदगी को लेकर पंजाब कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। पंजाब में पार्टी के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर लंबे समय से अलग-अलग मत सामने आते रहे हैं। चन्नी और उनके समर्थक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को दोबारा जिम्मेदारी दिए जाने पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यसमिति जैसी महत्वपूर्ण बैठक से चन्नी की अनुपस्थिति को कुछ लोग राजनीतिक नजरिए से भी देख रहे हैं।

हालांकि, उनकी अनुपस्थिति को लेकर किसी तरह का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। चन्नी की गुरुवार को परीक्षा होने की जानकारी सामने आई है और यह उनके बैठक में शामिल नहीं होने का प्रमुख व्यक्तिगत कारण माना जा रहा है। कांग्रेस के भीतर पंजाब से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान उनके विचारों और रुख को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी के बावजूद पंजाब की राजनीति और संगठनात्मक स्थिति पर बैठक में चर्चा होने की संभावना है।

आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पंजाब कांग्रेस के लिए संगठनात्मक एकजुटता बड़ा मुद्दा है। पार्टी लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दे रही है। ऐसे में चन्नी का बैठक से दूर रहना पार्टी के भीतर राजनीतिक चर्चाओं को जरूर हवा दे सकता है। हालांकि, परीक्षा के कारण उनकी अनुपस्थिति को फिलहाल निजी मामला ही माना जा रहा है। पार्टी की ओर से भी इस संबंध में किसी तरह की राजनीतिक व्याख्या सामने नहीं आई है।

इस बीच पंजाब की राजनीति में चन्नी की भूमिका पर भी नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद चन्नी कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं और राज्य की राजनीति में उनका अपना प्रभाव माना जाता है। इसलिए कार्यसमिति की बैठक में उनकी अनुपस्थिति को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक पर्यवेक्षकों की दिलचस्पी स्वाभाविक है।

चंडीगढ़ में 21 अगस्त को लगेगा पेट्रोल लंगर, वाहन चालकों को मिलेंगे कूपन

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

अमृतसर निवासी राकेश त्रेहन, जिन्हें राजा दी किंग के नाम से जाना जाता है, अब चंडीगढ़ में पेट्रोल का लंगर लगाने जा रहे हैं। यह आयोजन 21 अगस्त को सेक्टर-10 और सेक्टर-7 स्थित पेट्रोल पंपों के बाहर किया जाएगा। इस दौरान वाहन चालकों को पेट्रोल के लिए कूपन दिए जाएंगे। आयोजक के अनुसार दोपहिया और तिपहिया वाहन चालकों को 500 रुपये तथा चारपहिया वाहन चालकों को 1000 रुपये का पेट्रोल कूपन दिया जाएगा।

राजा दी किंग ने स्वयं इस आयोजन की घोषणा की है। पहले पेट्रोल का लंगर 18 अगस्त को आयोजित किया जाना था, लेकिन चंडीगढ़ में भारी बारिश के कारण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। अब इसे 21 अगस्त को निर्धारित स्थानों पर आयोजित करने की तैयारी है। आयोजन को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता बनी हुई है।

पहले भी लगा चुके हैं कई तरह के लंगर : राजा दी किंग इससे पहले भी चंडीगढ़ में अलग-अलग तरह के लंगर आयोजित कर चुके हैं। कुछ समय पहले सेक्टर-8 में आयोजित लंगर के दौरान उन्होंने लोगों को 500-500 रुपये के नोट के साथ खाने-पीने की चीजें भी उपलब्ध कराई थीं। इस दौरान फास्ट फूड, मैकडॉनल्ड के बर्गर और ठंडे पेय भी बांटे गए थे। इसके अलावा वह राशन और भारतीय मुद्रा से जुड़े लंगर भी लगा चुके हैं।

राजा दी किंग का कहना है कि वह लोगों की सेवा के उद्देश्य से इस तरह के आयोजन करते हैं। उनका दावा है कि उन पर महामाई की कृपा है और इसी भावना के चलते वह समय-समय पर जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं।

बिटकॉइन कारोबार से कमाई का हिस्सा सेवा में : राकेश त्रेहन के अनुसार उनके पिता अमृतसर में कपड़े का कारोबार करते थे, जबकि वह स्वयं बिटकॉइन का कारोबार करते हैं। उनका कहना है कि बिटकॉइन से होने वाली कमाई का एक हिस्सा वह लोगों की सेवा में खर्च करते हैं। इसी के तहत वह अलग-अलग प्रकार के लंगर आयोजित करते हैं।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में छह अहम विधेयकों पर होगा मंथन

कारोबार आसान बनाने, एमएसएमई मजबूत करने और नशे पर शिकंजा कसने वाले विधेयक सत्र में आएंगे

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का आगामी सत्र सरकार के व्यापक विधायी एजेंडे के कारण काफी महत्वपूर्ण रहने की संभावना है। 21 सितंबर से श्रीनगर में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सरकार करीब आधा दर्जन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इनमें कारोबार शुरू करने और संचालित करने की प्रक्रिया आसान बनाने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मजबूती देने तथा नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा मजबूत करने से जुड़े प्रस्ताव प्रमुख हैं।

सूत्रों के अनुसार संबंधित विभाग इन विधेयकों के मसौदों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रस्तावों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास भेजा जाएगा। आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद विधेयकों को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

कारोबार शुरू करना होगा आसान : सरकार के विधायी एजेंडे में कारोबार सुगमता से जुड़ा कानून सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों में शामिल है। इसके माध्यम से जम्मू-कश्मीर में नया कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और अनावश्यक औपचारिकताओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था में कुछ अनिवार्य प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए कारोबारियों को तीन वर्ष तक का समय देने का प्रावधान किया जा सकता है।

सरकार का मानना है कि इससे नए उद्यमियों को शुरुआती दौर में राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न विभागों की मंजूरियों तथा दस्तावेजी प्रक्रियाओं में कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चार अगस्त को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भी इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। कुछ मंत्रियों द्वारा विस्तृत प्रस्तुति मांगे जाने के बाद फैसला टाल दिया गया था। अब विभागीय प्रस्तुति के बाद इसे दोबारा कैबिनेट के सामने लाए जाने की संभावना है।

एनओसी और लाइसेंस की प्रक्रिया होगी सरल : प्रस्तावित सुधारों में विभिन्न विभागों से अलग-अलग अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की व्यवस्था को कम करने पर जोर दिया गया है। जहां संभव होगा वहां स्व-प्रमाणन व्यवस्था लागू करने तथा अनावश्यक लाइसेंस और अनुमतियों को घटाने की तैयारी है।

होटल, होम स्टे, शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए मंजूरी प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा सकता है। निरीक्षण व्यवस्था में भी बदलाव की संभावना है। सरकार निरीक्षणों की संख्या कम करने और निरीक्षण रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है।

एमएसएमई को मिलेगा विधायी सहारा : सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अलग विधायी ढांचा तैयार करने पर भी काम कर रही है। इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों और उद्यमियों के लिए संस्थागत व्यवस्था मजबूत करना तथा नियामकीय अड़चनों को कम करना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और कारोबार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

नशे के खिलाफ कानून होगा मजबूत : नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी पर रोक लगाने के लिए भी सरकार मौजूदा कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून के जरिए नशे के कारोबार पर नियंत्रण के साथ इसके दुरुपयोग को रोकने के उपायों को मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा आपदा पीड़ितों के लिए राहत और रोजगार, ऊर्जा तथा उच्च शिक्षा से जुड़े विधेयकों पर भी काम चल रहा है। विधानसभा सचिवालय ने सरकार से सत्र के सरकारी कामकाज और विधायी एजेंडे का विवरण मांगा है।

अमेरिकी दूत से मुलाकात पर उमर बोले- जम्मू-कश्मीर मुद्दों पर नहीं मांगेंगे समाधान

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

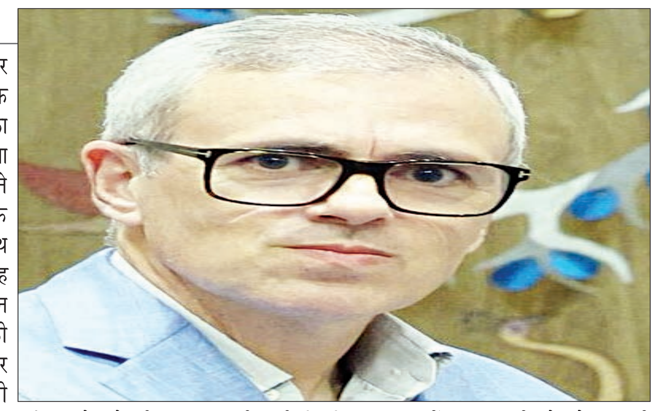

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े मुद्दों का समाधान भारत सरकार को करना है, अमेरिका को नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के साथ प्रस्तावित मुलाकात के दौरान वह न तो कोई शिकायत करेंगे और न ही किसी समस्या के समाधान की मांग रखेंगे। सर्जियो गोर बुधवार को जम्मू-कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे हैं। श्रीनगर में उनकी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात निर्धारित है।

श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिकी दूत के साथ बैठक में जम्मू-कश्मीर और पूरे क्षेत्र की मौजूदा स्थिति सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात का उद्देश्य अपनी समस्याओं को अमेरिका के सामने रखकर समाधान मांगना नहीं है। उमर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के मामलों को केंद्र सरकार के साथ ही उठाया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अमेरिकी दूत की बात सुनने को अधिक प्राथमिकता देंगे और साथ ही अपनी ओर से भी जम्मू-कश्मीर की स्थिति और लोगों से जुड़े विषयों पर जानकारी साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद इस तरह की बैठक हो रही है और वह बातचीत के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने संकेत दिया कि बैठक में क्षेत्रीय परिस्थितियों को समझने और विचारों के आदान-प्रदान पर जोर रहेगा।

इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने बुधवार सुबह श्रीनगर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर कई विकास परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अधिकांश परियोजनाओं का काम संतोषजनक तरीके से आगे बढ़ रहा है। हालांकि कुछ परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए प्रशासन की ओर से अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है।

वहीं, भाजपा की ओर से सरकारी नियुक्तियों में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस, अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उनके सीधे नियंत्रण में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि नियुक्तियों में वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोष साबित होने पर मामला दर्ज कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

उमर ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी तरह की अनदेखी नहीं होनी चाहिए और आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए संबंधित जांच एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए।

बुड्ढा अमरनाथ दर्शन के बाद शिवखोड़ी पहुंचे 2044 श्रद्धालु, भोले बाबा का लिया आशीर्वाद

2044 श्रद्धालुओं की आमद से शिवखोड़ी में बढ़ी धार्मिक रौनक

भारतेंदु संवाददाता, पौनी। बाबा बुड्ढा अमरनाथ के दर्शन करने के बाद बुधवार को करीब 2044 श्रद्धालुओं का पहला जत्था शिवखोड़ी पहुंचा। श्रद्धालुओं ने यहां पवित्र गुफा में भोले बाबा के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं के पहुंचने से शिवखोड़ी क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल बना रहा।

जानकारी के अनुसार बुड्ढा अमरनाथ के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं का जत्था सुबह शिव शक्ति आश्रम कोठियां पहुंचा। यहां सुबह करीब आठ बजे श्रद्धालुओं ने लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद करीब नौ बजे सभी श्रद्धालु शिव शक्ति आश्रम से शिवखोड़ी के लिए रवाना हुए।

शिवखोड़ी पहुंचने पर श्राइन बोर्ड के प्रबंधक तरसेम लाल शर्मा और तहसीलदार पौनी साहिल रंधावा ने श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत किया। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने बारी-बारी से शिवखोड़ी स्थित भोले बाबा की पवित्र गुफा में पहुंचकर दर्शन किए।

दर्शन के बाद श्रद्धालुओं का जत्था शाम करीब चार बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू के लिए रवाना हुआ। इस दौरान प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी बाबा अमरनाथ और बाबा बुड्ढा अमरनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालु शिवखोड़ी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए शिव शक्ति आश्रम कोठियां में लंगर की विशेष व्यवस्था की गई है। यहां श्रद्धालुओं को भोजन और प्रसाद उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए शिवखोड़ी और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। जिला पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना के जवान चप्पे-चप्पे पर तैनात हैं। सुरक्षा कर्मियों द्वारा प्रमुख मार्गों, प्रवेश द्वारों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है।

चार ग्राम हेरोइन संग पकड़ा तस्कर, पुलिस ने किया मामला दर्ज

भारतेंदु संवाददाता, कठुआ। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कठुआ पुलिस ने बेरियां पत्तन लिंक रोड क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक कथित नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब चार ग्राम हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार हटली पुलिस चौकी की टीम क्षेत्र में नियमित गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम ने संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब चार ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान बरकत अली निवासी सुर्जन चलोग, तहसील बनी, जिला कठुआ के रूप में हुई है। बरामद पदार्थ को कब्जे में लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना कठुआ में एफआईआर संख्या 408/2026 दर्ज की है। मामला एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 8/21/22 के तहत दर्ज किया गया है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बरामद पदार्थ के स्रोत तथा आरोपी के संभावित संपर्कों की जानकारी जुटाई जा रही है। यह कार्रवाई एसएसपी कठुआ मोहित शर्मा की निगरानी में की गई।

नशामुक्ति के बाद आत्मनिर्भर बनेंगे युवा, रोजगार से जुड़ेगा पुनर्वास अभियान

नशामुक्ति के बाद कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और रोजगार के मिलेंगे नए अवसर

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। नशे के खिलाफ जम्मू पुलिस की मुहिम अब केवल उपचार और नशामुक्ति तक सीमित नहीं रहेगी। ड्रग डी-एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर को मरीजों के पुनर्वास के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत नशामुक्त होकर लौटने वाले लोगों को कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की तैयारी है।

18 हजार मरीजों के उपचार के बाद अब रोजगार से जोड़ेगा पुनर्वास केंद्र

डीडीआरसी में वर्तमान में 25 आईपीडी बेड उपलब्ध हैं, जबकि 12 घंटे की ओपीडी सेवा के जरिए हर महीने करीब 500 लोगों का उपचार किया जा रहा है। केंद्र में अब तक लगभग 18 हजार लोगों का उपचार हो चुका है। मरीजों के लिए भोजन और रहने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। उपचार और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए केंद्र में भर्ती रहे करीब 10,500 मरीजों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया है।

कौशल प्रशिक्षण से रोजगार तक : एसपी अन्ना लता सिन्हा के नेतृत्व में केंद्र को व्यापक पुनर्वास केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। उनका कहना है कि नशामुक्ति के बाद मरीजों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मानसिक मजबूती के साथ रोजगारपरक कौशल भी मिलना जरूरी है।

इसी उद्देश्य से जल्द कौशल एवं प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की योजना है। यहां प्लंबिंग, बिजली का काम, मोबाइल मरम्मत, कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी, सौर तकनीशियन और वातानुकूलन उपकरणों की मरम्मत जैसे अल्पकालिक पाठ्यक्रम करवाए जाएंगे। साथ ही योग एवं ध्यान केंद्र स्थापित करने की भी तैयारी है।

डीडीआरसी मिशन युवा और कौशल भारत के साथ समझौते की दिशा में भी काम कर रहा है। इसके तहत छह माह या उससे अधिक समय तक नशे से दूर रहने वाले मरीजों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

विद्यार्थियों ने किया शोध : जम्मू और दिल्ली विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान तथा अपराध विज्ञान विभागों के दस स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने डीडीआरसी में शोध प्रशिक्षण लिया। विद्यार्थियों ने नशे की समस्या, परामर्श और पुनर्वास प्रक्रिया को करीब से समझा। केंद्र में आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से भी मरीजों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बढ़ाने का प्रयास किया गया।

बारिश के बीच वैष्णो देवी यात्रा जारी

सुरक्षा कारणों से बैटरी कार मार्ग बंद

भारतेंदु संवाददाता, कटड़ा। खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के बावजूद बुधवार को मां वैष्णो देवी की यात्रा पारंपरिक मार्ग से सुचारू रूप से जारी रही। बारिश के कारण श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान कई स्थानों पर परेशानी का सामना करना पड़ा। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश के बीच श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए भवन की ओर बढ़ते रहे।

बारिश से बचने के लिए श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्ग पर बनाए गए आश्रय स्थलों का सहारा लिया। कई श्रद्धालु कुछ देर वहां रुकने के बाद मौसम में थोड़ी राहत मिलते ही अपनी यात्रा आगे बढ़ाते नजर आए। खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं में माता के दर्शन को लेकर उत्साह बना रहा। लगातार बारिश और मौसम की स्थिति को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण बैटरी कार मार्ग को एहतियातन बंद कर दिया। बताया गया कि मार्ग के कुछ हिस्सों में पहाड़ी से कंकड़-पत्थर और मलबा गिरने के साथ कीचड़ जमा हो गया था। इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही में जोखिम बढ़ गया था।

मार्ग बंद किए जाने के बाद सफाई और बहाली का कार्य शुरू कर दिया गया। सफाई कर्मचारियों के साथ आपदा प्रबंधन दल के जवान भी मौके पर तैनात हैं। टीमें मार्ग से मलबा और कीचड़ हटाने में लगातार जुटी हुई हैं, ताकि स्थिति सामान्य होने पर श्रद्धालुओं की आवाजाही सुरक्षित तरीके से बहाल की जा सके।

नई नीति से ग्रामीण पर्यटन, आसान ऋण और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

जम्मू-कश्मीर में होमस्टे विस्तार से गांवों तक पहुंचेगा पर्यटन और रोजगार का नया अवसर

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को प्रसिद्ध स्थलों से आगे ग्रामीण और अनछुए क्षेत्रों तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन होमस्टे व्यवस्था को मजबूत कर स्थानीय परिवारों और बेरोजगार युवाओं को पर्यटन अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर जोर दे रहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव अटल डुल्लू की अध्यक्षता में हुई बैठक में नई होमस्टे नीति की समीक्षा की गई और दूरदराज क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने पर चर्चा हुई।

प्रशासन का मानना है कि होमस्टे के विस्तार से गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, खानपान तथा जीवनशैली को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में 2,802 पंजीकृत होमस्टे इकाइयां हैं, जिनमें करीब 20,514 बिस्तरों की क्षमता है। सरकार अब पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने और संपत्ति मालिकों को अधिक सहायता देने की दिशा में काम कर रही है।

अधिकारियों के अनुसार, पात्र आवेदकों को जम्मू-कश्मीर बैंक के माध्यम से प्रत्येक कमरे के लिए पांच लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है। एक संपत्ति के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये निर्धारित है। इसका उद्देश्य परिवारों को अपने घरों को पर्यटकों के लिए बेहतर आवास में बदलने में मदद करना है।

नई नीति के तहत दूसरी आवासीय संपत्तियों को बिस्तर एवं नाश्ता मॉडल के रूप में संचालित करने की अनुमति देने पर भी जोर है। इससे कम इस्तेमाल होने वाले मकानों से परिवारों की अतिरिक्त आय बढ़ सकती है।

लखनपुर में गोवंश तस्करी नाकाम, 15 गोवंश मुक्त चालक गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, कठुआ। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लखनपुर में गोवंश तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए 15 गोवंश को मुक्त करवाया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक को गिरफ्तार कर तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रक को भी जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार लखनपुर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ट्रक टर्मिनल में नाका लगाया था। इसी दौरान पंजाब से जम्मू-कश्मीर की ओर आ रहे संदिग्ध ट्रक संख्या जेके21-3250 को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक में 15 गोवंश लदे हुए पाए गए। पुलिस ने सभी गोवंश को सुरक्षित मुक्त करवाया।

बारिश से बासमती फसल को संजीवनी जम्मू के किसानों को बंपर पैदावार की उम्मीद

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। लगातार अंतराल पर हो रही बारिश से जम्मू के आरएसपुरा क्षेत्र में बासमती धान की फसल को बड़ी राहत मिली है। रोपाई के शुरुआती दिनों में पानी की कमी से परेशान किसानों को अब सिंचाई के लिए पंपसेट चलाने और नहरों पर निर्भर रहने की जरूरत कम पड़ रही है। पर्याप्त बारिश से खेतों में हरियाली लौट आई है और किसान अच्छी पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं।

आरएसपुरा से अखनूर होते हुए कठुआ तक करीब 65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बासमती धान की खेती की जाती है। क्षेत्र की बासमती अपनी खुशबू और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण बड़ी संख्या में किसान वर्षों से पारंपरिक बासमती खेती से जुड़े हुए हैं। नंदपुर के किसान विजय सैनी ने बताया कि शुरुआत में बारिश कम होने से चिंता थी, लेकिन अब फसल तेजी से बढ़ रही है। अरनिया के किसान महेश सिंह ने भी खेतों में अच्छी हरियाली देखकर इस बार बेहतर उत्पादन की उम्मीद जताई।

किसानों का कहना है कि यदि सितंबर में भी पर्याप्त बारिश होती रही तो बासमती की पैदावार अच्छी रह सकती है और उन्हें बेहतर आमदनी मिलने की संभावना है।

सोहांजना के किसान कुलभूषण खजूरिया ने बताया कि बासमती धान तैयार होने में अधिक समय लेता है, लेकिन क्षेत्र में इसकी खेती को किसान प्राथमिकता देते हैं। पनोतरे चक के किसान कुलदीप राज ने स्थानीय रणबीर बासमती 370 के संरक्षण और खेती को बढ़ावा देने की मांग की।

मांसाहारी व्यंजनों पर एफएसएसएआई सख्त मेन्यू में मांस की पूरी जानकारी देना अनिवार्य

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे या कैफे में खाना खाने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। अब मांसाहारी व्यंजन परोसने वाले खाद्य कारोबारियों को मेन्यू में इस्तेमाल किए गए मांस की स्पष्ट जानकारी देनी होगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वे मेन्यू में केवल सामान्य शब्दों जैसे मीट करी, मीट कबाब या नॉन-वेज का इस्तेमाल करने के बजाय उसमें इस्तेमाल होने वाले मांस का प्रकार स्पष्ट रूप से दर्ज करें।

नई व्यवस्था के तहत यदि किसी व्यंजन में चिकन, मटन, मछली, बीफ या किसी अन्य प्रकार के मांस का इस्तेमाल किया गया है तो इसकी जानकारी ग्राहकों को मेन्यू कार्ड, खाद्य सुरक्षा सूचना बोर्ड या संबंधित प्रदर्शन स्थल पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध करानी होगी। इसका उद्देश्य ग्राहकों को भोजन के संबंध में पूरी जानकारी देना और किसी भी तरह की गलतफहमी को रोकना है।

एफएसएसएआई ने होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबे, मिठाई की दुकानों, बेकरी और कैटरिंग कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा सूचना बोर्ड लगाने पर भी जोर दिया है। बोर्ड ऐसी जगह लगाया जाना चाहिए जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें। इसमें एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या और ग्राहक सहायता से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिए।

प्राधिकरण के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा संबंधित नियमों के तहत खाद्य कारोबारियों की जिम्मेदारी है कि ग्राहकों को सुरक्षित और सही तरीके से प्रदर्शित भोजन उपलब्ध कराया जाए। भोजन से जुड़ी जानकारी स्पष्ट और आसानी से पढ़ी जा सकने वाली होनी चाहिए।

एफएसएसएआई की सलाह के अनुसार मांसाहारी भोजन बेचने वाले कारोबारियों को प्रत्येक व्यंजन में इस्तेमाल किए गए मांस की जानकारी देनी होगी। उदाहरण के तौर पर चिकन करी में चिकन और मटन करी में मटन का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। इसी तरह कबाब, बिरयानी और अन्य मांसाहारी व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाले मांस की जानकारी भी ग्राहक को दी जानी चाहिए।

आरक्षण खेल प्रतिभाओं को मिलेगा रोजगार का सहारा, नई नीति से बढ़ेगा युवाओं का उत्साह

लद्दाख के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा चार प्रतिशत आरक्षण

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। लद्दाख के खिलाड़ियों के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। खेल को करियर के रूप में अपनाने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को अब सरकारी नौकरी में भी सीधा लाभ मिलेगा। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख प्रशासन के तहत समूह 'ग' के अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी है। प्रशासन ने इसके बाद संबंधित नियमों को अधिसूचित भी कर दिया है।

इस फैसले को लद्दाख के खेल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे खिलाड़ियों को खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के साथ भविष्य में रोजगार की सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। प्रशासन का उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करना और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करना है।

सभी सामाजिक वर्गों में लागू होगा आरक्षण : चार प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज आरक्षण के रूप में लागू होगा। इसका अर्थ है कि इसका लाभ विभिन्न सामाजिक वर्गों के पात्र खिलाड़ियों को मिलेगा और चयनित खिलाड़ी अपनी संबंधित आरक्षित या सामान्य श्रेणी में समायोजित किए जाएंगे। यह आरक्षण लद्दाख प्रशासन के अंतर्गत समूह 'ग' के सभी सीधी भर्ती वाले पदों पर लागू होगा। हालांकि प्रशासन द्वारा विशेष रूप से बाहर रखे गए पद इसके दायरे में नहीं आएंगे। आरक्षण का लाभ लेने के लिए खिलाड़ियों को भर्ती से जुड़ी सभी आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यता शर्तों के साथ भर्ती परीक्षा की शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

किन खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ : नियमों के तहत राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य या देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी पात्र होंगे। इसके अलावा वरिष्ठ या कनिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी में शामिल किया गया है।

18 वर्ष से अधिक आयु के वे खिलाड़ी भी पात्र होंगे जिन्होंने खेलो इंडिया युवा खेल, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, खेलो इंडिया पैरा खेल या खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में पदक हासिल किया है। मान्यता प्राप्त अंतरविश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में अपनी विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को भी नियमों में शामिल किया गया है। शतरंज के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी केंद्र सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार इसका लाभ मिलेगा।

खेल उपलब्धियों के आधार पर बनेगी मेरिट सूची : पात्र खिलाड़ियों की अलग खेल मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसमें खिलाड़ियों की रैंकिंग प्रतियोगिता के स्तर और उनके प्रदर्शन के आधार पर तय होगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा।

भारतेन्दु शिखर

शिक्षा और मार्गदर्शन के महत्व को समझाने वाला है गुरुवार का विशेष दिन

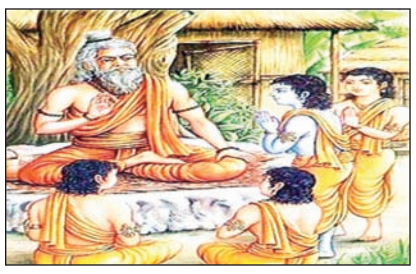

रामपाल पाठक
स्वतंत्र लेखक

गुरुवार सप्ताह का एक महत्वपूर्ण दिन है, जिसे भारतीय परंपरा में विशेष धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्राप्त है। सप्ताह में बुधवार के बाद और शुक्रवार से पहले आने वाला यह दिन सामान्य रूप से गुरु के नाम से जुड़ा माना जाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को ज्ञान, शिक्षा, संस्कार और मार्गदर्शन का प्रतीक माना गया है। इसी कारण गुरुवार को कई लोग गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने और अपने जीवन में ज्ञान तथा सकारात्मक विचारों को बढ़ाने का अवसर मानते हैं। यह दिन केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि आत्मचिंतन, अनुशासन और अच्छे कार्यों के लिए भी प्रेरणा देता है।

हिंदू धार्मिक मान्यताओं में गुरुवार का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, धर्म, विवेक और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ज्योतिषीय मान्यताओं में भी बृहस्पति को महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इसी वजह से गुरुवार के दिन कई लोग भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं। श्रद्धालु मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं और परिवार की सुख-शांति, समृद्धि तथा सफलता की कामना करते हैं। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और धार्मिक नियमों का पालन करते हैं।

गुरुवार को पीले रंग का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक परंपराओं में पीला रंग ज्ञान, पवित्रता, सकारात्मकता और समृद्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है। कई श्रद्धालु इस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं तथा पूजा में पीले फूल, पीले फल, चने की दाल, हल्दी और अन्य पीली वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हालांकि इन परंपराओं का पालन व्यक्ति की अपनी आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। किसी भी धार्मिक परंपरा का वास्तविक उद्देश्य मन में श्रद्धा, संयम और सकारात्मक भावना विकसित करना माना जा सकता है।

गुरुवार का संबंध गुरु और शिक्षा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। भारतीय परंपरा में गुरु को जीवन का मार्गदर्शक माना गया है। गुरु केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं देते बल्कि व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर समझने तथा जीवन में उचित निर्णय लेने की प्रेरणा भी देते हैं। इसलिए गुरुवार का दिन शिक्षकों, माता-पिता और उन सभी लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर भी बन सकता है जिन्होंने हमारे जीवन में ज्ञान और दिशा प्रदान की है।

आधुनिक जीवन की व्यस्तता में गुरुवार आत्ममंथन के लिए भी उपयोगी दिन हो सकता है। सप्ताह का एक बड़ा हिस्सा पूरा होने के बाद व्यक्ति अपने कार्यों की समीक्षा कर सकता है और यह सोच सकता है कि उसने अपने लक्ष्यों की दिशा में कितनी प्रगति की है। विद्यार्थियों के लिए यह पढ़ाई की योजना को व्यवस्थित करने और कमजोर विषयों पर ध्यान देने का अवसर हो सकता है। कामकाजी लोगों के लिए यह सप्ताह के बाकी दिनों की प्राथमिकताएं तय करने और अधूरे कार्य पूरे करने की प्रेरणा दे सकता है।

गुरुवार को जरूरतमंद लोगों की सहायता करने और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संकल्प भी लिया जा सकता है। भोजन, वस्त्र या आवश्यक सामग्री का दान करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, बुजुर्गों का सम्मान करना और पर्यावरण की रक्षा के लिए छोटे कदम उठाना ऐसे कार्य हैं जिनसे समाज में सकारात्मक भावना मजबूत होती है। धार्मिक आस्था तभी अधिक सार्थक बनती है जब वह मानवता, करुणा और सेवा की भावना से जुड़ती है।

गुरुवार हमें ज्ञान, अनुशासन, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों का महत्व समझाता है। यह दिन व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखने, बड़ों का सम्मान करने और जीवन में सही दिशा चुनने की प्रेरणा दे सकता है। चाहे कोई व्यक्ति धार्मिक आस्था रखता हो या केवल सप्ताह के एक विशेष दिन के रूप में गुरुवार को देखता हो, वह इसे आत्मचिंतन और बेहतर कार्यों के लिए उपयोग कर सकता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

आस्था और पर्यटन के विस्तार के साथ स्थानीय सुविधाओं का विकास भी जरूरी

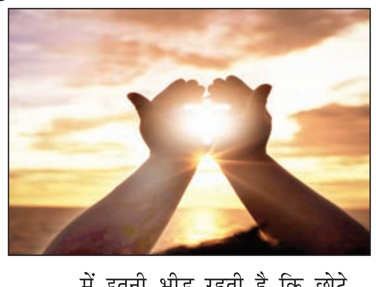

कनुप्रिया
स्वतंत्र लेखक

आस्था जब उत्कर्ष पर, उमड़े जन-अभिराम।
ध्यान रहे उस भीड़ में, न दब जाए जन-धाम॥

धार्मिक स्थलों की महत्ता भारतीय संस्कृति में सदैव से विशेष रही है। ये स्थल केवल पूजा-अर्चना के केंद्र नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ऐसे ही एक पावन स्थल वृंदावन की हालिया यात्रा ने मुझे जहां एक ओर भक्तिभाव से परिपूर्ण किया, वहीं दूसरी ओर एक गंभीर सामाजिक प्रश्न पर विचार करने के लिए भी बाध्य कर दिया।

वृंदावन की गलियों में उमड़ती अपार भीड़, 'राधे-राधे' के गगनभेदी जयघोष और भक्तों की अद्भुत श्रद्धा देखकर मन भाव-विभोर हो उठा। भीड़ इतनी अधिक थी कि क्षण भर को लगा मानो सांस लेना भी कठिन हो जाएगा, किंतु आस्था का वातावरण ऐसा था कि वही भीड़ धीरे-धीरे उत्साह और ऊर्जा का कारण बन गई, परंतु इस दृश्य का एक दूसरा पक्ष भी है, जो वहां के स्थानीय निवासियों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

दोहा – भक्त आए पल दो घड़ी, लेकर मन में प्रेम। पीड़ा उनकी कौन देखे, जिनका नित यह नेम॥ यात्रा के दौरान एक स्थानीय दुकानदार से हुई बातचीत ने इस विषय की वास्तविकता से परिचित कराया। उसने बताया कि प्रतिदिन की भीड़ उनके सामान्य जीवन को अत्यंत कठिन बना देती है।

बच्चों का विद्यालय पहुंचना तक चुनौती बन जाता है, क्योंकि गलियों में इतनी भीड़ रहती है कि छोटे बच्चों को अकेले भेजना जोखिमपूर्ण हो जाता है। परिणामस्वरूप अनेक बच्चे नियमित शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई वृद्ध या बीमार व्यक्ति अचानक चिकित्सकीय सहायता चाहता है, तो अस्पताल तक पहुंचना एक संघर्ष बन जाता है। कम दूरी भी भीड़ के कारण इतनी कठिन प्रतीत होती है कि कई बार सहायता समय पर नहीं मिल पाती।

सिर्फ शारीरिक ही नहीं, यह स्थिति मानसिक रूप से भी स्थानीय लोगों को प्रभावित करती है। निरंतर शोर, भीड़, अव्यवस्था और दैनिक व्यवधान उन्हें तनाव, थकान और अवसाद की स्थिति तक पहुंचा देते हैं।

आज परिवहन और संचार के साधनों के विकास ने धार्मिक यात्राओं को अत्यंत सरल बना दिया है। परिणामस्वरूप तीर्थस्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह धार्मिक पर्यटन जहां अर्थव्यवस्था और श्रद्धा दोनों के लिए सकारात्मक है, वहीं इसके दुष्प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

दोहा– पूजा पावन भाव है, श्रद्धा है सम्मान। पर जनजीवन भी रहे, इतना रखिए ध्यान॥ आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन, स्थानीय निकाय और समाज मिलकर ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करें जिनसे धार्मिक आस्था भी सुरक्षित रहे और स्थानीय नागरिकों का जीवन भी सुचारु बना रहे। बेहतर यातायात प्रबंधन, आपातकालीन मार्ग, भीड़ नियंत्रण और स्थानीय सुविधाओं का विस्तार इस दिशा में उपयोगी कदम हो सकते हैं।

अंततः यह समझना आवश्यक है कि आस्था तभी पूर्ण है जब वह किसी अन्य के जीवन को असहनीय न बनाए। धार्मिक स्थलों की पवित्रता तभी सार्थक है जब वहाँ श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय निवासियों के जीवन का सम्मान भी सुरक्षित रहे।

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि धार्मिक स्थलों पर बढ़ती भीड़ केवल स्थानीय जीवन को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि पर्यावरण और स्वच्छता व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डालती है। अनेक तीर्थस्थलों पर प्लास्टिक कचरा, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याएँ लगातार बढ़ रही हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। यदि समय रहते उचित प्रबंधन नहीं किया गया, तो इन पवित्र स्थलों की आध्यात्मिक गरिमा और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों प्रभावित हो सकते हैं।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

संपादकीय

महाराष्ट्र में 36 हजार कंपनियां बंद

महायुति सरकार के कार्यकाल में महाराष्ट्र में लाखों करोड़ रुपये के निवेश आने और राज्य के औद्योगीकरण में देश में पहले स्थान पर होने के दावों की जोरदार चर्चा हो रही है। प्रतिदिन नए समझौता ज्ञापनों और निवेश प्रस्तावों के आंकड़े जनता के सामने रखे जा रहे हैं। हालांकि संसद में हाल ही में सामने आए आधिकारिक आंकड़ों ने इन दावों की वास्तविकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सांसद राजाभाऊ वाजे द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पिछले पांच वर्षों में महाराष्ट्र की 36,211 निजी कंपनियां बंद हो गईं, उनका विघटन हो गया या उन्हें कंपनी रजिस्टर से पूरी तरह हटा दिया गया।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अकेले 12,181 कंपनियों पर ताले लगे हैं। इसके बाद पुणे में 6,433, ठाणे में 4,904 और नासिक में 840 कंपनियां बंद हुई हैं। ये आंकड़े राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता पैदा करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार सहित विपक्षी दलों ने इस गंभीर आंकड़े को लेकर सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बचाव करते हुए कहा कि बंद हुई कंपनियों में से 76 प्रतिशत कंपनियां ऐसी थीं, जो कभी शुरू ही नहीं हुईं। लेकिन सवाल यह है कि यदि इतनी बड़ी संख्या में कंपनियां कागजों पर स्थापित होकर शुरू ही नहीं हो सकीं, तो इसका कारण क्या है? यह स्थिति भी राज्य के उद्योग अनुकूल वातावरण पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

सरकार का यह तर्क एक क्षण के लिए स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि इतनी बड़ी संख्या में कंपनियों का शुरू न होना या शुरू होने के कुछ समय बाद बंद हो जाना आखिर किस ओर संकेत करता है। किसी भी राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए केवल निवेश प्रस्ताव और समझौता ज्ञापन पर्याप्त नहीं होते। इसके लिए अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, परिवहन, प्रशासनिक सुविधा, समय पर मंजूरियां और सुरक्षित कारोबारी वातावरण जरूरी होता है। इसलिए राज्य की औद्योगिक प्रगति का वास्तविक मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि कितने उद्योग वास्तव में जमीन पर उतरे, कितनी पूंजी का निवेश हुआ और उससे कितने रोजगार पैदा हुए।

बंद हुई इन कंपनियों के कारण कितने कर्मचारी बेरोजगार हुए और कितने परिवारों के भविष्य पर संकट आया, इसका कोई एकीकृत आंकड़ा केंद्र या राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। क्षेत्रवार देखा जाए तो केवल सेवा क्षेत्र में 14,693 कंपनियां बंद हुई हैं, जबकि उत्पादन क्षेत्र में 6,582 कंपनियों पर ताले लगे हैं। छोटे और मध्यम उद्योगों की यह समस्या राज्य की आर्थिक व्यवस्था को भीतर से कमजोर कर रही है। किसी उद्योग के बंद होने का प्रभाव केवल वहां काम करने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे जुड़े छोटे व्यापारियों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य लोगों की आजीविका पर भी पड़ता है।

दूसरी ओर चाकण और तलेगांव जैसे प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है। रोजाना की भारी यातायात समस्या, खराब सड़कें, पानी और बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और स्थानीय स्तर की समस्याओं से परेशान होकर चाकण की करीब 20 से अधिक बड़ी कंपनियों ने दूसरे राज्यों में स्थानांतरित होने की चेतावनी दी है। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो इसका सीधा असर महाराष्ट्र के रोजगार और औद्योगिक विकास पर पड़ेगा। किसी बड़े उद्योग के बाहर जाने के साथ उससे जुड़े सहायक उद्योग और रोजगार के अवसर भी दूसरे राज्यों में चले जाते हैं।

नासिक और छत्रपति संभाजीनगर का औद्योगिक क्षेत्र भी प्रशासनिक उदासीनता से परेशान होने की बात सामने आ रही है। दूसरी ओर गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे राज्य निवेश आकर्षित करने के लिए उद्यमियों को सुविधाएं और विभिन्न प्रकार की रियायतें उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में यदि बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक देरी बनी रहती है तो यहां मौजूद उद्योगों के सामने भी दूसरे राज्यों में जाने का विकल्प खुला रहेगा। श्रीरामपुर में कृषि महामंडल की 1500 एकड़ जमीन एक निजी कंपनी को 50 वर्ष के पट्टे पर बिना पारदर्शी निविदा के देने जैसे निर्णयों को लेकर भी सरकार की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

इस पूरे औद्योगिक संकट का सबसे बड़ा सीधा असर युवा पीढ़ी और रोजगार पर पड़ रहा है। सांख्यिकी मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार रोजगार की स्थिति को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। देश में स्नातक युवाओं की संख्या 6.3 करोड़ तक पहुंच चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में युवा आज भी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। हर वर्ष दो करोड़ रोजगार देने के वादे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शिक्षित युवा रोजगार के अवसरों की कमी के कारण निराश और परेशान हैं। उद्योग मजबूत होंगे तभी रोजगार के अवसर भी मजबूत होंगे। इसलिए सरकार को केवल बड़ी-बड़ी घोषणाओं और निवेश के आंकड़ों तक सीमित रहने के बजाय जमीन पर मौजूद वास्तविक समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

-शिवांश धाकड़

जिंदगी का धागा

कविता

योगिंद्र पाल वालिया, डडौर नेर चौक) जिला मंडी

जीवन का सफर यूँ ही चलता रहा,
कभी धागा उलझा, कभी सुलझता रहा।
कभी धूप मिली, कभी छाँव मिली,
हर मोड़ पर जिंदगी नई राह मिली।
ठहरी जिंदगी को जब पीछे मुड़कर देखा,
हर पल में कोई अपना चेहरा देखा।
कभी दोस्त मिले, कभी रिश्ते मिले,
कभी खुशियों के दीप जले, कभी गम मिले।
दोस्ती निभाई, रिश्तों को संभाला,
कभी किसी ने रूठकर दिल दुखाया,
कभी हमने मुस्कुराकर उसे मनाया,
इसी तरह जीवन ने सबक सिखाया।
कभी सुकून खुद में तलाशता रहा,
कभी दूसरों से सुकून माँगता रहा।
कभी भीड़ में अकेला चलता रहा,
कभी तन्हाई में खुद से मिलता रहा।
परहित को अपना धर्म समझा,
सेवा को जीवन का कर्म समझा।
राह कठिन थी, कदम फिर भी बढ़ते रहे,
टूटे सपनों में नए सपने सजते रहे।
बंधन बहुत थे, फिर भी नदी-सा बहा,
हर दर्द को चुपचाप सहता रहा।
किसी ने हाल पूछा, किसी ने शिकायत की,
हर रिश्ते ने अपनी एक कहानी लिखी।
पता ही नहीं चला समय कब गुजर गया,
देखते ही देखते मौसम भी बदल गया।
कभी धागा उलझा, कभी धागा सुलझा,
हर पल जीवन नया रंग दिखाता रहा।

आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति के बीच जनहित के मुद्दे लगातार हो रहे नजरअंदाज

कमलेश ठाकुर
स्वतंत्र लेखक

हिमाचल प्रदेश में राजनीति का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। कुछेक माननीय अमर्यादित भाषा का उच्चारण करके देवभूमि की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। माननीय एक-दूसरे को खलड़ी में रहने का सुझाव देकर सनसनी फैला चुके हैं। आपसी तीखी नोकझोंक में हू आर यू, नानसेंस जैसे शब्द विधानसभा सत्र में बोलकर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जा चुकी है। विधानसभा सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के नेता सदैव आपसी टकराव की स्थिति में रहते हुए जनहित के मुद्दों पर सही ढंग से चर्चा करने में सफल नहीं हो पाते हैं। माननीयों को प्रदेश की जनता ने इसलिए चुनकर भेजा है कि वे उनकी समस्याओं का समाधान करें। गनीमत यह है कि माननीय अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हुए एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने तक सीमित होकर रह गए हैं। जनता पर सरकारों की कर्जधारी का आर्थिक बोझ निरंतर बढ़ रहा है, जिसकी माननीयों को अवश्य चिंता करनी होगी।

धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता लामबंद हैं। इस बाबत विधायक का पुतला जलाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की एवज में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने की खबर सामने आई है। शांतिप्रिय हिमाचल प्रदेश में प्रतिशोध की भावना से काम करने पर नेताओं को अंकुश लगाकर एकता का मार्ग अपनाना चाहिए। माना कि विधायक सुधीर शर्मा द्वारा प्रदेश मुखिया पर की गई टिप्पणी सही नहीं ठहराई जा सकती है। मगर आज हमें इस बात पर जरूर सोचना होगा कि सभ्य, हंसमुख, मिलनसार और मृदुभाषी विधायक के मुंह से ऐसे कटु शब्द आखिर निकले क्यों? जब कोई जनता द्वारा चुने हुए विधायक को सरगना का खिताब देकर संबोधित करेगा तो उस नेता के हल्के की जनता का अपमान कहलाएगा, जिसने उसे चुनकर विधानसभा में भेजा है।

सुख की सरकार अपने कांग्रेसी विधायकों के साथ तालमेल बैठाने में पिछड़ गई। नतीजन कांग्रेसी विधायकों ने धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा की अगुवाई में भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को अपना मत डाल दिया था। लोकतंत्र में मत अपनी इच्छानुसार डालने का मौलिक अधिकार हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को देता है। विधायक सुधीर शर्मा द्वारा भाजपा प्रत्याशी राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को अपना वोट डालना कांग्रेस नेताओं को पसंद नहीं आया। सुख सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक सुधीर शर्मा को बिका हुआ और सरगना का खिताब देने में कोई गुरेज नहीं किया था।

प्रदेश मुखिया द्वारा अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ विधायक को सरगना कहना बिल्कुल गलत था। सुख की सरकार ने विधायक सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा को समय रहते मान-सम्मान दिया होता तो आज अमर्यादित शब्द एक-दूसरे के खिलाफ मुंह से नहीं निकलते। विधायक सुधीर शर्मा ने इस अपमान की वजह से कांग्रेस सरकार से त्यागपत्र देकर भाजपा का दामन थामा। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के करीबी रहे विधायक सुधीर शर्मा के मन में यह टीस अवश्य चुभती होगी कि उन्हें प्रदेश मुखिया की वजह से कांग्रेस से वर्षों पुराना नाता तोड़ना पड़ा। सुधीर शर्मा धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उपचुनाव में विजय पताका फहराने में सफल रहे।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

भारतीय आईटी क्रांति के प्रमुख शिल्पकार

एन. आर. नारायण मूर्ति
जन्म : 20 अगस्त 1946

भारत के प्रमुख उद्योगपतियों और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तित्वों में **एन. आर. नारायण मूर्ति** का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका जन्म **20 अगस्त 1946** को कर्नाटक के शिदलघट्टा में हुआ था। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत, अनुशासन और दूरदृष्टि के बल पर भारतीय उद्योग जगत में अलग पहचान बनाई। नारायण मूर्ति ने न केवल एक सफल कंपनी खड़ी की बल्कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नारायण मूर्ति ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कर्नाटक में पूरी की और आगे चलकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक से विद्युत अभियांत्रिकी की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से परास्नातक की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विभिन्न संस्थानों में काम किया और तकनीकी क्षेत्र के साथ-साथ प्रबंधन और व्यवसाय की बारीकियों को समझा। उनके अनुभवों ने आगे चलकर उन्हें अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।

वर्ष 1981 में नारायण मूर्ति ने अपने छह सहयोगियों के साथ इंफोसिस की स्थापना की। उस समय भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आज की तरह विकसित नहीं था। सीमित संसाधनों और अनेक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कंपनी को पारदर्शिता, गुणवत्ता, ग्राहक सेवा और नैतिक व्यावसायिक मूल्यों पर आगे बढ़ाया। धीरे-धीरे इंफोसिस ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाई और भारत को वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में योगदान दिया।

नारायण मूर्ति की कार्यशैली में ईमानदारी, सादगी और संस्थागत अनुशासन को विशेष महत्व दिया जाता है। वे मानते रहे हैं कि किसी भी संगठन की दीर्घकालिक सफलता केवल आर्थिक लाभ से नहीं बल्कि मजबूत मूल्यों, बेहतर कार्य संस्कृति और समाज के प्रति जिम्मेदारी से तय होती है। उन्होंने कर्मचारियों के लिए पारदर्शी व्यवस्था और पेशेवर वातावरण विकसित करने पर जोर दिया।

वन विभाग की नाक तले बाहरी राज्यों में लकड़ी तस्करी, हिमाचल की हरियाली पर गंभीर खतरा

सत्यभान पुंडीर
स्वतंत्र लेखक

हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण राज्य है। यहां के घने जंगल, ऊंचे पहाड़, स्वच्छ नदियां, प्राकृतिक जलस्रोत, हरे-भरे वन और जैव विविधता प्रदेश की पहचान हैं। पर्यावरण संरक्षण बनाए रखने और हरित क्रांति को अर्थव्यवस्था का आधार बनाए जाने पर सुख सरकार काम कर रही है। लेकिन दूसरी ओर कुछेक वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हिमाचल प्रदेश की वन संपदा बाहरी राज्यों में किस तरह सरेआम बेची जा रही है, इसके कई मामले प्रकाश में आए हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वास्तव में राज्य सरकार प्रकृति संरक्षण के लिए गंभीरता से काम कर रही है, जबकि वन विभाग की नाक तले लकड़ी पड़ोसी राज्यों की प्लाई मिलों तक पहुंच रही है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के बावजूद अब गर्मियों में लगातार बढ़ते तापमान के कारण आम जनमानस का जीना मुहाल होता जा रहा है। गर्मी बढ़ने के अन्य कई कारण हो सकते हैं, लेकिन घटती पेड़ों की संख्या और पर्यावरणीय असंतुलन भी इसके महत्वपूर्ण कारण हैं।

जंगलों में पेड़ों की संख्या लगातार कम हो रही है और उनकी जगह खरपतवार तथा छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। किसानों द्वारा अपनी जमीनों से पेड़ कटवाने का क्रम भी कई स्थानों पर निरंतर जारी है, जिसका विपरीत प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है। आरोप है कि ठेकेदार पांच पेड़ काटने की अनुमति की आड़ में विभागीय अधिकारियों से मिलीभगत करके अनगिनत पेड़ों पर आरी चला रहे हैं। देवभूमि के जंगलों में वन काटुओं की कुल्हाड़ी लंबे समय से चल रही है। ऊपरी हिमाचल के जंगलों से काटी गई लकड़ी खड्डों, नालों और नदियों में बहती हुई बांधों में एकत्रित होती रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की वन संपदा पर कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है। बांधों में एकत्रित हुई लकड़ी राज्य सरकार ने किसे और कितने दामों में बेची, इसका पूरा आंकड़ा सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।

नूरपुर जिला पुलिस की सीआईए टीम ने सतर्कता बरतते हुए सात वाहनों को अवैध लकड़ी सहित अपने कब्जे में लिया है। इसी तरह वन विभाग द्वारा भी अवैध लकड़ी से भरी गाड़ियों को पकड़े जाने की कार्रवाई सामने आई है। जिला ऊना में दस गाड़ियां अवैध लकड़ी से भरी हुई पकड़े जाने तथा कंडवाल में एक ट्रक के पकड़े जाने की घटनाएं बताती हैं कि लकड़ी की अवैध आवाजाही पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं है। गरीब व्यक्ति अपनी जमीन से एक पेड़ तक वन और राजस्व विभाग की अनुमति के बिना नहीं काट सकता। सुख की सरकार ने गत वर्ष कुछेक पेड़ों को छोड़कर पेड़ कटान पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद यदि हिमाचल प्रदेश से ट्रकों में भरकर पड़ोसी राज्यों में लकड़ी की तस्करी की जा रही है तो यह कानून व्यवस्था और विभागीय निगरानी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

बाहरी राज्यों में लकड़ी बेचने की प्रक्रिया भी सामान्य नहीं है। वन विभाग के अधिकारी इसके लिए पंजीकृत ठेकेदार को परमिट सौंपते हैं। परमिट पर वन रक्षक से लेकर वनमंडल अधिकारी तक संस्तुति करते हैं। वनमंडल अधिकारी कार्यालय से पंजीकृत होने के बाद परमिट की प्रतियां पुलिस चैक नाकों पर भेजी जाती हैं। ऐसी स्थिति में यदि अवैध लकड़ी से भरे वाहन पुलिस और वन विभाग की निगरानी व्यवस्था को पार कर दूसरे राज्यों तक पहुंच रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक है। सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि अवैध लकड़ी कहां से काटी गई, किसने काटी, किसके संरक्षण में परिवहन हुआ और इसे कहां बेचा गया। दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

हिमाचल प्रदेश में सड़क विस्तारीकरण के चलते भी अनगिनत पेड़ों की बलि दी गई है। कई स्थानों पर जेसीबी मशीनों से पेड़ों को उखाड़कर सड़क निर्माण किया गया है। सड़कें विकास के लिए जरूरी हैं, लेकिन विकास के नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध विनाश किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता। पेड़ों की जड़ें पहाड़ों की मिट्टी को बांधकर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब बड़े पैमाने पर पेड़ों को काट दिया जाता है तो पहाड़ों की प्राकृतिक पकड़ कमजोर होती है और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से जनता को भारी जान-माल का नुकसान हुआ है। सड़कें, पुल, पुलियां, डंगे, मकान, भवन, रेस्टोरेंट और वाहन तक जमींदोज हुए हैं। ऐसे हालात में सरकार और प्रशासन को यह गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इनमें से कितनी घटनाएं प्राकृतिक कारणों से हुईं और कितनी मानव गतिविधियों के कारण बढ़ीं।

देवभूमि का अस्तित्व उसके जंगलों से है। हिम और अंचल से मिलकर हिमाचल प्रदेश नाम बना है और पहाड़ इसकी पहचान हैं। जंगलों का अस्तित्व मिटने से पहाड़ की जनता को सबसे अधिक इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा भी पहाड़ी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मिला है। यदि लगातार पहाड़ों और जंगलों का अस्तित्व कमजोर होता गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक पहचान को बचाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सरकार को विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

न्यूज ब्रीफ

प्रदेश के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट पूर्वांचल में सबसे अधिक वर्षा की संभावना

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मानसून बुधवार को सक्रिय है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दक्षिण-पूर्वी जिलों में कहीं-कहीं 21 सेंटीमीटर से अधिक बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। राजधानी लखनऊ में बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, उत्तरी झारखंड और दक्षिण-पश्चिमी बिहार के ऊपर बना अवदाब पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वी यूपी में अगले 24 घंटे भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है। लखनऊ में पिछले तीन-चार दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है। इससे निचले इलाकों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।

जिलाधिकारी ने सीएचसी सलेमपुर का औचक निरीक्षण किया,कई चिकित्सक अनुपस्थित मिले

एजेंसी, देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ चिकित्सक ड्यूटी से अनुपस्थित मिले, जबकि कुछ चिकित्सक बिना एप्रन के मरीजों का उपचार करते पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबंधित चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। डीएम ने सीएचसी के एमसीएच विंग का निरीक्षण कर भर्ती गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने हाल में हुए प्रसव, नवजात बच्चों और माताओं के टीकाकरण कार्ड भी जांचे। आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और एएनएम को गर्भवती महिलाओं व बच्चों की नियमित जांच और टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार मिलना चाहिए।

नोएडा में दो आत्महत्याओं से सनसनी, दो लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

एजेंसी, नोएडा। नोएडा जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दो युवकों ने मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या कर ली, जबकि दो अन्य लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, दादरी थाना क्षेत्र के ओमिक्रान प्रथम निवासी 17 वर्षीय दिव्यांश ठाकुर ने मंगलवार रात घर में फंदा लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, सेक्टर-39 थाना क्षेत्र की सदरपुर कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय अनुज प्रताप ने भी मानसिक तनाव के चलते घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिसरख थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय मनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। एक अन्य व्यक्ति की भी मौत की सूचना है। पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है।

बाराबंकी में पुरानी रंजिश में चौकीदार की पीट-पीटकर हत्या, पांच पर मुकदमा

एजेंसी, बाराबंकी। रामनगर कोतवाली क्षेत्र के भरसवां गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने थाना रामनगर में तैनात चौकीदार राजेश यादव (45) की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल राजेश की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बुधवार को मृतक के बेटे रामू यादव की तहरीर पर पुलिस ने पांच आरोपितों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के अनुसार, राजेश सोमवार शाम ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के पास शुभम, बाबू, श्रवण, कुलदीप और राम कैलाश ने उन्हें रोककर हमला कर दिया। सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है।

जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी का छापा, जमीन विवाद से कार्रवाई तक की पूरी कहानी सामने आई

38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश से ईडी छापे तक, जौहर यूनिवर्सिटी का सफर

एजेंसी, रामपुर

आजम खान की ड्रीम प्रोजेक्ट कही जाने वाली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद इसके निर्माण, जमीन से जुड़े विवाद और अब तक हुई सरकारी कार्रवाइयों की चर्चा तेज हो गई है। स्थापना के बाद से ही यह विश्वविद्यालय कई तरह के विवादों और जांच के कारण चर्चा में रहा है।

जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुई थी। इसे आजम खान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में देखा गया। विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए आधुनिक संस्थान तैयार करना था। समय के साथ परिसर का विस्तार हुआ और यहां कई भवनों तथा अन्य सुविधाओं का निर्माण किया गया। हालांकि, विश्वविद्यालय के विस्तार के साथ ही जमीन से जुड़े विवाद भी सामने आते रहे। आरोप लगाए गए कि विश्वविद्यालय के लिए जमीन हासिल करने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया।

कुछ मामलों में जमीन पर अतिक्रमण और सरकारी भूमि से जुड़े आरोप भी सामने आए। इन आरोपों के आधार पर प्रशासन की ओर से अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई की गई। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई का एक बड़ा मामला 38 भवनों से संबंधित रहा। संबंधित विभाग की ओर से इन भवनों को लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि, बाद में कमिश्नर कोर्ट की ओर से इस आदेश पर रोक लगा दी गई।

इसके बाद इन भवनों को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट होने तक कार्रवाई पर विराम लग गया। यूनिवर्सिटी पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं। इन्हीं मामलों के बीच प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई ने मामले को फिर चर्चा में ला दिया है। ईडी की जांच और छापेमारी के बाद यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय लेनदेन तथा अन्य दस्तावेजों की जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, जांच एजेंसी की कार्रवाई का अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

जौहर यूनिवर्सिटी का मामला केवल एक शिक्षण संस्थान से जुड़े विवाद तक सीमित नहीं रहा। इसके साथ आजम खान की राजनीतिक भूमिका, जमीन से जुड़े मामले और प्रशासनिक कार्रवाई भी जुड़ी रही हैं। यही वजह है कि विश्वविद्यालय से जुड़ी हर नई कार्रवाई राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बन जाती है। अब ईडी की छापेमारी के बाद जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े पुराने विवाद एक बार फिर सामने आ गए हैं। जांच एजेंसियां जिन पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। वहीं, 38 भवनों के मामले में कमिश्नर कोर्ट की रोक के कारण उस कार्रवाई की कानूनी स्थिति भी महत्वपूर्ण बनी हुई है।

बसपा की चुनावी रणनीति में सतीश मिश्र की बढ़ी भूमिका, मायावती ने दी जिम्मेदारी

एजेंसी, लखनऊ

विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सतीश मिश्र की बढ़ी भूमिका।

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चन्द्र मिश्र को चुनाव आयोग से जुड़े कार्यों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। अब तक पार्टी के कानूनी और मीडिया संबंधी काम देख रहे सतीश मिश्र आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, तैयारियों और प्रबंधन में भी अहम भूमिका निभाएंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव-2027 को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनके मुताबिक, उम्मीदवारों के चयन को लेकर विरोधी दलों में बेचैनी दिखाई दे रही है। मायावती ने कहा कि चुनावी तैयारियों के बीच सत्ताधारी भाजपा समेत अन्य दलों में बदलाव होना स्वाभाविक है। मायावती ने कहा कि बसपा सर्वसमाज को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने विशेष रूप से ब्राह्मण समाज का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी की ओर से उन्हें भी उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने इसे 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तैयारी से जोड़ते हुए कहा कि इससे विरोधी दलों में चर्चा और चिंता बढ़ी है। बसपा प्रमुख ने पार्टी समर्थकों और बहुजन समाज के लोगों से विरोधी दलों के कथित हथकंडों को लेकर सजग और सतर्क रहने की अपील की।

उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ उम्मीदवार चयन और चुनाव प्रबंधन पर भी लगातार काम कर रही है। सतीश मिश्र को नई जिम्मेदारी दिए जाने को इसी चुनावी तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती के इस फैसले से चुनावी तैयारियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सतीश मिश्र अब चुनाव आयोग से जुड़े मामलों के साथ उम्मीदवार चयन, रणनीति और चुनाव प्रबंधन में भी अहम भूमिका निभाएंगे।

बहराइच में 15 .07 किलोग्राम गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, तलाश रहा था ग्राहक

एजेंसी, बहराइच

मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आरोपी गिरफ्तार हुआ।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दरगाह शरीफ पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15.07 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया।

गांजा 15 पॉलीथिन के पैकेटों में रखा हुआ था। पुलिस के अनुसार, 18 अगस्त को थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली गई।

तलाशी में उसके पास से 15 पॉलीथिन पैकेट मिले, जिनमें कुल 15.07 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी की पहचान आशीष कुमार पुत्र स्वर्गीय कुंवर साहब, निवासी विशेश्वरगंज बाजार, थाना विशेश्वरगंज, बहराइच के रूप में हुई।

पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी गौ-तस्कर घायल, गिरफ्तार

एजेंसी, मीरजापुर। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में बुधवार को पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी वांछित गो-तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपित के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत सामान्य है। लालगंज थाना प्रभारी वेद प्रकाश पाण्डेय ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 25 हजार रुपये का इनामी वांछित गो-तस्कर मोटरसाइकिल से नैड़ी कठारी की ओर से गड़बड़ा धाम रोड पर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पुलिया के पास घेराबंदी की और उसे रोकने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपित ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा।

पीएम मोदी बने बुनकरों की आवाज हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील

एजेंसी, बाराबंकी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील का बुनकरों पर सकारात्मक असर दिखाई देने लगा है। सात अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार किए गए वस्त्र और अन्य हैंडलूम उत्पाद खरीदने की अपील की थी।

इसके बाद बाराबंकी के बुनकरों में भी कारोबार बढ़ने की उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में बुनकरों के हाथों से तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के गमछे और अन्य वस्त्रों को प्रदर्शित किया। उन्होंने लोगों से अपनी पसंद के हैंडलूम उत्पाद खरीदने तथा उनसे जुड़े वीडियो बनाकर इंटरनेट पर साझा करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री की इस पहल से हथकरघा उत्पादों को देशभर में पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

बाराबंकी में 'एक जिला एक उत्पाद' के तहत तैयार होने वाले स्टोल और अन्य कपड़ों की मांग बढ़ने की संभावना है। बुनकर नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील से स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। उनका मानना है कि यदि लोग नियमित रूप से स्थानीय हैंडलूम उत्पाद खरीदते हैं तो बुनकर परिवारों की आय में भी वृद्धि हो सकती है।

एआई की जांच ने छीना आवास का हक, 11 हजार से ज्यादा आवेदन बाहर

एजेंसी, अलीगढ़

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर देने की योजना में तकनीकी जांच के कारण कई आवेदकों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। अलीगढ़ जिले में एआई जांच और सत्यापन के बाद 11,482 आवेदकों के नाम पात्रता सूची से बाहर हो गए। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनके मकान जर्जर स्थिति में हैं और उन्हें पक्के घर की वास्तविक जरूरत है।

धनीपुर ब्लाक की भटौला पंचायत के शेखूपुर निवासी विजय कुमार का मामला इसका उदाहरण है। उनका मकान मिट्टी और ईंटों से बना हुआ है। दीवारें कमजोर हैं और बरसात के दौरान परिवार को घर की छत और दीवारों को लेकर चिंता बनी रहती है। परिवार को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए सहायता मिलेगी। आवेदकों के मकानों की तस्वीरों के आधार पर एआई तकनीक से जांच की गई। आरोप है कि तस्वीर में दिखाई दे रही ईंटों और दीवारों को देखकर जर्जर मकानों को भी पक्का मकान मान लिया गया। इसके चलते कई जरूरतमंद परिवार पात्रता सूची से बाहर हो गए।

स्थानीय स्तर पर ऐसे मामलों को लेकर आवेदकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि केवल तस्वीर के आधार पर मकान की स्थिति का सही आकलन नहीं किया जा सकता। कई मकान बाहर से ईंटों के बने दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी छत, दीवारें और अंदरूनी संरचना बेहद कमजोर होती हैं। अब प्रभावित परिवारों को उम्मीद है कि प्रशासन दोबारा भौतिक सत्यापन कराकर वास्तविक स्थिति सामने लाएगा।

हमीरपुर में बच्चों का अनोखा आंदोलन, स्कूल की सड़क बनवाने के लिए किया प्रदर्शन

एजेंसी, हमीरपुर

हमीरपुर में स्कूल की खराब सड़क को लेकर बच्चों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आवाज उठाई।

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में स्कूल की खराब सड़क को लेकर बच्चों ने अपनी आवाज बुलंद की। स्कूल आने-जाने में हो रही परेशानी को देखते हुए बच्चे सड़क निर्माण की मांग लेकर कलेक्ट्रेट की ओर निकल पड़े। बच्चों के इस प्रदर्शन ने स्थानीय प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा। बताया गया कि बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल की सड़क बनवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचने के लिए निकले थे।

पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। कुछ बच्चे गलियों के रास्ते आगे बढ़ते रहे। बाद में बच्चों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई और स्कूल तक जाने वाली सड़क जल्द बनवाने की मांग की। बच्चों का कहना है कि खराब सड़क के कारण उन्हें रोजाना स्कूल आने-जाने में परेशानी होती है। बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है। सड़क पर कीचड़ और गड्ढों के कारण बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल के दिनों में बच्चों और युवाओं की ओर से अपनी बुनियादी सुविधाओं को लेकर आवाज उठाने के मामले सामने आए हैं। फतेहपुर से शुरू हुई स्कूल में सुविधाओं की मांग अब हमीरपुर तक पहुंच गई है।

बच्चों की मांग है कि प्रशासन उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए सड़क निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करे। वहीं, अधिकारियों ने उनकी समस्या सुनकर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। बच्चों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण शुरू कराने की मांग की।

ससुराल पहुंचे युवक ने नहर में लगाई छलांग, तलाश के बाद बरामद हुआ शव

एजेंसी, अमेठी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र में नागपंचमी पर्व पर ससुराल पहुंचे युवक ने गोमिया नहर में छलांग लगा दी। घटना के बाद परिवार और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने लगातार तलाश अभियान चलाया। बुधवार को युवक का शव नहर से बरामद कर लिया गया। जानकारी के अनुसार, शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव निवासी सीताराम (35) अहमदाबाद में रहता था। नागपंचमी के अवसर पर वह मोहनगंज थाना क्षेत्र के खानापुर चपरा गांव स्थित पूरे तिवारी में अपनी ससुराल आया था। ग्रामीणों के मुताबिक, मंगलवार को ससुराल में किसी मामूली बात को लेकर उसकी नाराजगी हो गई। इसके बाद युवक अचानक घर से बाहर निकला और दौड़ते हुए ससुराल के पास से बह रही गोमिया नहर में छलांग लगा दी।

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और युवक की तलाश शुरू कराई। नहर में पानी अधिक होने के कारण शुरुआती प्रयासों में युवक का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ टीम और स्थानीय गोताखोरों को तलाश अभियान में लगाया। लगातार कई घंटों की मशक्कत के बाद बुधवार को युवक का शव बरामद कर लिया गया। मोहनगंज थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। ग्रामीणों की मदद से तलाश शुरू की गई, बाद में एसडीआरएफ और गोताखोरों को भी बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

बेहतर भविष्य की तलाश में निकले युवा, खाड़ी देशों में मौत का शिकार

एजेंसी, गोरखपुर

पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खाड़ी देशों में रोजगार बेहतर भविष्य और परिवार की आर्थिक स्थिति बदलने का जरिया माना जाता है। घर की जरूरतें पूरी करने, बच्चों की पढ़ाई, बहन की शादी और बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के सपने लेकर युवा विदेश जाते हैं। परिवार भी उम्मीद करता है कि परदेस की कमाई से उनकी परेशानियां कम होंगी।

लेकिन कई परिवारों के लिए विदेश जाने का यह सपना दर्दनाक हादसे में बदल जाता है। एजेंटों की धोखाधड़ी, नौकरी से जुड़े झूठे वादे, कठिन कामकाजी परिस्थितियां और दुर्घटनाएं युवाओं के जीवन पर भारी पड़ रही हैं। जिस बेटे को परिवार खुशहाल भविष्य की उम्मीद के साथ विदा करता है, कई बार उसकी मौत की खबर ही वापस आती है। खाड़ी देशों में काम करने वाले युवाओं को कई बार बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने या दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों से परिवारों की उम्मीदें टूट जाती हैं। कुछ मामलों में विदेश भेजने वाले एजेंट भी युवाओं और उनके परिजनों को नौकरी, वेतन और सुविधाओं को लेकर गुमराह करते हैं।

सबसे बड़ी परेशानी तब होती है, जब मृतक का शव भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू होती है। कागजी कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया और परिवहन का खर्च परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। आर्थिक मजबूरी से विदेश गए युवाओं की मौत के बाद उनके परिवारों पर भावनात्मक दुख के साथ आर्थिक संकट भी बढ़ जाता है। पूर्वी यूपी में ऐसी घटनाएं विदेश रोजगार से जुड़े जोखिमों को सामने ला रही हैं।

भरोसा | योगी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उद्योगों के लिए प्रदेश में सरल और अनुकूल माहौल बनाया जाएगा

यूपी-जापान निवेश बैठक में योगी ने उद्योग जगत को दिया सहयोग का भरोसा

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026 के दौरान प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों और कंपनियों को सरकार की ओर से हर स्तर पर पूरा सहयोग दिया जाएगा। निवेशकों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए सरकार प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में व्यापक बदलाव हुआ है। कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, संपर्क व्यवस्था, औद्योगिक वातावरण और निवेश के अनुकूल नीतियों में सुधार के कारण प्रदेश देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में उभरकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को उद्योग और कारोबार के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाना है। योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों की ओर से बैठक के दौरान दिए गए सुझावों और अपेक्षाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों के सुझावों को गंभीरता से ले रही है। व्यावहारिक स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

सरकार की कोशिश है कि निवेश की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो, ताकि उद्यमी बिना किसी बाधा के अपने कारोबार का विस्तार कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा मानव संसाधन उपलब्ध है। सरकार युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर प्रदान कर रही है। इससे प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों को प्रशिक्षित और सक्षम कर्मचारी उपलब्ध होंगे।

उन्होंने कहा कि बदलते औद्योगिक परिदृश्य को देखते हुए सरकार कौशल विकास के साथ बुनियादी ढांचे और संपर्क व्यवस्था को भी लगातार मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाला निवेश कंपनियों के लिए लाभकारी साबित होगा। सरकार अपनी नीतियों के दायरे में उद्यमियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी। निवेशकों को बेहतर माहौल देने के लिए विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया जा रहा है। सरकार की पूरी टीम निवेशकों के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार केवल घोषणाएं करने में विश्वास नहीं करती, बल्कि जो कहती है उसे जमीन पर उतारने का प्रयास करती है। पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में हुए बदलाव को निवेशक स्वयं देख सकते हैं। बेहतर कानून-व्यवस्था, मजबूत बुनियादी ढांचा, बेहतर संपर्क व्यवस्था और उद्योगों के लिए तैयार नीतियों ने प्रदेश की नई तस्वीर बनाई है।मुख्यमंत्री ने यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट को औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से सरकार को उद्योग जगत की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने का अवसर मिलता है। वहीं निवेशकों को उत्तर प्रदेश में उपलब्ध संभावनाओं, सुविधाओं और नीतियों की जानकारी मिलती है।

भारत-नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया तस्कर, 583 ग्राम चरस बरामद

एजेंसी, बहराइच

भारत-नेपाल सीमा पर 583 ग्राम चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार।

बहराइच में पुलिस और एसएसबी ने चरस तस्करी का किया भंडाफोड़।

भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बहराइच पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। मोतीपुर पुलिस और 59वीं वाहिनी एसएसबी की टीम ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 583 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने मौके से एक प्लेटिना मोटरसाइकिल भी बरामद की है।

पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में जिले में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 19 अगस्त को मोतीपुर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रही थी। टीम बलईगांव पुलिया के पास संदिग्ध लोगों और वाहनों की जांच कर रही थी।

इसी दौरान एक युवक पुलिस टीम को देखकर संदिग्ध गतिविधियां करता दिखाई दिया। संदेह होने पर टीम ने उसे रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से 583 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने उसकी पहचान शाहरूख खान उर्फ लल्लू, उम्र 31 वर्ष, निवासी मेढ़किया पोंडा, थाना मोतीपुर, बहराइच के रूप में की है। पुलिस ने बरामद चरस और मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना मोतीपुर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा संख्या 362/2026 दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत कार्रवाई की गई है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया गया।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले में आगे की जांच की जा रही है। जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि आरोपी के पास मादक पदार्थ कहां से आया था और इसे कहां पहुंचाया जाना था। सीमा क्षेत्र में तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने के लिए भी पूछताछ की जा रही है। संयुक्त कार्रवाई में मोतीपुर पुलिस और 59वीं वाहिनी एसएसबी के अधिकारी एवं जवान शामिल रहे।

जींद में 12 करोड़ की हेरोइन बरामद सीआईए ने दो तस्करों को दबोचा

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पिपलथा निवासी बलजीत और लवप्रीत के रूप में हुई

भारतेन्दु संवाददाता, जींद

नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत जींद सीआईए पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 किलो 600 ग्राम हेरोइन बरामद की है। बरामद नशीले पदार्थ की कीमत करीब 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार 18 अगस्त को सीआईए जींद की टीम गांव उझाना रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम को दो युवक संदिग्ध परिस्थितियों में आते दिखाई दिए। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों को रोककर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम पिपलथा निवासी बलजीत और लवप्रीत बताया।

पुलिस टीम ने दोनों युवकों की तलाशी ली तो उनके कब्जे से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई। वजन करने पर नशीले पदार्थ की मात्रा 7 किलो 600 ग्राम निकली। इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन मिलने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बरामद हेरोइन की अनुमानित कीमत करीब 12 करोड़ रुपये बताई है।

इतनी बड़ी खेप की बरामदगी के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी हेरोइन कहां से लेकर आए थे और इसे आगे कहां पहुंचाना था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अब जांच का मुख्य फोकस नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क तक पहुंचने पर है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके संपर्कों और नशीले पदार्थ की आपूर्ति से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

जांच एजेंसी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों आरोपी पहले भी किसी नशीले पदार्थ की तस्करी में शामिल रहे हैं या नहीं। उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा सकती है। इसके अलावा पुलिस बरामद हेरोइन की खेप के स्रोत और संभावित खरीदारों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार गश्त और संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है।

करनाल एनकाउंटर की अब स्टेट क्राइम ब्रांच करेगी जांच, सीएम सैनी ने दिए आदेश

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने करनाल में 7 अगस्त को हुए एनकाउंटर की जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश के बाद पुलिस ने मधुबन थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 282 को जिला पुलिस से क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित कर दिया है। मामले की जांच एडीजीपी कानून-व्यवस्था संजय कुमार के नेतृत्व में की जाएगी।

यह एफआईआर आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। आदेश के अनुसार हरियाणा पुलिस के आईजी क्राइम एक अधिकारी नियुक्त करेंगे। संबंधित अधिकारी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद करनाल पुलिस से केस की फाइल और सभी संबंधित रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेंगे। करनाल के पुलिस अधीक्षक को भी जांच अधिकारी को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला करनाल एनकाउंटर को लेकर रोर समुदाय में बढ़ती नाराजगी के बीच आया है। 7 अगस्त को हुई मुठभेड़ में हर्ष और मटरवा खेड़ी गांव के बीरबल के मारे जाने के बाद समुदाय के लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। दोनों को सदर बाजार के वीरू वाल्मीकि की कथित हत्या के मामले में हुई पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था।

रोर समुदाय के प्रतिनिधियों ने 12 अगस्त को कुरुक्षेत्र में बैठक कर सीबीआई जांच, एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और करनाल विधायक जगमोहन आनंद के इस्तीफे की मांग की थी। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं। सरकार से ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर समुदाय ने 24 अगस्त को करनाल में महापंचायत का ऐलान किया था। इसके बाद सरकार ने देर रात मामले की जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपने का फैसला लिया।

न्यूज ब्रीफ

सोनीपत में रिटायर्ड जेई पर रॉड-लाठी से हमला, लाइव वीडियो आया सामने

भारतेन्दु संवाददाता, सोनीपत। सेक्टर-12 में सोमवार दोपहर घर के बाहर सेवानिवृत्त एचएसवीपी जेई पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में जेई घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का कथित लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग उनके साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि जेई ने विभागीय कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की थी। इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। मामले में अधिकारियों और ठेकेदार पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस वीडियो और शिकायत के आधार पर हमलावरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रामपाल को आर्य समाज का खुला चैलेंज उमेद शर्मा बोले- शास्त्रार्थ के लिए तैयार

भारतेन्दु संवाददाता, रोहतक। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के उपप्रधान उमेद शर्मा ने रामपाल दास को खुली बहस और शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आर्य समाज रामपाल के साथ शास्त्रार्थ के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रामपाल चाहें तो अपने आश्रम में लाइव बहस आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए एक समिति गठित की जाए, जो बहस के तथ्यों और परिणाम का निर्णय करे। उमेद शर्मा ने कहा कि आर्य समाज लंबे समय से पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रामपाल भगवान राम, भगवान कृष्ण और आर्य समाज के गुरुओं को लेकर आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बयानों से आर्य समाज में नाराजगी है और संगठन वैदिक संस्कृति के मुद्दे पर मजबूती से अपना पक्ष रखेगा। उन्होंने इसे निर्णायक लड़ाई बताया।

शादी के लिए दबाव और पैसों का विवाद युवक की मौत से उठे सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर। राजकरण आत्महत्या मामले में उसकी बहन खुशबू ने रिश्ते को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। खुशबू के अनुसार, राजकरण की गर्लफ्रेंड उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। जब राजकरण शादी के लिए तैयार हुआ तो मामले में उसकी गर्लफ्रेंड के पूर्व प्रेमी की भी एंट्री हो गई। बहन का आरोप है कि गर्लफ्रेंड अपने एक्स-बॉयफ्रेंड को पैसे देती थी, जिससे राजकरण परेशान रहने लगा था। परिवार के मुताबिक, शादी को लेकर दोनों के बीच लगातार बातचीत और विवाद चल रहा था। इसी दौरान राजकरण मानसिक तनाव में आ गया। घटना से पहले उसने अपनी मां को फोन किया और कहा कि वह जिंदगी से हार गया है।

2047 तक विकसित भारत के संकल्प में महिलाओं की होगी मुख्य भूमिका : रिचा पाहवा

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष रिचा पाहवा ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बुधवार को फतेहाबाद स्थित भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा, अधिकारों और आत्मरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाएगा। इसमें हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी का सहयोग लिया जाएगा। रिचा पाहवा ने कहा कि महिला संगठन को अधिक मजबूत और सक्रिय बनाना उनका प्रमुख उद्देश्य है।

फतेहाबाद के भूना में खेल सुविधाओं को मिलेगा बढ़ावा, 7 करोड़ से बनेगा स्टेडियम

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। फतेहाबाद के भूना स्थित राजकीय महाविद्यालय परिसर में एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर के सामाजिक सरोकार प्रोजेक्ट के तहत स्टेडियम निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए करीब 7 करोड़ 30 हजार रुपये का टेंडर जारी किया गया है।

नगरपालिका चेयरपर्सन अर्पणा पसरीजा और प्रतिनिधि पंकज पसरीजा ने बताया कि भूना में लंबे समय से फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए उचित स्टेडियम का अभाव था। इस समस्या को देखते हुए नगरपालिका की ओर से प्रस्ताव पारित कर सामाजिक सरोकार प्रोजेक्ट के अधिकारियों के समक्ष स्टेडियम निर्माण की मांग रखी गई थी। सामाजिक सरोकार प्रोजेक्ट गोरखपुर के चेयरमैन अनिल जाखड़ ने बताया कि स्टेडियम निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम से खिलाड़ियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं।

टेंडर करीब 10 दिन में खोला जाएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग तीन महीने में निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ होने की उम्मीद है। परियोजना पर सात करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। स्टेडियम बनने से भूना और आसपास के क्षेत्र के फुटबॉल खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

पलवल में कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, पलवल। पलवल में नेशनल हाईवे-19 पर हुए सड़क हादसे में 25 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। हादसा सत्य साईं अस्पताल के पास हुआ। मृतक की पहचान इस्लामाबाद, पलवल निवासी सौरभ के रूप में हुई है। वह एक निजी कंपनी में काम करता था और ड्यूटी खत्म करने के बाद बाइक से घर लौट रहा था। जानकारी के अनुसार, सौरभ अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर घर जा रहा था। इसी दौरान सत्य साईं अस्पताल के पास एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने सौरभ को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके साथी का उपचार चल रहा है।

हरियाणा में अग्निवीरों को बड़ा तोहफा, पुलिस समेत छह सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने सेना से सेवा पूरी कर लौटे पूर्व अग्निवीरों के लिए नई आरक्षण नीति जारी कर दी है। इस नीति के तहत अग्निवीरों को विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। पुलिस भर्ती समेत छह विशेष पदों पर उन्हें 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। वहीं, द्वितीय श्रेणी के पदों पर एक प्रतिशत और तृतीय श्रेणी के पदों पर पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नई व्यवस्था एक सितंबर से लागू होगी।

सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड, वन्यजीव गार्ड और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर के पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। इससे सेना से लौटने वाले युवाओं को

हरियाणा में सरकारी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

नीति के तहत सामान्य पात्रता परीक्षा में भी पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लाभ मिलेगा। पुलिस भर्ती में उन्हें शारीरिक जांच परीक्षण से छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि, तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए उन्हें संबंधित विभाग की लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। यानी आरक्षण का लाभ मिलने के बावजूद निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अन्य आवश्यक चरणों को पूरा करना जरूरी रहेगा। मानव संसाधन विभाग ने आरक्षण नीति में संशोधन करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश पूर्व अग्निवीरों की सीधी भर्ती में आरक्षण देने से संबंधित सरकार के 20 अगस्त 2025 और 20 जुलाई 2026 के आदेशों को रद करते हुए जारी किया गया है।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के उन युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो अग्निवीर योजना के तहत सेना में सेवा देने के बाद वापस लौटेंगे। खास तौर पर पुलिस, वन विभाग, जेल और अग्निशमन विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे पूर्व अग्निवीरों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई नीति लागू होने के बाद संबंधित विभागों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित पदों का प्रावधान किया जाएगा।

हरियाणा के स्कूल में छात्राओं से अभद्रता का आरोप, शिकायत के बाद शिक्षक का तबादला

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

टोहाना के पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में केमिस्ट्री शिक्षक पर छात्राओं से अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप लगे हैं। 30 से अधिक छात्राओं ने शिक्षक अनूप कुमार के खिलाफ शिकायत की है। शिकायत सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक का तबादला इंदाछोई कर दिया। हालांकि, शिक्षक ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को साजिश बताया है।

एसडीएम के निरीक्षण के दौरान छात्राओं ने शिक्षक के व्यवहार की शिकायत की।

मामला 11 अगस्त को सामने आया। टोहाना के एसडीएम आकाश शर्मा स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने स्कूल के पुस्तकालय, प्रयोगशाला और शिकायत पेटिका की जांच की। इसी दौरान छात्राओं ने शिक्षक के व्यवहार को लेकर एसडीएम के सामने अपनी शिकायत रखी। इसके बाद छात्राओं से लिखित शिकायत भी ली गई। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक कक्षा में उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे और कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियां करते थे। शिकायत में शिक्षक पर छात्राओं को अपमानजनक शब्द कहने के आरोप भी लगाए गए हैं।

अधिकतर शिकायतकर्ता छात्राएं दसवीं कक्षा की बताई जा रही हैं। छात्राओं ने अधिकारियों से शिक्षक के व्यवहार की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की थी। मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने भी शिक्षक की कक्षाएं दूसरे अध्यापकों को सौंप दीं। वहीं, स्कूल कमेटी ने शिकायत की जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी है। इसके बाद शिक्षक का तबादला इंदाछोई कर दिया गया। शिक्षक अनूप कुमार ने छात्राओं की ओर से लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

अधिकारियों की कार्रवाई के बाद अब मामले में विभागीय स्तर पर भी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। स्कूल में छात्राओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर प्रशासन ने शिकायत को गंभीरता से लिया है। फिलहाल शिक्षक का तबादला किया जा चुका है और स्कूल प्रबंधन ने संबंधित कक्षाओं की पढ़ाई दूसरे शिक्षकों के माध्यम से जारी रखने की व्यवस्था की है। इस मामले के सामने आने के बाद स्कूलों में छात्राओं के साथ शिक्षकों के व्यवहार और शिकायतों के निपटारे को लेकर भी सवाल उठे हैं।

सिरसा में किसान आंदोलन तेज टावर लाइन उखाड़ने का ऐलान

भारतेन्दु संवाददाता, सिरसा

सिरसा जिले के वैदवाला गांव में बिजली टावर के लिए अधिकृत की गई जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। किसान संगठनों की ओर से प्रशासन को दिया गया अल्टीमेटम अब खत्म हो गया है। किसानों ने बुधवार, 19 अगस्त को खेतों में लगी टावर लाइन उखाड़ने की चेतावनी दी है। इसके चलते गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।

किसान संगठनों का कहना है कि बिजली टावरों के लिए जमीन इस्तेमाल किए जाने के बावजूद उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है। इसी मांग को लेकर किसान काफी समय से धरना दे रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से मामले का समाधान करने और मुआवजे को लेकर उचित निर्णय लेने की मांग की थी। निर्धारित समय में समाधान नहीं होने पर अब उन्होंने टावर लाइन उखाड़ने का निर्णय लिया है। किसानों के ऐलान के अनुसार दोपहर करीब दो बजे ग्रामीण और किसान खेतों की ओर कूच करेंगे।

इस दौरान टावर लाइन हटाने की कोशिश की जा सकती है। आंदोलन को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गए हैं। पुलिस ने गांव में पड़ाव डाल दिया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

प्रशासन की ओर से किसानों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। वहीं, किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक मुआवजे से जुड़ा विवाद हल नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वैदवाला में आज होने वाले किसानों के कूच को लेकर प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभाला जाए। पुलिस की मौजूदगी बढ़ने से गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अब सभी की नजर दोपहर दो बजे होने वाले किसानों के प्रदर्शन पर है।

अंबाला के बाद पूरे हरियाणा में फर्जी वाहन रजिस्ट्रेशन की जांच, एसीबी ने संभाला मोर्चा

भारतेन्दु संवाददाता, अंबाला

अंबाला कैंट एसडीएम कार्यालय में फर्जी पतों के आधार पर दूसरे राज्यों के वाहनों के पंजीकरण का मामला सामने आने के बाद अब इसकी जांच पूरे हरियाणा में शुरू कर दी गई है। परिवहन मंत्री अनिल विज के निर्देश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने प्रदेश के सभी एसडीएम कार्यालयों में वाहन पंजीकरण से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू कर दी है। इस जांच के दायरे में विशेष रूप से दूसरे राज्यों से आने वाले भारी व्यावसायिक वाहनों के पंजीकरण को शामिल किया गया है।

जानकारी के अनुसार, अंबाला कैंट में ऐसे वाहनों के पंजीकरण का मामला सामने आया था, जिनके लिए कथित तौर पर फर्जी या संदिग्ध पतों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। जांच में क्रेन, जेसीबी, ट्रैक्टर और अन्य भारी वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को खंगाला जा रहा है। अधिकारियों द्वारा यह देखा जा

हरियाणा में वाहन पंजीकरण रिकॉर्ड खंगालते एसीबी के अधिकारी।

रहा है कि वाहन मालिकों की ओर से दिए गए पते वास्तविक हैं या नहीं और पंजीकरण के दौरान निर्धारित नियमों का पालन किया गया है या नहीं।

दैनिक जागरण ने अंबाला में सामने आए इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। खबरों पर संज्ञान लेते हुए परिवहन मंत्री अनिल विज ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अंबाला में जिला प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई शुरू की गई। डीसी के निरीक्षण के बाद एसडीएम कार्यालय में वाहन पंजीकरण से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। अब एसीबी ने इस जांच का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी एसडीएम कार्यालयों में पंजीकरण रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू कर दी है।

जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं अन्य जिलों में भी फर्जी पते देकर दूसरे राज्यों के वाहनों का पंजीकरण तो नहीं कराया गया। यदि जांच में अनियमितताएं सामने आती हैं तो संबंधित लोगों और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। प्रदेशभर में जांच शुरू होने से वाहन पंजीकरण व्यवस्था में कथित फर्जीवाड़े की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

पंचकूला में कांग्रेस का धरना, एचकेआरएन कर्मचारियों को पक्का करने की मांग

पार्टी ने कहा कि एचकेआरएन कर्मचारियों को लंबे समय तक अस्थायी व्यवस्था में रखना उनके साथ अन्याय है

भारतेन्दु संवाददाता, पंचकूला

हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के कर्मचारियों को पक्का करने और प्रदेश में नियमित सरकारी भर्तियां शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को पंचकूला में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सेक्टर-6 स्थित एचकेआरएन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने एचकेआरएन कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया। पार्टी का कहना है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी लंबे समय से अलग-अलग सरकारी विभागों और संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। कांग्रेस ने सरकार से कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि प्रदेश में सरकारी विभागों में नियमित पद खाली पड़े हैं। इसके बावजूद नियमित भर्ती प्रक्रिया पर्याप्त स्तर पर नहीं हो रही है। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार खाली पदों की पहचान कर नियमित भर्ती शुरू करे, ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। पार्टी ने एचकेआरएन के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों के हितों को भी प्राथमिकता देने की मांग की।

कांग्रेस नेताओं ने धरने के दौरान सरकार की रोजगार नीति पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि युवाओं को स्थायी रोजगार देने के बजाय अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से काम कराया जा रहा है। एचकेआरएन कर्मचारियों को भी लंबे समय तक अस्थायी व्यवस्था में रखना उनके भविष्य के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस ने कहा कि सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के अनुरूप सुरक्षा और स्थायित्व मिलना चाहिए। पार्टी ने सरकार से एचकेआरएन कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में नीति बनाने की मांग की। साथ ही प्रदेश में खाली पड़े सरकारी पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर जोर दिया गया।

पंचकूला में आयोजित इस धरने में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी प्रभारी ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। नेताओं ने धरने के दौरान कर्मचारियों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी की मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। एचकेआरएन कार्यालय के बाहर हुए इस प्रदर्शन के चलते क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज रहीं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के नियमितीकरण और सरकारी भर्तियों का मुद्दा पार्टी आगे भी उठाती रहेगी। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा में बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ऐसे में सरकारी विभागों में खाली पदों को लंबे समय तक रिक्त रखना उचित नहीं है। पार्टी ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया को तेज करने और पारदर्शी तरीके से नियमित नियुक्तियां करने की मांग की।

पार्टी नेताओं ने कहा कि नियमित भर्तियां होने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी भी दूर होगी। वहीं एचकेआरएन कर्मचारियों को स्थायी करने से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो पहले से सरकारी व्यवस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद एचकेआरएन कर्मचारियों का मुद्दा एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल कांग्रेस ने कर्मचारियों को पक्का करने और नियमित भर्तियां शुरू करने की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है।

नौकरी की सलाह देने पर भड़का बेटा पिता की कमर और छाती में मारा चाकू

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद

शहर की भीम बस्ती में नौकरी करने की सलाह देना एक पिता को भारी पड़ गया। आरोप है कि नौकरी की बात से नाराज 22 वर्षीय बेटे ने अपने 46 वर्षीय पिता पर सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दिया। हमले में पिता की कमर और छाती पर गंभीर चोटें आईं। हालत बिगड़ने पर उन्हें फरीदाबाद के बीके अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। मामला ओल्ड फरीदाबाद थाना क्षेत्र का है। घायल बालकिशन ने पुलिस को बताया कि 16 अगस्त की शाम वह अपनी पत्नी पूनम और दोनों बेटों विकास उर्फ विक्की तथा योगेश उर्फ योगी के साथ घर पर मौजूद थे। इसी दौरान वह और उनकी पत्नी बड़े बेटे विकास को नौकरी करने के लिए समझा रहे थे।

परिजनों के अनुसार, पिता की ओर से नौकरी करने की सलाह देने पर विकास नाराज हो गया। आरोप है कि देखते ही देखते बेटे ने गुस्से में पिता पर सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दिया। हमले में बालकिशन की कमर और छाती पर गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई। परिजन घायल पिता को उपचार के लिए फरीदाबाद जिला नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बीके अस्पताल भेजा। बीके अस्पताल में उपचार के दौरान भी उनकी स्थिति चिंताजनक बनी रही। इसके बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के सफदरजंग

अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। परिवार में नौकरी को लेकर हुई बातचीत अचानक हिंसक घटना में बदल गई।

पुलिस घायल पिता के बयान और परिवार के सदस्यों से मिली जानकारी के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि हमले के दौरान घर में मौजूद अन्य सदस्यों ने क्या देखा और विवाद किस बात को लेकर बढ़ा। पिता पर बेटे द्वारा किए गए हमले की घटना से आसपास के लोगों में भी हैरानी है। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल घायल बालकिशन का दिल्ली के अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने घायल पिता के बयान दर्ज कर मामले की जांच तेज कर दी है। आरोपी बेटे से पूछताछ कर घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है।

न्यूज ब्रीफ

16 वर्षीय किशोर का सफल ऑपरेशन, 275 से घटकर 223 किलो हुआ वजन

एजेंसी, नई दिल्ली । सर गंगाराम अस्पताल में चिकित्सकों ने अत्यधिक मोटापे से जूझ रहे 16 वर्षीय किशोर का सफल लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टॉमी ऑपरेशन किया। किशोर का वजन 275 किलोग्राम और बीएमआई करीब 100 था। अत्यधिक मोटापे के कारण उसे सांस लेने में गंभीर परेशानी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और व्यापक त्वचा संक्रमण की समस्या थी। उपचार के लिए उसे कार के बजाय मैटाडोर से अस्पताल लाना पड़ा। चिकित्सकों ने पहले करीब दो सप्ताह उसे बाल गहन चिकित्सा कक्ष में रखकर सर्जरी के लिए तैयार किया। इसके बाद करीब 20 विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने सफल ऑपरेशन किया। सर्जरी के लगभग दो महीने बाद किशोर का वजन 275 से घटकर 223 किलोग्राम रह गया है। चिकित्सकों के अनुसार उपचार का उद्देश्य केवल वजन कम करना नहीं, बल्कि उसकी शारीरिक सक्रियता बढ़ाना, सांस संबंधी परेशानी और स्लीप एपनिया को कम करना तथा मोटापे से जुड़े हृदय और चयापचय संबंधी जोखिमों को घटाना है। ऑपरेशन के दौरान बाल गहन चिकित्सा, मोटापा सर्जरी, हृदय रोग, जठरांत्र और बेहोशी विशेषज्ञों ने समन्वय से काम किया।

कालकाजी में पांच दिन बाद मिला 75 वर्षीय संगीतकार का शव

एजेंसी, नई दिल्ली । कालकाजी थाना क्षेत्र में 75 वर्षीय संगीतकार का शव उनके किराए के कमरे में करीब पांच दिनों तक पड़ा रहा। मृतक रबी डे गोविंदपुरी एक्सटेंशन में पिछले तीन वर्षों से रह रहे थे। 14 अगस्त की रात कमरे से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव बाथरूम के गेट के पास पड़ा मिला। पुलिस ने मृतक के बेटों को घटना की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने रात में आने से इनकार कर दिया। अगले दिन भी वे नहीं पहुंचे। पुलिस के दबाव के बाद 16 अगस्त को दोनों बेटे शवगृह पहुंचे। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए उन्हें सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार मृतक के बेटे लाजपत नगर क्षेत्र में रहते हैं, जो घटनास्थल से करीब पांच किलोमीटर दूर है। मामले ने बुजुर्गों की देखभाल और पारिवारिक संवेदनशीलता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली पीडब्ल्यूडी में अलग इंजीनियरिंग कैडर गठन की राह हुई आसान

एजेंसी, नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग के लिए स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर गठित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। केंद्र से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के बाद कैडर गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार स्वतंत्र कैडर के गठन के बाद दिल्ली पीडब्ल्यूडी अपने इंजीनियरों और अन्य तकनीकी अधिकारियों के लिए भर्ती नियम तैयार करेगा। अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। भर्ती नियम तैयार करने में संघ लोक सेवा आयोग या किसी अन्य विशेषज्ञ संस्था की सलाह लेने की संभावना है। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई में पीडब्ल्यूडी के लिए अलग कैडर बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद विभाग ने प्रस्ताव तैयार करने और आवश्यक मंजूरियां लेने की प्रक्रिया शुरू की। सुधारों को लेकर सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों की समिति भी गठित की गई थी। सरकार का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में कई अधिकारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कैडर नियंत्रण में रहते हैं। बार-बार तबादलों और पदस्थापन के कारण परियोजनाओं की निरंतरता प्रभावित होती है। इससे निर्माण कार्यों में देरी, लागत बढ़ने और जवाबदेही से जुड़ी समस्याएं सामने आती हैं। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद प्रतिनियुक्त अधिकारियों को मूल कैडर में लौटने या निर्धारित शर्तों के तहत नए दिल्ली पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग कैडर में शामिल होने का विकल्प दिया जा सकता है।

हरी नगर एक्सटेंशन में 20 दिन से दूषित पानी, दो हजार से अधिक लोग परेशान

एजेंसी, नई दिल्ली

हरी नगर एक्सटेंशन के ए ब्लॉक में पिछले करीब 20 दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति होने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नलों से आने वाले पानी में गंदगी और बदबू होने के कारण लोग इसे घरेलू कामकाज में इस्तेमाल करने से भी बच रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है।

ए ब्लॉक में 500 से अधिक घर हैं, जिनमें करीब दो हजार लोग रहते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई बार तीन-तीन दिन तक पानी की आपूर्ति नहीं होती। जब पानी आता है तो वह इतना गंदा और दुर्गंधयुक्त होता है कि उसे पीने और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना संभव नहीं रहता। मजबूरी में लोगों को बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है।

लोगों ने बताया कि दूषित पानी आने के कारण घरों की पानी की टंकियां भी जल्दी गंदी हो जाती हैं। कई परिवारों ने टंकियों की सफाई कराई, लेकिन इसके बावजूद अगले दिन फिर गंदा पानी आने से समस्या दोबारा खड़ी हो जाती है। पानी की बदबू से घरों में भी दुर्गंध फैलने की शिकायत लोगों ने की है।

लगातार दूषित पानी की आपूर्ति के कारण परिवारों को पीने के पानी के साथ-साथ खाना बनाने, कपड़े धोने और अन्य जरूरी घरेलू कामों के लिए भी पानी बाहर से मंगाना पड़ रहा है।

दिल्ली की मतदाता सूची में बड़ा बदलाव 47 सीटों पर लाखों नाम होंगे प्रभावित

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 24 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में राजधानी की 70 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों पर 30 से 40 प्रतिशत तक मतदाताओं के नाम बाहर होने की संभावना है। घर-घर सत्यापन अभियान के दौरान 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 47 लाख से अधिक लोगों के सत्यापन प्रपत्र जमा नहीं हुए हैं। ऐसे मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक या दोहरे नाम जैसी श्रेणियों में चिह्नित किया गया है।

मतदाता सूची से नाम हटने का असर केवल ग्रामीण या अनधिकृत क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के पॉश इलाकों में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं। ग्रेटर कैलाश में करीब 35 प्रतिशत, मालवीय नगर में 38.64 प्रतिशत, नई दिल्ली में 41.76 प्रतिशत और आरके पुरम में 44.46 प्रतिशत सत्यापन प्रपत्र जमा नहीं हुए हैं। दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में यह आंकड़ा करीब 48 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

इसके विपरीत कई अनधिकृत कॉलोनियों, झुग्गी बस्तियों और पुनर्वास क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से प्रपत्र जमा करने की स्थिति बेहतर रही है। किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा, करावल नगर, मंगोलपुरी और सीलमपुर जैसे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची से बाहर होने की संभावना है। इससे पता चलता है कि इन क्षेत्रों में डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया का इस्तेमाल अधिक प्रभावी ढंग से किया गया।

अल्पसंख्यक बहुल विधानसभा क्षेत्रों में भी स्थिति एक जैसी नहीं रही। ओखला में करीब 45 प्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन प्रपत्र जमा नहीं हुए हैं। दूसरी ओर सीलमपुर में 23.37 प्रतिशत, मटिया महल में 24.5 प्रतिशत, बाबरपुर में 27 प्रतिशत और मुस्तफाबाद में करीब 28 प्रतिशत प्रपत्र जमा नहीं हुए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार रोहिणी और शकूरबस्ती में डिजिटल प्रपत्र जमा करने की दर सबसे बेहतर रही। रोहिणी में 83.43 प्रतिशत और शकूरबस्ती में 81.26 प्रतिशत प्रपत्र जमा हुए हैं। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची से नाम बाहर होने के बाद भी मतदाताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा।

फरीदाबाद में बिना डिग्री चल रहा था क्लीनिक, हुआ सील

एजेंसी, नई दिल्ली

फरीदाबाद के चंदावली गांव में बिना वैध मेडिकल डिग्री के मरीजों का इलाज करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार को राधिका सरोवर के सामने स्थित साक्षी क्लीनिक पर औचक छापा मारा। कार्रवाई के दौरान क्लीनिक में एक व्यक्ति मरीजों का इलाज करता हुआ मिला। जांच टीम ने जब व्यक्ति से उसकी मेडिकल योग्यता और इलाज से संबंधित आवश्यक दस्तावेज मांगे तो वह कोई वैध मेडिकल डिग्री या प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सका।

टीम के अनुसार, व्यक्ति की पहचान बलराज उर्फ बनवारी लाल के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह डॉक्टर के रूप में मरीजों का उपचार कर रहा था, जबकि उसके पास चिकित्सा प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी वैध योग्यता नहीं थी। मुख्यमंत्री

उड़नदस्ते को पहले सूचना मिली थी कि चंदावली गांव में बलराज नामक व्यक्ति डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर रहा है। सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त टीम बनाई गई और क्लीनिक की जांच की गई। मौके पर पहुंचने के बाद टीम ने क्लीनिक में मौजूद व्यवस्थाओं और इलाज से संबंधित दस्तावेजों की जांच की।

दस्तावेज नहीं मिलने और बिना मान्य डिग्री के मरीजों का उपचार किए जाने की पुष्टि के बाद अधिकारियों ने क्लीनिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जांच के बाद क्लीनिक को सील कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता के मरीजों का इलाज करना गंभीर मामला है और इससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री उड़नदस्ता अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि आरोपी कितने समय से क्लीनिक चला रहा था और उसके पास इलाज कराने के लिए कितने मरीज आते थे।

ग्रेटर नोएडा को मिलेगी हरियाली की सौगात, प्राधिकरण ने जारी किए टेंडर

एजेंसी, नई दिल्ली

ग्रेटर नोएडा को और हरा-भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। शहर में हरियाली बढ़ाने और मौजूदा हरित क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए प्राधिकरण 12 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करेगा। यह धनराशि पार्कों, ग्रीन बेल्ट, सेंट्रल वर्ज और सड़कों के किनारे हरियाली विकसित करने के साथ-साथ उनके रखरखाव पर खर्च की जाएगी। प्राधिकरण ने शहर के नौ प्रमुख सेक्टरों में हरियाली से जुड़े विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये के टेंडर जारी किए हैं। इनमें चाई-5, ओमिक्रान-1ए, केपी-2, केपी-3, ओमिक्रान-3, चाई-3, ज्यू-1, स्वर्ण नगरी और ईकोटेक-1 सेक्टर शामिल हैं।

इन क्षेत्रों में पार्कों के विकास, ग्रीन बेल्ट को बेहतर बनाने और सड़कों के किनारे पौधरोपण व हरियाली बढ़ाने पर विशेष ध्यान

ग्रेटर नोएडा में 12 करोड़ से बढ़ेगी हरियाली, पार्क संवरेंगे

दिया जाएगा। योजना के तहत केवल नई हरियाली विकसित करने पर ही जोर नहीं दिया जाएगा, बल्कि मौजूदा पार्कों और हरित क्षेत्रों के रखरखाव की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए संबंधित स्थानों पर नियमित रूप से पौधों की देखभाल, सिंचाई, घास की कटाई और आवश्यकतानुसार नए पौधे लगाने जैसे कार्य किए जाएंगे।

इससे शहर के हरित क्षेत्रों को लंबे समय तक बेहतर स्थिति में बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्राधिकरण का उद्देश्य शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ पर्यावरण को भी बेहतर बनाना है। लगातार बढ़ते शहरीकरण के बीच पार्क और ग्रीन बेल्ट लोगों को खुले और हरित स्थान उपलब्ध कराते हैं। इन क्षेत्रों में हरियाली बढ़ने से शहर का वातावरण बेहतर होने और लोगों को स्वच्छ एवं सुंदर परिवेश मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण की इस योजना के तहत विकास कार्यों के साथ करीब दो वर्षों तक रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्रयागराज-गोरखपुर वंदे भारत पर बरसे पत्थर, सहमे यात्री

एजेंसी, नई दिल्ली

प्रयागराज-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार दोपहर फाफामऊ पुल के पास पथराव की घटना का शिकार हो गई। गोरखपुर से प्रयागराज आ रही ट्रेन संख्या 22549 जैसे ही फाफामऊ पुल पार कर प्रयागराज जंक्शन की ओर बढ़ी, अचानक उपद्रवियों ने ट्रेन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। घटना दोपहर करीब 1:05 बजे हुई, जिससे ट्रेन में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई। ताबड़तोड़ पथराव के कारण ट्रेन के सी-5, सी-6, सी-7, सी-8 और ई-1 कोच के शीशे टूट गए। पत्थरों की तेज आवाज सुनकर यात्री सहम गए और कुछ देर के लिए ट्रेन के अंदर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

हालांकि, खिड़कियों पर पर्दे खिंचे होने के कारण टूटे शीशे के नुकीले टुकड़े यात्रियों के चेहरों तक नहीं पहुंचे और बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन में सफर कर रहे यात्री

अरविंद राठौड़ ने बताया कि यात्रा सामान्य रूप से चल रही थी, तभी अचानक खिड़की पर तेज धमाके जैसी आवाज आई।

कुछ ही क्षणों में शीशा चटक गया और उसके टुकड़े सीट पर गिरने लगे। घटना से घबराए यात्रियों ने तुरंत 'रेल मदद' ऐप के जरिए रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी। दोपहर करीब 1:22 बजे ट्रेन के प्रयागराज जंक्शन पहुंचते ही आरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। टीमों ने सभी प्रभावित कोचों की जांच की और घटना की जानकारी जुटाई। अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आरोपियों की पहचान के लिए जांच कर रही हैं। रेलवे ने घटना को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। आरपीएफ और पुलिस की टीमें पथराव करने वालों की तलाश में जुटी हैं। अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया।

गुरुग्राम के मंदिर में मिला तीन दिन का नवजात, मचा हड़कंप

एजेंसी, नई दिल्ली

गुरुग्राम के मानेसर स्थित बाबा भीष्मदास मंदिर में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब मंदिर परिसर में करीब तीन दिन का नवजात बच्चा लावारिस हालत में मिला। सुबह मंदिर पहुंचे पुजारी और श्रद्धालुओं ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। आसपास तलाश करने पर बच्चा मंदिर परिसर में मिला। घटना की जानकारी तुरंत मानेसर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नवजात को अपने कब्जे में लेकर तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और उसके शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं। फिलहाल बच्चे की हालत ठीक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि बच्चे के परिजन उसे देर रात अंधेरे में मंदिर परिसर में छोड़कर चले गए होंगे।

शाहदरा में जाम से निजात की तैयारी सलाहकार नियुक्त करने को मंजूरी

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली के शाहदरा इलाके में लगातार बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या को कम करने के लिए प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर की योजना अब आगे बढ़ने लगी है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने बिहारी कॉलोनी और कांति नगर पुल से टाटा टेल्को टी-प्वाइंट तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए सलाहकार नियुक्त करने को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के शुरुआती चरण के लिए 2.63 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है।

यह प्रस्तावित एलिवेटेड रोड स्वामी दयानंद मार्ग, यानी रोड नंबर-57 के पास ट्रंक ड्रेन नंबर-1 के ऊपर बनाए जाने की योजना है। इसका उद्देश्य शाहदरा क्षेत्र में सड़क पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करना और प्रमुख मार्गों पर

शाहदरा में एलिवेटेड कॉरिडोर, जाम से राहत

जाम की स्थिति से लोगों को राहत दिलाना है। परियोजना के पूरा होने के बाद आसपास के इलाकों से आने-जाने वाले वाहन चालकों को बेहतर और तेज आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग के 3 अगस्त के मंजूरी आदेश के अनुसार, सलाहकार की नियुक्ति के लिए स्वीकृत राशि वित्त वर्ष 2026-27 में अनुसंधान एवं विकास तथा व्यवहार्यता अध्ययन से संबंधित बजट से खर्च की जाएगी। सलाहकार परियोजना की तकनीकी और व्यावहारिक संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन करेगा।

इसके बाद परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। परियोजना के शुरुआती चरण में सलाहकार द्वारा विस्तृत यातायात सर्वेक्षण कराया जाएगा। इस सर्वेक्षण के जरिए क्षेत्र में वाहनों की संख्या, यातायात का दबाव, जाम की स्थिति और आने-जाने के प्रमुख मार्गों का अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर यह आकलन किया जाएगा कि प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर यातायात व्यवस्था को किस तरह बेहतर बना सकता है। इसके अलावा सलाहकार परियोजना की व्यवहार्यता का भी अध्ययन करेगा।

ग्रेटर नोएडा में हॉस्टल के स्टोर रूम में आग, सामान जलकर राख

एजेंसी, नई दिल्ली

ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र स्थित सावित्रीबाई फुले कन्या इंटर कॉलेज के हॉस्टल में सोमवार को अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग हॉस्टल के स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। देखते ही देखते आग ने स्टोर रूम में रखे फर्नीचर और अन्य सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद कॉलेज परिसर में मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। घटना के समय हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं अपनी कक्षाओं में पढ़ाई कर रही थीं। इस वजह से छात्राएं आग की चपेट में आने से बच गईं और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और उसे हॉस्टल के अन्य हिस्सों तक फैलने से

रोक दिया। हालांकि, आग की वजह से स्टोर रूम में रखा फर्नीचर और कुछ सामान जलकर खराब हो गया। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।

घटना के बाद कॉलेज प्रशासन और दमकल विभाग ने स्थिति का जायजा लिया। समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

ग्रेटर नोएडा के सावित्रीबाई फुले कन्या इंटर कॉलेज के हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना के बाद कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। आग हॉस्टल के स्टोर रूम में लगी, जहां फर्नीचर और अन्य सामान रखा हुआ था। आग तेजी से फैलने के कारण स्टोर में रखा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय सभी छात्राएं अपनी कक्षाओं में मौजूद थीं। इस कारण किसी भी छात्रा के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है। समय रहते आग बुझा दिए जाने से बड़ा हादसा टल गया। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आग लगने के कारणों और नुकसान की जांच शुरू कर दी है।

प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि पर अवध ओझा का बड़ा बयान, बोले- इसे करता हूं सलाम

अवध ओझा बोले- सामान्य परिवार से तीन बार प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी उपलब्धि

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके अवध ओझा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और जाने-माने कोचिंग शिक्षक अवध ओझा ने प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक उपलब्धि को बड़ी उपलब्धि बताते हुए उनके प्रति सम्मान जताया। उन्होंने कहा कि भले ही वे वैचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी बातों से सहमत नहीं हैं, लेकिन कुछ उपलब्धियां ऐसी हैं, जिनकी सराहना की जानी चाहिए।

अवध ओझा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामान्य परिवार से निकलकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना और लगातार तीन बार देश का नेतृत्व करना अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि किसी सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति का देश की सर्वोच्च राजनीतिक जिम्मेदारी तक पहुंचना आसान नहीं होता। इसके बाद लगातार जनता का विश्वास हासिल करते हुए तीन बार प्रधानमंत्री बनना भी अपने आप में बड़ी राजनीतिक सफलता है। ओझा ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, लेकिन व्यक्तिगत और राजनीतिक उपलब्धियों को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसी नेता के बारे में विचारधारात्मक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसके संघर्ष, मेहनत और उपलब्धियों को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी भावना के तहत उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि को सलाम करने की बात कही। उन्होंने अपने बयान में यह भी संकेत दिया कि लोकतंत्र में राजनीतिक असहमति स्वाभाविक है।

किसी व्यक्ति की नीतियों या विचारों से असहमति होने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी हर उपलब्धि को नकार दिया जाए। ओझा के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह लंबे समय तक देश की राजनीति में अपनी जगह बनाए रखी और लगातार चुनावी सफलता हासिल की, वह राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अवध ओझा का

अवध ओझा ने मोदी की उपलब्धि को सलाम

यह बयान इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि वह खुद आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ चुके हैं।

चुनावी राजनीति में सक्रिय होने के बाद उनके राजनीतिक बयानों पर लोगों की नजर रहती है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ वाला उनका यह बयान इसी कारण राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया। ओझा ने प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि को केवल एक व्यक्ति की सफलता के रूप में नहीं, बल्कि सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के लिए प्रेरणा के रूप में भी देखने की बात कही। उनका मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता किसी व्यक्ति को बार-बार जिम्मेदारी देती है, तो उस जनादेश और राजनीतिक यात्रा का मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। उनके बयान का मुख्य संदेश यही रहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन असाधारण उपलब्धियों को स्वीकार करना भी जरूरी है। अवध ओझा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बनने को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि वह इस उपलब्धि के लिए उन्हें सलाम करते हैं। उनके इस बयान ने एक बार फिर यह चर्चा शुरू कर दी है कि राजनीति में वैचारिक असहमति के बावजूद किसी नेता की व्यक्तिगत उपलब्धियों और संघर्ष को सम्मान दिया जा सकता है।

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त

चंद्रताल, शिकारी देवी और चूड़धार में नई सड़कों के प्रस्ताव रोकने के निर्देश

◆ पर्यावरण संरक्षण पर हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क निर्माण और मानव गतिविधियों के बढ़ते प्रभाव पर गंभीर चिंता जताई है।

अदालत ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है और राज्य सरकार, वन विभाग तथा हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य में कई ऐसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां स्थानीय आबादी नहीं है, लेकिन वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। अदालत ने उदाहरण के तौर पर चंद्रताल झील, शिकारी देवी मंदिर और चूड़धार मंदिर का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि इन स्थलों तक मोटर योग्य सड़कों की पहुंच बनने से पर्यावरणीय नुकसान की आशंका बढ़ गई है। न्यायालय के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में सड़क पहुंच बढ़ने से पर्यावरण पर दबाव बढ़ सकता है और पेड़ों की कटाई जैसे मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। अदालत ने माना कि यह विषय गंभीर विचार का है। हाईकोर्ट ने विशेष रूप से चंद्रताल क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि वन विभाग झील के आसपास रात में कैंप लगाने की अनुमति दे रहा है। अदालत ने सवाल उठाया कि वहां रुकने वाले पर्यटकों से उत्पन्न मानव अपशिष्ट और प्लास्टिक कचरे का निपटान किस प्रकार किया जाता है। न्यायालय ने यह भी जानना चाहा है कि क्या ऐसे स्थानों पर मोबाइल शौचालयों की व्यवस्था उपलब्ध है और प्लास्टिक कचरे के उचित निस्तारण के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। मामले में अदालत ने हिमाचल सरकार के प्रधान सचिव (वन) को पहला प्रतिवादी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक को दूसरा प्रतिवादी और हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को तीसरा प्रतिवादी बनाया है। न्यायालय ने कहा कि यदि चंद्रताल, शिकारी देवी, चूड़धार या ऐसे अन्य संबंधित स्थलों तक नई सड़कें बनाने अथवा मौजूदा सड़कों को तारकोल से पक्का करने के लिए वन स्वीकृति से जुड़े कोई प्रस्ताव लंबित हैं, तो उन्हें फिलहाल स्थगित रखा जाए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में विकास कार्यों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने का मुद्दा महत्वपूर्ण है।

सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए बीपीएल परिवारों का बनेगा व्हाट्सएप ग्रुप: केवल पठानिया

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के धारकंडी क्षेत्र की पंचायतों के बीपीएल सर्वे में चिह्नित 715 परिवारों के सदस्यों के साथ रिडकमार में विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने संवाद किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि बीपीएल परिवारों का एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें प्रदेश सरकार की इन परिवारों से संबंधित सभी कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी साझा की जाएगी। इससे पात्र लाभार्थियों को समय पर योजनाओं की जानकारी मिलेगी और वे उनका लाभ उठा सकेंगे।

उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से भी आह्वान किया कि वे अपने-अपने वार्डों में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें, ताकि योजनाओं का लाभ सही मायनों में पात्र लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों के लिए आने वाले समय में मुख्यमंत्री द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, जिससे इन परिवारों को अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन-पोषण करने में सहायता मिलेगी। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा राहत में ऐतिहासिक वृद्धि की है। अब आपदा के दौरान पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान के मालिक को 7.50 लाख रुपए तथा घर के सामान के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर विधायक ने गत दिनों बोह में आई आपदा के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

एसडीएम शाहपुर गणेश ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार के संवाद कार्यक्रम पूरे विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे हैं। अधिकांश पंचायतों के चिह्नित बीपीएल परिवारों से संवाद किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों को विधायक के माध्यम से प्रदेश सरकार तक भेजा जाएगा।

हिमाचल प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की बिक्री में 39 प्रतिशत की वृद्धि: हर्षवर्धन

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड ने वर्ष 2025-26 के दौरान विपणन एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों की 54.84 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है।

यह वित्त वर्ष 2024-25 में हुई 39.19 करोड़ रुपए की बिक्री की तुलना में 39 प्रतिशत अधिक है। इससे बोर्ड को लगभग 4.50 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। यह जानकारी आज यहां उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड के निदेशक मंडल की 248वीं बैठक के दौरान दी गई। उद्योग मंत्री ने बोर्ड द्वारा विभिन्न उत्पादों की प्रभावशाली बिक्री के लिए उपलब्धियों की सराहना की। बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को वास्तविक कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों का युक्तिकरण करने के निर्देश दिए, ताकि श्रम शक्ति का अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रशासनिक और परिचालन दक्षता को बढ़ाया जा सके। बोर्ड के भवनों एवं परिसरों जैसी परिसंपत्तियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल ने कांगड़ा परिसर में खाली पड़े भवनों एवं बिक्री केंद्रों तथा उदयपुर, होली और पूह स्थित ऊन कार्डिंग केंद्रों को किराये पर देने को मंजूरी प्रदान की।

इस निर्णय से बोर्ड को अतिरिक्त राजस्व अर्जित होने के अलावा बोर्ड आत्मनिर्भर बनेगा। बैठक में अवगत करवाया गया कि वर्ष 2026-27 के लिए बोर्ड ने विपणन एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के तहत उत्पादों की बिक्री का 112 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इसमें से जुलाई 2026 तक 19.71 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य पहले ही हासिल किया जा चुका है। विशेष सचिव वित्त विजय वर्धन, विशेष सचिव उद्योग सुनील शर्मा, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र कंवर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

न्यूज ब्रीफ

इजराइल में केयरगिवर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित, एक सितंबर तक करें पंजीकरण

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से इजराइल में होम बेस्ड केयरगिवर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनुबंध अवधि दो वर्ष होगी, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को 6,443.85 न्यू इजरायली शेकेल मासिक वेतन मिलेगा, जो करीब 1.99 लाख रुपए है। इन कटौतियों के बाद इन-हैंड वेतन लगभग एक लाख रुपए रहने का अनुमान है। अभ्यर्थी के पास कम से कम 990 घंटे का मान्यता प्राप्त केयरगिविंग प्रशिक्षण या नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, नर्स असिस्टेंट अथवा मिडवाइफरी में मान्य डिप्लोमा होना चाहिए। जीडीए, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग योग्यता वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को यात्रा व अन्य निर्धारित खर्च स्वयं वहन करना होगा।

टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस में 150 पदों पर भर्ती

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि मैसर्ज टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड, नालागढ़ ने फ्लोर स्टाफ के 150 नियमित पद अधिसूचित किए हैं। इन पदों के लिए साक्षात्कार 26 अगस्त को जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर में सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं या इससे अधिक तथा आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को 14,300 रुपए मासिक वेतन के साथ ईपीएफ, ईएसआईसी, ओवरटाइम, दो समय निःशुल्क भोजन, दो समय चाय और बस सुविधा प्रदान की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड, दसवीं एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट आकार के फोटो, बायोडाटा और अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियों सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-222450 अथवा नियोक्ता के मोबाइल नंबर 9217669490 पर संपर्क किया जा सकता है।

पारिवारिक विवाद, मां-बेटों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। घुमारवीं उपमंडल के तन्था गांव में मां और बेटों के बीच हुए पारिवारिक विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर क्रॉस प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, संतोष कुमार ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसके छोटे भाई सुनील कुमार और माता कौशल्या देवी ने उसका रास्ता रोककर डंडे और हेलमेट से हमला किया। शिकायतकर्ता ने मारपीट में चोट लगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं, कौशल्या देवी ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके बड़े बेटे संतोष कुमार ने उसके और छोटे बेटे सुनील कुमार के साथ मारपीट की। उन्होंने गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। घुमारवीं पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं। पुलिस का कहना है कि घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच की जा रही है तथा जांच के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

अवैध तौर पर ले जाई जा रहीं शराब की बोतलें पकड़ीं

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। मंडी जिला के अंतर्गत पुलिस थाना करसोग की टीम ने गश्त के दौरान अवैध तौर पर ले जाई जा रही उना नंबर वन ब्रांड की 480 बोतलें पकड़ी तथा इस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस थाना करसोग की टीम बीती रात गश्त, यातायात चेकिंग तथा अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान शंकर देहरा चौक सनारली में एक महिंद्रा कैंपन वाहन एचपी 25 ए-0671 को चेकिंग के लिए रोका गया। वाहन की जब तलाशी ली गई तो नीले रंग की प्लास्टिक तिरपाल से ढकी हुई देसी शराब की 40 पेटियां बरामद हुई वाहन चालक की पहचान विनोद कुमार डाकघर तेवन, तहसील करसोग जिला मंडी के तौर पर हुई है। मौके पर पुलिस ने जब इन पेटियों को खोला तो इसमें 480 बोतलें पाई गई। चालक किसी भी तरह के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। पुलिस ने चालक के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना करसोग में अभियोग पंजीकृत किया है तथा इसे कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

कारीगरों को ब्रांडिंग, एआई टूल्स की दी जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास एवं सुविधा कार्यालय, सोलन की ओर से कांगड़ा जिले के सुलह में पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों के लिए 'ब्रांडिंग और मार्केटिंग' विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता बढ़ाने, बाजार तक पहुंच मजबूत करने और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहा। सहायक निदेशक ग्रेड-1 अभिषेक कुमार राय ने एमएसएमई मंत्रालय की विपणन सहायता योजना, बौद्धिक संपदा अधिकार, मुद्रा, पीएमईजीपी, सीजीटीएमएसई, व्यापार मेलों और बारकोड प्रमाणीकरण सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने लाभार्थियों से सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को मजबूत बनाने का आग्रह किया। उद्योग विभाग की परियोजना प्रबंधन इकाई की नताशा कटोच और अभय कुमार ने आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग तथा व्यवसाय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के उपयोग की जानकारी दी। लीड जिला प्रबंधक पृथ्वी राज ने ऋण प्रक्रिया, वित्तीय साक्षरता और साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताए। जिला समन्वयक हरि दत्त शर्मा ने कारीगरों की समस्याएं सुनीं और समाधान का आश्वासन दिया।

कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं सुक्खू: जयराम ठाकुर

◆ गांधी परिवार के इशारे पर चल रही सुक्खू सरकार

◆ कहा- मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र सराज के बालीचौकी में बुधवार को आयोजित एक विरोध प्रदर्शन और नवनिर्वाचित पंचायतीराज प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू केवल अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं और प्रदेशहित को दरकिनार कर पूरी तरह गांधी परिवार के पिछलग्गू बन चुके हैं।

उन्होंने कहा कि आपदा में नष्ट हुए अनगिनत स्कूलों में से सरकार को केवल वही एक स्कूल दिखा जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का दौरा प्रस्तावित था, और एक नेता के स्वागत के चक्कर में मासूम बच्चों को पूरे एक साल तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया, जिस पर आखिरकार माननीय हाईकोर्ट को कड़ा दखल देना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश में कई स्कूल आपदा में नष्ट हुए लेकिन मुख्यमंत्री को सिर्फ एक स्कूल दिखाई दिया, जहां आपदा में इनकी नेता प्रियंका गांधी तब आई जब सब कुछ सामान्य हो गया था। किसी एक नेता के इंतजार में पूरा एक साल बच्चों को इन्होंने सुविधा से वंचित रखा। सिर्फ एक गांधी परिवार को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री ने सारे कायदे कानून ताक पर रखे और प्रियंका गांधी को उद्घाटन के लिए बुलाने पर अड़े रहे, लेकिन उन्होंने तीनों बार कार्यक्रम में आने से इंकार किया तो माननीय हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा कि आप किसी नेता के इंतजार में बच्चों को सुविधाओं से बंचित नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश की जनता का भरोसा तोड़ा है और अब केवल गांधी परिवार के इशारे पर नाच रहे हैं। पूरे देश ने देखा और सुना कि कांग्रेस नेताओं ने ही ये सवाल खड़ा किया कि मुख्यमंत्री किसको अटैची लेकर दिल्ली जाते हैं और कितनी उनके नाम से इकट्ठा करके अपना घर भर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी अब आपके बस में नहीं रह गया है और आप प्रदेशहित में कुर्सी छोड़ दें। हम एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में हैं।

नाहन कॉलेज के मुख्य द्वार पर तालाबंदी, 6 के खिलाफ मामला दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाहन के मुख्य द्वार पर तालाबंदी करने पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना नाहन में कार्यवाहक प्रधानाचार्य डॉ. देवराज शर्माकी शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया गया कि मंगलवार को प्रातः करीब 10:38 बजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंधित छात्रों द्वारा महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाया गया और परिसर के भीतर नारेबाजी की गई। तालाबंदी के कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों का आवागमन बाधित हुआ तथा महाविद्यालय की सामान्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। मौके पर बातचीत के दौरान संबंधित व्यक्तियों ने बताया कि यह कार्यक्रम राज्यस्तरीय धरने के रूप में आयोजित किया गया था। प्रारंभिक जांच में रमन, आयुष, राहुल, अरुण और दो गैर-छात्र जानवी व गौरव की संलिप्तता मिली है।

भाजपा हमीरपुर ने संगठन में की नियुक्तियां पांचों विधानसभा क्षेत्रों में समन्वयक नियुक्त

◆ भाजपा कानून व विधि प्रकोष्ठ की 11 सदस्यीय जिला टीम घोषित

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर ने संगठनात्मक गतिविधियों को और गति देते हुए जिला कार्यसमिति में रिक्त हुए चार पदों पर नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी है। उखली से सुशील कुमार ठाकुर, बस्सी-भोरंज से उत्तम चंद, रंगस से कविश्का कौशल तथा ननावां-बड़सर से रेणु बाला को जिला कार्यसमिति सदस्य नियुक्त किया गया है। ये पद कार्यसमिति के चार सदस्यों के प्रदेश संगठन में समायोजित होने के बाद रिक्त हुए थे।

जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने पार्टी नेतृत्व और प्रदेश हाईकमान से विचार-विमर्श के बाद भाजपा कानून एवं विधि प्रकोष्ठ की 11 सदस्यीय जिला टीम की घोषणा भी की है। अधिवक्ता राजीव सोनी को जिला संयोजक तथा अधिवक्ता दिनेश ठाकुर को सह-संयोजक नियुक्त किया गया है। अधिवक्ता विवेक शर्मा, राजेश चौहान, सुनय वर्मा, अश्वनी ठाकुर, हिमांशु शर्मा, अक्षय कुमार, राजेश कुमार, नवीन पटियाल और हैप्पी कानूनगो को सदस्य बनाया गया है। संगठन को मजबूत करने के लिए जिला की पांचों विधानसभा सीटों पर पार्टी समन्वयक भी नियुक्त किए गए हैं। हमीरपुर में अजय शर्मा, सुजानपुर में अनिल ठाकुर, नादौन में पवन शर्मा, भोरंज में जयमल ठाकुर और बड़सर में कमल नयन शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह ठाकुर को पांचों मोर्चों का संयुक्त समन्वयक बनाया गया है। राकेश ठाकुर ने कहा कि इन नियुक्तियों से संगठन में नई ऊर्जा आएगी और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित होगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों तथा मंडल प्रभारियों की नियुक्तियां भी जल्द की जाएंगी।

मात्तर स्कूल भवन भाजपा की देन, कांग्रेस ने पंचायत में सड़क-पुलों के काम रोके: डॉ. बिंदल

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने नाहन विधानसभा क्षेत्र की दूरदराज मात्तर पंचायत के मात्तर स्कूल पहुंचकर भारी बारिश के कारण गत दिन खड्ड में आई बाढ़ से मात्तर स्कूल के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के फंसने की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की।

डॉ. बिंदल ने कहा कि मात्तर स्कूल भवन भाजपा सरकार के कार्यकाल में अथक प्रयासों के बाद बनकर तैयार हुआ था। 12 बीघा भूमि वन विभाग से शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित करवाकर लगभग 40 लाख रुपए की लागत से स्कूल के शानदार भवन का निर्माण करवाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय पक्की सड़क जीरो पॉइंट तक पहुंचाई गई थी तथा वहां से स्कूल और निचले गांव तक सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया था। मात्तर एवं नालका संभालका में सड़कों, पुलों पेयजल आदि विकास कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग एवं आईपीएच विभाग को करीब 35 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए थे। डॉ. बिंदल ने कहा कि वर्ष 2022 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद इन विकास कार्यों को पूरी तरह रोक दिया गया। सड़क का एक इंच भी विस्तार नहीं हुआ और आवश्यक पुलों का निर्माण भी नहीं किया गया। इसके चलते आज ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कल भारी बारिश के बाद खड्ड में आई बाढ़ में मात्तर स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षक फंस गए, जिन्हें हिमाचल होमगार्ड व अन्य बलों की टीम ने रेस्क्यू किया। यह घटना बेहद गंभीर और चिंताजनक है। यदि सड़क एवं पुलों के निर्माण का कार्य समय पर पूरे किए गए होते तो बच्चों और शिक्षकों को ऐसी जोखिमपूर्ण स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता।

राहुल को मिला नेशनल ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवॉर्ड

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से संबंध रखने वाले राहुल कपूर, संस्थापक एवं होस्ट द जोआट कास्ट, को कहानी-कथन और मीडिया के माध्यम से हिमालयी क्षेत्र के प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को मंच देने के लिए 8वें नेशनल ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें शिक्षा, मीडिया और कला श्रेणी में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह सम्मान मिला। नई दिल्ली के रैडिसन ब्लू, द्वारका में आयोजित समारोह में राहुल कपूर को यह सम्मान प्रदान किया गया। पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर गौरव गौतम मौजूद रहे। समारोह में दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री राज कुमार आनंद, दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस उपायुक्त लक्ष्मी नारायण राव और ओएनजीसी के पूर्व निदेशक डॉ. जौहरी लाल सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व उपस्थित रहे।

दिसंबर तक तैयार होगा 45 करोड़ का फोरलेन पुल, पंजाब-हिमाचल का सफर होगा जाममुक्त

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले सामरिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग-154 पर चक्की दरिया में बन रहे नए फोरलेन पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस 520 मीटर लंबे पुल को दिसंबर 2026 तक वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) और निर्माण कंपनी आईआरबी की ओर से पुल का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। पुल के कुल 17 पिलरों में से 14 का निर्माण और ऊपरी स्लैब डालने का काम पूरा हो चुका है। पठानकोट की ओर बचे तीन स्पैन का निर्माण मानसून के बाद पूरा किया जाएगा। नए पुल के शुरू होने से चक्की दरिया पर लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। योजना के अनुसार हिमाचल से पठानकोट और पंजाब की ओर जाने वाला यातायात नए फोरलेन पुल से गुजरेगा, जबकि पंजाब से कांगड़ा, धर्मशाला, कुल्लू और मनाली की ओर जाने वाले वाहनों को मौजूदा चक्की पुल से भेजा जाएगा। इस दोहरी यातायात व्यवस्था से दोनों राज्यों के बीच आवागमन सुगम होगा और यात्रा समय में कमी आएगी। पुल की मजबूती के लिए वेल फाउंडेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुल के पिलरों की नींव दरिया के धरातल से करीब 23 मीटर गहराई तक रखी गई है। अगस्त 2022 की बाढ़ और तेज बहाव के कारण पुराने सड़क एवं रेलवे पुलों को हुए नुकसान को देखते हुए यह तकनीक अपनाई गई है। चक्की कॉरिडोर से सामान्य दिनों में प्रतिदिन करीब 20 हजार से 25 हजार वाहन गुजरते हैं। पर्यटन सीजन, सप्ताहांत और नववर्ष के दौरान यह संख्या 35 हजार से 40 हजार तक पहुंच जाती है। प्रतिदिन करीब 80 हजार से एक लाख यात्रियों के इस मार्ग से गुजरने का अनुमान है। यह मार्ग पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और होशियारपुर तथा हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, चंबा, लाहौल-स्पीति और ऊना जिलों के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापार, पर्यटन और परिवहन के साथ-साथ यह हाईवे सामरिक दृष्टि से भी अहम है, क्योंकि सुरक्षा बलों और सैन्य वाहनों की आवाजाही के लिए इसका उपयोग होता है।

राजस्व अधिकारियों को लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे के दिए निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में जिला परिषद कार्यालय मंडी के सम्मेलन कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में 11 जुलाई से 14 अगस्त तक निपटाए गए राजस्व मामलों की समीक्षा की गई। इस अवधि में जिले के तहसील एवं उपतहसील कार्यालयों में तकसीम के 353, निशानदेही के 394 और राजस्व दुरुस्ती के 172 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अलावा 3,615 इंतकाल भी किए गए। उपायुक्त ने अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित तकसीम, निशानदेही और राजस्व दुरुस्ती के मामलों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा। बैठक में स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। पटवारखाना निर्माण, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प, शिकायतों, विशेष राहत पैकेज और देवी-देवता भूमि आवंटन सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

री-इवैल्युएशन के बाद स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की 12वीं की अंतिम मेरिट सूची

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2026 में आयोजित 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा की अंतिम मेरिट सूची जारी कर दी है। पुनर्मूल्यांकन (री-इवैल्युएशन) और पुनः जांच (री-चेकिंग) के बाद आए संशोधित परिणामों को वार्षिक डाटाबेस में समाहित करते हुए यह अंतिम सूची तैयार की गई है। छात्र और अभिभावक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस मेरिट सूची को देख सकते हैं।

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा और परिणाम प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और शुद्धता बनाए रखना बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुनर्मूल्यांकन के परिणामों को मेरिट सूची में जगह देना छात्रों के हितों की रक्षा और त्रुटिहीन मूल्यांकन व्यवस्था के प्रति बोर्ड की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे परीक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार के असमंजस या अनिश्चितता की गुंजाइश न रहे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी मेधावी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि यह सफलता छात्रों के अनुशासन, कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयासों का नतीजा है।

इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों के परिवारों के सहयोग और शिक्षकों के अमूल्य मार्गदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें भी इस उपलब्धि का श्रेय दिया। डॉ. शर्मा ने कहा कि हिमाचल के युवाओं में अपार प्रतिभा और क्षमता है। उन्होंने सफल छात्रों से अपनी उपलब्धियों को नई जिम्मेदारियों की शुरुआत मानते हुए उच्च शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखने का आह्वान किया।

मनरेगा कर्मियों को राहत, मानदेय में नहीं होगी कटौती

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा (वीबीजी रामजी योजना) से जुड़े कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक जुलाई 2026 से लागू नई व्यवस्था के बाद किसी भी कर्मचारी के मानदेय में कटौती नहीं होगी। संशोधित आदेश के अनुसार कर्मचारियों को निश्चित मासिक मानदेय उतना ही मिलेगा, जितना उन्हें 30 जून 2026 तक सकल मासिक पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हो रहा था। विभाग की ओर से जारी शुद्धिपत्र में पहले जारी आदेश के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इससे कर्मचारियों की आय प्रभावित होने की आशंका खत्म हो गई है। मानदेय का भुगतान ग्राम विकास एवं रोजगार गारंटी योजना की प्रशासनिक निधि से किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र के निर्धारित मानकों के अनुसार धन उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने 27 जून को कार्यालय आदेश जारी किया था, जबकि इसके प्रावधान चार जुलाई को राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। केंद्र की 20 जुलाई की अधिसूचना के बाद अब आदेश में संशोधन किया गया है।

कांग्रेस के भीतर 'जयचंद' व 'स्लीपर सेल' सक्रिय : नेगी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब प्रदेश के बागवानी, जनजातीय व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपनी ही पार्टी के संगठन और कुछ नेताओं पर खुलकर सवाल उठा दिए।

उन्होंने कांग्रेस के भीतर 'जयचंद', 'भगोड़े' और 'स्लीपर सेल' सक्रिय होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ वह दिल्ली में पार्टी आलाकमान के समक्ष प्रमाण सहित मामला उठाएंगे। उनका यह बयान बुधवार को राजीव भवन में आयोजित हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदिवासी एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के पदभार ग्रहण समारोह में आया। इस कार्यक्रम में लाहौल-स्पीति से विधायक अनुराधा राणा ने विभाग की नई प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। समारोह में आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और अन्य नेता भी मौजूद थे। अनुराधा राणा को विभाग का अध्यक्ष बनने पर बधाई देने के बाद जगत सिंह नेगी ने संगठन के भीतर चल रही गुटबाजी और अनुशासनहीनता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देशभर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करती है, लेकिन संगठन के भीतर ऐसे लोगों को महत्व दिया जा रहा है जिन्होंने पार्टी के साथ निष्ठा नहीं निभाई और समय-समय पर नुकसान पहुंचाया है। नेगी ने प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर हाल में हुई संगठनात्मक नियुक्तियों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने इन नियुक्तियों को निराशाजनक बताते हुए कहा कि कुछ फैसलों से कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश गया है। उनके अनुसार संगठन में ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं जिनकी भूमिका को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि वह इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे। उन्होंने दावा किया कि उनके पास पर्याप्त जानकारी और प्रमाण हैं।

बारिश से जनजीवन प्रभावित, 166 सड़कें बंद

310 ट्रांसफार्मर और 84 पेयजल योजनाएं प्रभावित, मयाड़ घाटी में अचानक आई बाढ़ से पुल डूबा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में बुधवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। भूस्खलन, पेड़ गिरने और जलभराव की घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश में इस समय 166 सड़कें बंद हैं, जबकि मानसून से होने वाले नुकसान का आंकड़ा बढ़कर एक हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में बिजली और पेयजल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार बीते 24 घंटों में सबसे अधिक 156 मिलीमीटर बारिश हमीरपुर जिले के सुजानपुर टीहरा में दर्ज की गई। इसके अलावा बिलासपुर जिले के नैना देवी में 136 मिलीमीटर, हमीरपुर के नादौन में 128 मिलीमीटर, कांगड़ा जिले के धर्मशाला में 127 मिलीमीटर, ऊना जिले के भरवीं में 118 मिलीमीटर, कांगड़ा के गगल और पालमपुर में 111-111 मिलीमीटर तथा नगरोटा सूरियां में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में नदी-नाले उफान पर हैं। जगह-जगह भूस्खलन होने से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बुधवार सुबह तक प्रदेश में 279 सड़कें बंद थीं। इनमें मंडी जिले में सबसे अधिक 100 सड़कें प्रभावित हैं। चंबा में 83, शिमला में 26, कुल्लू में 25 और सिरमौर में 16 सड़कें बंद हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क भी प्रभावित हुआ है। बारिश का असर बिजली और पेयजल व्यवस्था पर भी पड़ा है। प्रदेश में 310 बिजली ट्रांसफार्मर और 84 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। लाहौल-स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल में 101 ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली आपूर्ति बाधित है। सिरमौर जिले के नाहन, पांवटा साहिब और राजगढ़ क्षेत्रों में 78 ट्रांसफार्मर ठप हैं। मंडी जिले के गोहर, सुंदरनगर, सरकाघाट और धर्मपुर क्षेत्रों में 64 ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं। शिमला जिले के चौपाल और डोडरा-क्वार क्षेत्रों में 27 ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं। पेयजल योजनाओं पर भी बारिश का असर पड़ा है। हमीरपुर जिले के बड़सर और भोटा क्षेत्रों में 32 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। सिरमौर जिले के संगड़ाह क्षेत्र में 23 और शिमला जिले के रामपुर, चौपाल तथा जुब्बल क्षेत्रों में 17 पेयजल योजनाएं बंद हैं। इस बीच लाहौल-स्पीति जिले की मयाड़ घाटी में अचानक आई बाढ़ ने स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। करपट नाले और चौखंग नैनगार के गवाड़ी नाले में जलस्तर अचानक बढ़ने से भारी नुकसान हुआ है। करपट नाले पर बना पुल पूरी तरह पानी में डूब गया और गांव को जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग कट गया। बाढ़ से कृषि योग्य भूमि और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और सभी ग्रामीण सुरक्षित बताए गए हैं।

बारिश से जुड़ी घटनाओं में 205 लोगों की मौत

मानसून से होने वाले नुकसान का दायरा लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में मानसून ने 30 जून को दस्तक दी थी। तब से अब तक बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 205 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 121 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। इसके अलावा 28 लोगों की जान पहाड़ी से गिरने या पेड़ गिरने की घटनाओं में गई है। 14 लोगों की मौत भूस्खलन से, पांच लोगों की मौत बहने से और एक व्यक्ति की मौत फ्लैश फ्लड की घटना में हुई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मानसून के दौरान अब तक सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान का आंकड़ा एक हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सबसे अधिक 750 करोड़ रुपए का नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। जल शक्ति विभाग को 227 करोड़ रुपए की क्षति आंकी गई है। मानसून के दौरान अब तक 85 मकान, 14 दुकानें और 284 पशुशालाएं पूरी तरह ध्वस्त हुई हैं, जबकि 320 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है।

बारिश से अवरुद्ध हुई सड़कों को पीडब्ल्यूडी ने किया बहाल

मानसून सीजन में हमीरपुर में अभी तक लगभग 29.22 करोड़ के नुकसान का अनुमान

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। जिला हमीरपुर के अधिकांश क्षेत्रों में मंगलवार रात और बुधवार सुबह हुई भारी बारिश से काफी नुक्सान हुआ है। जगह-जगह भूस्खलन और पेड़ गिरने से जिले की कई सड़कें अवरुद्ध हो गई थीं, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने तत्परता दिखाते हुए कुछ घंटों में ही अधिकांश सड़कों को यातायात के लिए बहाल कर दिया।

सुजानपुर-संधोल सड़क, बदारन-जोल गाहलियां सड़क, कसीरी महादेव-डूहक-छतरूडू सड़क, टौणी देवी-उहल सड़क, उहल-जंदडू सड़क, लघवाण-टौणी देवी, टियालू-लोहारडा, पंजोत-ललयार, बणी-मटकर और कई अन्य सड़कें भूस्खलन या पेड़ गिरने के कारण कुछ समय के लिए बंद रहीं। अवरुद्ध होने की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग ने मशीनरी एवं लेबर लगाकर अधिकांश सड़कों को तुरंत बहाल कर दिया। उधर, नादौन उपमंडल में मान खड्ड का जल स्तर बढ़ने के कारण नादौन-गौना-धनेटा सड़क भी अवरुद्ध रही। ग्राम पंचायत कश्मीर में कुछ घरों में मलबा आने की सूचना मिलते ही एसडीएम निशांत शर्मा और बचाव दल बुधवार सुबह ही मौके पर पहुंच गए। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के जिला एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (डीईओसी) में बुधवार दोपहर तक प्राप्त प्रारंभिक सूचनाओं के अनुसार गत 24 घंटों के दौरान जिले भर में 15 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान है। इस दौरान एक पक्का मकान, 4 कच्चे मकान और एक गौशाला भी क्षतिग्रस्त हुई है। इसी के साथ इस मॉनसून सीजन में 30 जून के बाद जिला हमीरपुर में सरकारी और निजी संपत्ति के नुक्सान का आंकड़ा 29.22 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

इस अवधि के दौरान जिला में लोक निर्माण विभाग को सर्वाधिक 24.13 करोड़ का नुक्सान हुआ है। जल शक्ति विभाग को 4.53 करोड़, बिजली बोर्ड को 39.48 लाख और शिक्षा विभाग को दस हजार रुपए की क्षति हुई है। 3 कच्चे मकान ध्वस्त होने से लगभग 7.50 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। 9 अन्य कच्चे मकानों और 3 पक्के मकानों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है, जिससे लगभग साढ़े चार लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 13 गौशालाओं के क्षतिग्रस्त होने से लगभग 2.70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए सभी विभागों को किसी भी तरह की आपात परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों के फील्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में हुए नुकसान की रिपोर्ट तुरंत प्रेषित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि बचाव एवं राहत कार्य तुरंत आरंभ किए जा सकें और प्रभावित लोगों की मदद की जा सके। डीसी ने कहा कि आने वाले दिनों के दौरान भी जिला में भारी बारिश हो सकती है। इसलिए, सभी जिला वासी विशेष एहतियात बरतें और नदी-नालों के पास न जाएं। भूस्खलन की आशंका वाले स्थानों से भी दूर रहें। भारी बारिश में घर से बाहर निकलने का जोखिम न उठाएं। खराब मौसम में पेड़ों के नीचे आश्रय न लें तथा बिजली की तारों से सुरक्षित दूरी बनाएं रखें। उन्होंने कहा कि ब्यास नदी के किनारे वाले क्षेत्रों के लोग नदी के पास न जाएं।

न्यूज ब्रीफ

फीस वृद्धि और छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर एबीवीपी ने किया शव प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी इकाई ने प्रदेशस्तरीय मांगों को लेकर शव प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शव का रूप धारण कर प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बढ़ाई गई फीस वापस लेने, छात्र संघ चुनाव बहाल करने तथा सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) के घटाए गए दायरे को पूर्व स्थिति में बहाल करने की मांग उठाई गई। कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। इकाई अध्यक्ष करण ठाकुर ने कहा कि एबीवीपी लंबे समय से फीस वृद्धि वापस लेने और विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि एसपीयू का दायरा घटाने से विश्वविद्यालय के विस्तार और कार्यक्षमता पर असर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो एबीवीपी उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।

डियारा सेक्टर में छात्रों ने लोगों को एचआईवी और नशे से बचाव के प्रति किया जागरूक

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के रेड रिबन क्लब की ओर से प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल की अध्यक्षता में डियारा सेक्टर में जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य मां से बच्चे में एचआईवी व सिफलिस संक्रमण की रोकथाम, नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता व इंजेक्शन के माध्यम से नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों में एचआईवी संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी देना था। अभियान के दौरान विद्यार्थियों ने स्थानीय लोगों को क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में संचालित ओएसटी (ओपिओइड सब्स्टीट्यूशन थेरेपी) केंद्र की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नशे की लत से प्रभावित लोगों के लिए केंद्र में निशुल्क उपचार व परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों ने ओएसटी उपचार के लाभों तथा नशीली दवाओं पर निर्भरता कम करने के उपायों की जानकारी दी। साथ ही दूषित सुइयों को साझा करने से एचआईवी सहित अन्य संक्रमणों के खतरे के बारे में भी जागरूक किया। विद्यार्थियों ने लोगों से नशे से दूर रहने, सुरक्षित व्यवहार अपनाने व समय पर चिकित्सकीय सहायता लेने का आग्रह किया। उन्होंने नशे की लत से जूझ रहे लोगों से असुरक्षित तरीकों के बजाय उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की। रेड रिबन क्लब की नोडल अधिकारी डॉ. सोनिया राठौर ने बताया कि अभियान में करीब 40 विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए और कई लोग भावुक हो गए। अभियान का उद्देश्य नशा-मुक्त एवं एचआईवी-मुक्त समाज के निर्माण को बढ़ावा देना रहा।

घुमारवीं कॉलेज की पीटीए सभा 23 अगस्त को

भारतेन्दु संवाददाता, घुमारवीं। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पीटीए (अभिभावक-शिक्षक संघ) की वार्षिक आम सभा 23 अगस्त 2026, रविवार को सुबह 10:30 बजे कॉलेज परिसर में आयोजित होगी। कॉलेज के प्राचार्य प्रो. प्रीतम लाल ने बताया कि इस बार सुरक्षा एवं सत्यापन को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों के प्रवेश के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभा में केवल वही माता-पिता या रक्त संबंधी अभिभावक भाग ले सकेंगे, जिन्होंने पीटीए नामांकन फॉर्म भरकर उसमें अपनी फोटो लगाई होगी। इसके साथ ही प्रत्येक अभिभावक को अपने पुत्र या पुत्री का कॉलेज पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। बिना पहचान पत्र के किसी भी अभिभावक को महाविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्राचार्य ने कहा कि कॉलेज के समग्र विकास में पीटीए की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावकों और शिक्षकों के बीच बेहतर समन्वय विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखता है। उन्होंने सभी अभिभावकों से समय पर पहुंचकर सभा को सफल बनाने की अपील की।

मोहीं सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। पुलिस थाना तलाई के अंतर्गत मोहीं क्षेत्र में 18 अगस्त को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार हादसे में अभिषेक कुमार (18) पुत्र मदन लाल, निवासी गांव मन्नण, डाकघर सुन्हाणी, तहसील झंडूता तथा विनोद कुमार (40) पुत्र स्वर्गीय राम रत्न, निवासी गांव व डाकघर बड़गांव, तहसील झंडूता घायल हुए थे। दोनों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बरठीं पहुंचाया गया। गंभीर हालत के चलते अभिषेक कुमार ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, विनोद कुमार का अस्पताल में उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके और अस्पताल पहुंचकर जांच की। पुलिस थाना तलाई में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया व पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया। हादसे के कारणों की जांच जारी है।

सीपीआरआई आज मनाएगा 78वां स्थापना दिवस

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), शिमला अपना 78वां स्थापना दिवस समारोह 20 अगस्त को आयोजित करेगा। समारोह में शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कुमार कश्यप मुख्यातिथि, जबकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. महावीर सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। संस्थान के समाज विज्ञान संभाग के अध्यक्ष डॉ. आलोक कुमार ने बताया कि समारोह के दौरान स्थानीय स्कूलों के विद्यार्थियों को आलू अनुसंधान में हो रही नई प्रगति से अवगत करवाया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय प्रगतिशील किसानों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा। किसानों के साथ तकनीकी सत्र में संवाद भी होगा, जिसमें वे अपने अनुभव साझा करने के साथ समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों से प्राप्त कर सकेंगे। समारोह में संस्थान के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए 'बेस्ट वर्कर अवॉर्ड' प्रदान किए जाएंगे। साथ ही स्थानीय संस्थानों की ओर से प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी।

सस्त्र गांव को 40 वर्ष बाद मिलेगी पक्की सड़क : सुनील

बिजली की वोल्टेज की समस्या का समाधान 10 दिन में किया जाएगा

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि हमीरपुर के निकटवर्ती गांव सस्त्र में लगभग 40 वर्ष से चली आ रही सड़क की समस्या का अतिशीघ्र समाधान किया जाएगा और बरसात के बाद गांव के लिए एक बेहतरीन पक्की सड़क बनाई जाएगी। बुधवार को गांव सस्त्र के अपने दौरे के दौरान जनसमस्याओं की सुनवाई करते हुए सुनील शर्मा बिट्टू ने यह घोषणा की।

उन्होंने कहा कि गांव में बिजली की वोल्टेज की समस्या के अतिशीघ्र समाधान के लिए भी बिजली बोर्ड के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि हमीरपुर शहर के बाहरी क्षेत्रों में विकास की एक नई क्रांति आने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के लिए कई नए संस्थान और राज्य स्तर के कार्यालय मंजूर किए हैं। इन संस्थानों और कार्यालयों के लिए स्वाभाविक रूप से शहर के बाहरी क्षेत्रों में ही पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी।

इससे गांव सस्त्र और हमीरपुर शहर के कई अन्य बाहरी क्षेत्र भी तेजी से विकसित होंगे। हमीरपुर से पक्का भरो, सस्त्र, मटाहणी, सलासी, झनियारी, नेरी, जोल सप्पड़ और रंगस तक के क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेगा। यह मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की दूरदर्शी एवं विकासात्मक सोच के कारण ही संभव हो रहा है। इससे पहले, सस्त्र पहुंचने पर सुनील शर्मा बिट्टू का गांववासियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर गांववासी मुश्ताक मुहम्मद, अली मुहम्मद, जमील, बाबू खान, सलीमो बेगम, रजिया बेगम, लालद्दीन, मुश्ताक, शशि मुहम्मद, रमेश चंद, विशाल, कर्ण, जमील खान, रीता देवी, सोनिका और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

नूरपुर पुलिस ने पूर्व में दर्ज नशा तस्करी के मामलों में वांछित दो आरोपी किए काबू

भारतेन्दु संवाददाता, नूरमपुर। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना नूरपुर में दर्ज नशा तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंक जांच के आधार पर वांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहले मामले में बीते 28 जून 2026 को रजत पुत्र राकेश कुमार, निवासी नौशेरा पत्तन, तहसील मुकेरियां, जिला होशियारपुर, पंजाब, आयु 32 वर्ष को दर्ज नशा तस्करी के मामले में पुलिस टीम द्वारा पुलिस स्टेशन शाहपुर कंडी, पठानकोट (पंजाब) से गिरफ्तार किया गया।

वहीं, दूसरे मामले में रंगीला राम पुत्र टेक चंद, निवासी गांव बजोट, डाकघर थलटूखोड़, तहसील पधर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश, आयु 52 वर्ष को 22 अप्रैल 2026 को दर्ज नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एसपी नूरपुर इलमा अफरोज ने बताया कि इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी मामलों की जांच के दौरान विकसित किए गए बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंक के आधार पर की गई है। जांच में नशीले पदार्थों की सप्लाई के स्रोत, सप्लाई चैन तथा इससे जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के अवैध कारोबार के नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंक के आधार पर लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने 9.51 ग्राम चिट्टे के साथ युवक को किया गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। पुलिस थाना कोट कहलूर की टीम ने नशे की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टोबा क्षेत्र में गश्त एवं चेकिंग के दौरान एक युवक को चिट्टे सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान गुरिंदर सिंह (31) पुत्र मोहन सिंह, निवासी गांव नंद बहल, डाकघर टोबा, तहसील श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली, जिसमें उसके कब्जे से 9.51 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने बरामद नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में पुलिस थाना कोट कहलूर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है तथा नशे की तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

23 को बिलासपुर में होगा राष्ट्र गौरव सम्मान समारोह

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। समाज कल्याण फेडरेशन ऑफ इंडिया की हिमाचल प्रदेश इकाई की ओर से भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में 23 अगस्त 2026, रविवार को बिलासपुर में राष्ट्र गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम चंगर सेक्टर स्थित भाषा एवं संस्कृति सभागार में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे समापन होगा।

प्रदेश अध्यक्ष ललिता कश्यप ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार होंगे। कर्नल जसवंत सिंह चंदेल विशिष्टातिथि, जबकि जिला भाषा अधिकारी नीलम चंदेल अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। उन्होंने बताया कि समारोह का उद्देश्य राष्ट्र, समाज, भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करना और समाज में सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से शिक्षाविद, साहित्यकार, पत्रकार और सामाजिक क्षेत्र की हस्तियां भी शामिल होंगी। ललिता कश्यप ने कहा कि भाषा और संस्कृति समाज की पहचान हैं, इसलिए इनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। समारोह के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मान देने के साथ युवाओं को राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बिलासपुरवासियों से अधिक संख्या में समारोह में पहुंचने की अपील की।

बिलासपुर में मारपीट और यातायात बाधा समेत पांच मामले दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर में पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मारपीट, यातायात बाधित करने और तेज रफ्तार वाहन से चोट पहुंचाने के आरोप में पांच मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने सभी मामलों में भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना तलाई में चंपा देवी की शिकायत पर भगत राम के खिलाफ रास्ता रोककर गाली-गलौज व मारपीट का मामला दर्ज हुआ। थाना बरमाणा में देश राज उर्फ पम्मी पर सड़क किनारे रेता-बजरी डालकर यातायात बाधित करने पर केस दर्ज किया गया। घुमारवीं में कर्म सिंह की शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ मारपीट व गाली-गलौज, जबकि रोहित शर्मा की शिकायत पर विजय कुमार के खिलाफ रास्ता रोककर मारपीट का मामला दर्ज हुआ। थाना भराड़ी में पूनम सिंह की शिकायत पर वाहन चालक पृथ्वी चंद के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने मामलों की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच जारी है।

1965 के युद्ध में शहीद हुए गरीबू राम को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान

विधायक आशीष शर्मा ने भी शहीद के परिवार को किया सम्मानित

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत ललीण के टुकलेहड़ा गांव निवासी बलिदानी सिपाही अमर शहीद गरीबू राम के परिवार को उनके देश के लिए दिए बलिदान के 61 वर्ष बाद राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है।

16 अगस्त को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक में आयोजित समारोह में भारतीय सेना और भारत सरकार की ओर से उनके परिजनों को सेना और भारत सरकार की ओर से सम्मानित किया गया। वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में अटारी बार्डर पर गरीबू राम शहीद हुए थे। युद्ध में बलिदान देने के लिए उन्हें मेडल से सम्मानित किया गया था। वहीं, 15 डोगरा रेजीमेंट ने दिल्ली में उनके परिजनों को सम्मानित किया है। दिल्ली में आयोजित समारोह में शहीद के भाई एवं पूर्व सैनिक जुल्फी राम, उनकी पत्नी शकुंतला देवी, पुत्रवधू रीना देवी, करण कुमार शर्मा, भानजे राजकुमार और उनकी पत्नी कांता देवी शामिल हुईं। ने सम्मान प्राप्त किया। इसी कड़ी में बुधवार को विधायक सदर आशीष शर्मा ने उनके गांव जाकर शहीद के भाई जुल्फी राम एवं परिवार को सम्मानित किया। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 15 डोगरा रेजीमेंट में तैनात 25 वर्षीय गरीबू राम शहीद हो गए थे, अब उन्हें सरकार द्वारा सम्मान दिया गया। यह सम्मान मिलने से परिवार के साथ पूरा क्षेत्र गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गरीबू राम पुत्र इंद्र दत्त और माता कौशल्या देवी के पुत्र थे। शहीद होने से करीब दो वर्ष पहले उनका विवाह रोशनी देवी से हुआ था। उस समय रोशनी देवी की उम्र महज 18 वर्ष थी। पति की बलिदान के बाद उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया और पूरा जीवन उनकी स्मृतियों के साथ बिताया। पंचायत प्रधान सोनिका और उपप्रधान रोहित शर्मा ने कहा कि इस सम्मान से पूरा क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने विधायक आशीष शर्मा का भी शहीद के परिवार को सम्मानित करने के लिए आभार व्यक्त किया है।

संवाद विद्यार्थियों को दिलाई नशामुक्त हिमाचल की शपथ, वर्षाशालिका की घोषणा

शिक्षा ही जीवन में आगे बढ़ने का सशक्त माध्यम: धर्माणी

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। नगर व ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने राजकीय महाविद्यालय घंडालवीं के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व, कौशल विकास, करियर निर्माण और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

राजेश धर्माणी ने कहा कि शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है, जिसके जरिए व्यक्ति जीवन में आगे बढ़कर अपने सपनों को साकार कर सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से केवल डिग्री या डिप्लोमा हासिल करने तक सीमित न रहने, बल्कि विषय के गहन ज्ञान के साथ स्वयं को हुनरमंद और सक्षम बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ उसे जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक भी बनाती है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपना स्वॉट विश्लेषण करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपनी शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों का आकलन कर जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रणनीति तैयार करें। साथ ही करियर का रोडमैप बनाने, शैक्षणिक लक्ष्य निर्धारित करने और अंग्रेजी संप्रेषण कौशल को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दें। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक और मोबाइल फोन का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए न करते हुए ज्ञान अर्जन और स्वयं को अपडेट रखने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने नियमित व्यायाम, अच्छी पुस्तकों के अध्ययन और संचार कौशल में सुधार के साथ प्रतिदिन पुस्तकालय जाने की आदत विकसित करने की सलाह दी। सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए समाचार पत्रों, विशेषकर संपादकीय पृष्ठ का नियमित अध्ययन करने का भी आग्रह किया। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मनिर्भर बनने, स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य निर्धारित करने और दूसरों से अनावश्यक तुलना करने के बजाय अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं और व्यक्ति के विचार ही उसके व्यक्तित्व एवं चरित्र का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों को झिझक दूर कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर अपनी प्रतिभा और कौशल की पहचान करनी चाहिए। संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे, जिनका मंत्री ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन को भविष्य में एक्सपोजर विजिट आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिल सके। साथ ही कॉलेज में विभिन्न क्लब स्थापित कर विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा विकसित करने के अवसर देने को कहा। विद्यार्थियों की मांग पर मंत्री ने मुख्य सड़क पर वर्षाशालिका बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने विद्यार्थियों को नशामुक्त हिमाचल अभियान के तहत नशामुक्ति की शपथ दिलाई। इससे पहले कॉलेज की प्राचार्य प्रो. रीता शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया।

कत्ल की गई महिला के घर पहुंची पठानकोट कांग्रेस, जताई संवेदना

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट के घरथौली मोहल्ले में सोमवार की रात बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद इलाके में दहशत और रोष का माहौल है।

इसी बीच पठानकोट कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। जिलाध्यक्ष एवं पूर्व मेयर पन्ना लाल भाटिया के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेसियों ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पठानकोट शहर और मोहल्लों में स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। नशा इस कदर फैल चुका है कि लोग अब अपने घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आशीष विज ने कहा कि नशा हर मोहल्ले में बिक रहा है और यही कारण है कि शहर में क्राइम का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार नशा मुक्त पंजाब की बात करती है। विज ने कहा कि जमीनी हालात ये हैं कि आए दिन चेन स्नैचिंग, चोरी और लूट की वारदातें हो रहीं हैं। लेकिन, अधिकतर मामलों में पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। ऐसे में लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले भाजपा पार्षद रामपाल विक्की भी शहर में लगातार बढ़ते नशे और क्राइम को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ युवक देर रात तक मोहल्लों में घूमते रहते हैं और बंद घरों तथा अकेले रहने वाले बुजुर्गों के घरों की रेकी करते हैं। विक्की ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए दावा किया कि नशे के आरोप में पकड़े गए लोग जल्द ही छूटकर वापस आ जाते हैं। उन्होंने पुलिस से नशे और आपराधिक गतिविधियों पर सख्ती से लगाम लगाने की मांग की।

◆ **नेताओं ने कहा- शहर में नशा चरम पर, घर में भी सुरक्षित नहीं लोग**

इवोना डाडिच का खूबसूरत अंदाज

ऑस्ट्रिया। इवोना डाडिच ऑस्ट्रिया की प्रसिद्ध एथलीट हैं, जिन्होंने बहु-प्रतियोगिता स्पर्धाओं में देश का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने हेप्टाथलॉन में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2017 में उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा और मेहनत का परिचय दिया।

गॉल टेस्ट में भारत की शानदार जीत, श्रीलंका को 165 रन से हराया

मानव सुथार ने 10 विकेट लिए, देवदत्त पडिक्कल ने जड़ा शतक

एजेंसी, कोलंबो

भारत ने गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। यह भारत का 600वां टेस्ट मैच था। भारत की जीत के हीरो 24 साल के लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुथार रहे। उन्होंने श्रीलंका की दूसरी पारी में 6 विकेट सहित मैच में 10 विकेट लिए। वहीं, देवदत्त पडिक्कल ने पहली पारी में 167 और दूसरी पारी में 44 रन की पारी खेली थी। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

सुथार को एक ओवर में 3 विकेट

मैच के पांचवें दिन बुधवार को दूसरी पारी में श्रीलंका का स्कोर 75 ओवर में 6 विकेट पर 199 रन था। सुथार ने अगले ओवर में तीन विकेट लेकर भारत की जीत लगभग तय कर दी। इस ओवर में सुथार ने सोनल दिनुषा, प्रभात जयसूर्या और लाहिरु कुमारा को आउट किया। श्रीलंका का स्कोर 9 विकेट पर 199 रन हो गया। सुथार ने अपने अगले ओवर में केशरा नुवांथा को आउट कर श्रीलंका की पारी समेट दी।

सुथार ने एक ओवर में लिए तीन विकेट

मानव सुथार ने श्रीलंका की दूसरी पारी के 75वें ओवर में 3 विकेट लेकर मैच का रुख भारत के पक्ष में कर दिया। उन्होंने पहले सोनल दिनूषा को 84 रन पर आउट किया। इसके बाद सुथार ने प्रभात जयसूर्या को पहली ही गेंद पर बोल्ड किया और अगली गेंद पर लाहिरू कुमारा को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। यह टेस्ट में सुथार का लगातार दूसरे मैच में दूसरा 5 विकेट हॉल है।

यशस्वी ने डिकवेला से कहा-छक्का मारो, आईपीएल में ले जाऊंगा

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट के आखिरी दिन यशस्वी जायसवाल और निरोशन डिकवेला के बीच मजेदार बातचीत देखने को मिली। स्क्वायर लेग पर खड़े यशस्वी ने डिकवेला से कहा कि एक छक्का मारो, मैं तुम्हें आईपीएल में ले जाऊंगा। डिकवेला ने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं। पहले मुझे आईपीएल में ले जाओ, फिर मारूंगा। मजेदार बात यह रही कि इसी ओवर में डिकवेला ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और स्लिप में कैच देकर आउट हो गए।

अपराजेय रहते हुए दूसरे दौर में जाना चाहेगी भारतीय महिला हॉकी टीम

एजेंसी, एम्सटेलवीन

शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय महिला हॉकी टीम एफआईएच विश्व कप में पहले दौर के अंतिम मैच में वीरवार को इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज करके पूल डी की शीर्ष टीम के रूप में अपराजेय रहते हुए दूसरे दौर में प्रवेश करने के इरादे से उतरेगी। पहले ही मैच में ओलंपिक रजत पदक विजेता और दुनिया की चौथे नंबर की टीम चीन को 2 -2 से ड्रॉ पर रोकने के बाद भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से रौंदकर अपना गोल ओसत सबसे बेहतर कर लिया है । भारत और चीन के पूल डी में एक जीत और एक ड्रॉ के बाद चार चार अंक हैं लेकिन भारत ने दो मैचों में आठ गोल किये और तीन ही गंवाये हैं जबकि चीन ने छह गोल किये और चार गंवाये हैं । बेहतर गोल औसत के आधार पर भारत शीर्ष पर है ।

चीन से 2 -4 से हारी इंग्लैंड टीम के तीन अंक हैं यानी उसे हर हालत में यह मैच जीतना होगा जबकि भारत ड्रॉ खेलने पर भी अगले दौर में पहुंच जायेगा । दक्षिण अफ्रीका दोनों मैच हारकर दौड़ से बाहर ही हो चुका है जिसे आखिरी मुकाबला चीन से खेलना है। कोच शोर्ड मारिन की भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अभी तक अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है । पहले मैच में चीन की कठिन चुनौती के बावजूद ड्रॉ कराने के बाद दक्षिण अफ्रीका को 6 -1 से हराया और अहम बात यह है कि छह गोल छह अलग अलग खिलाड़ियों ने किये । भारत की 11 खिलाड़ियों का यह पहला विश्व कप है, लेकिन उन्होंने दबाव लिये बिना अपना स्वाभाविक खेल दिखाया है।

भारत का पेनल्टी कॉर्नर भी बेहतर हुआ है जिसमें स्टार ड्रैग फ्लिकर दीपिका के साथ शानदार फॉर्म में चल रही नवनीत कौर ने भी योगदान दिया है । दोनों खिलाड़ी अभी तक दो दो गोल कर चुकी हैं जबकि गोल के सामने बिछू देवी और 300 से अधिक मैच खेल चुकी अनुभवी सविता पूनिया ने भी सराहनीय प्रदर्शन किया है।

एफआईएच विश्व कप में आज इंग्लैंड से होगा मैच

स्पोर्ट्स विंडो

सिंकफील्ड कपः आर प्रज्ञानानंदा ने मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव को हराया

एजेंसी, सेंट लुई। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञाननंदा ने सिंकफील्ड कप शतरंज टूर्नामेंट के आठवें दौर में फ्रांस के मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव को हराकर अमेरिका के वेस्ली सो के साथ संयुक्त बढ़त हासिल कर ली है। इस जीत से प्रज्ञाननंदा ने संभावित आठ में से पांच अंक हासिल कर लिए हैं और भारतीय खिलाड़ी ने इस साल के अंत में होने वाले ग्रैंड फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रज्ञाननंदा ने केवल 28 चाल में जीत हासिल की। जिस दिन वेस्ली ने अपने हमवतन सेवियन सैमुअल्स के साथ एक और ड्रॉ खेला, उसी दिन जावोखिर सिंदारोव ने नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फोरेस्ट को हराया और लगातार तीसरा मैच जीतकर 4.5 अंकों के साथ शीर्ष खिलाड़ियों के करीब पहुंच गए। दिन के एक अन्य महत्वपूर्ण मैच में जर्मनी के विन्सेंट कीमर ने शीर्ष वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी फैबियानो कारुआना को हराकर सिंदारोव के साथ तीसरे स्थान पर जगह बनाई। दिन के एक अन्य रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड के अनीश गिरी ने अमेरिका के लेवोन अरोनियन के साथ ड्रॉ खेला।

सात्विक-चिराग विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

एजेंसी, नई दिल्ली। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने दूसरे दौर में वॉकओवर मिलने के बाद बुधवार को यहां बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। विश्व चैंपियनशिप में पहले दो कांस्य पदक जीत चुकी पांचवीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी तथा दूसरे दौर में उनका मुकाबला स्कॉटलैंड के एलेक्जेंडर डन और एडम प्रिंगल से होना था। स्कॉटलैंड की जोड़ी ने हालांकि आखिरी क्षण में नाम वापस ले लिया, जिससे सात्विक और चिराग को कोर्ट में उतरे बिना ही 'राउंड ऑफ 16' में जगह मिल गई। तनीशा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिश्रित युगल जोड़ी ने भी मकाऊ के लियोन इओक चोंग और एनजी वेंग ची को 21-11 21-11 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। भारतीय खिलाड़ियों में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन को भी बुधवार को अपने मैच खेलने हैं।

वीनस विलियम्स को यूएस ओपन के विमेंस सिंगल्स ड्रॉ के लिए वाइल्ड कार्ड

एजेंसी, न्यूयॉर्क। 7 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन वीनस विलियम्स को यूएस ओपन के विमेंस सिंगल्स मुख्य ड्रॉ के लिए वाइल्ड कार्ड मिला है। टूर्नामेंट ने एक और वाइल्ड कार्ड की घोषणा रोक रखी है। यह जगह उनकी छोटी बहन और 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स को मिल सकती है। सेरेना ने इस साल विंबलडन में सिंगल्स के जरिए टेनिस में वापसी की थी। सेरेना विलियम्स के सिंगल्स में खेलने के फैसले के लिए यूएस ओपन का आखिरी वाइल्ड कार्ड रोका गया है। सेरेना विलियम्स के सिंगल्स में खेलने के फैसले के लिए यूएस ओपन का आखिरी वाइल्ड कार्ड रोका गया है। 46 साल की वीनस पिछले साल भी वाइल्ड कार्ड के जरिए स ओपन में खेली थीं। उन्होंने 2023 के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के अनुसार, वीनस 1981 में 47 साल की उम्र में खेलने वाली रेनी रिचर्ड्स के बाद यूएस ओपन सिंगल्स में उतरने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं।

बांग्लादेश में गहराया बिजली संकट, भारत से मांगी ऊर्जा मदद

एजेंसी, नई दिल्ली। बांग्लादेश इन दिनों गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। राजधानी ढाका के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना आठ से दस घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। बिजली बचाने के लिए सरकार ने दुकानों और शॉपिंग मॉल को रात आठ बजे के बाद बंद रखने तथा सजावटी रोशनी पर रोक जैसे कदम उठाए हैं। वित्तमंत्री अमीर खुसरो चौधरी के अनुसार संकट से पूरी तरह उबरने में करीब दो वर्ष लग सकते हैं। सरकार ने भारत से ऊर्जा सहयोग की उम्मीद जताई है। इस संकट का असर उद्योग, व्यापार और आम लोगों पर भी पड़ रहा है।

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लगातार 21 महीने से नंबर-1 बॉलर

एजेंसी, दुबई

आईसीसी ने 19 अगस्त को मेंस वीकली रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में लगातार 21 महीने से नंबर-1 बने हुए हैं। बुमराह ने नवंबर 2024 में पहला स्थान हासिल किया था और तब से इसे बरकरार रखा है। उनके खाते में 870 रेटिंग पॉइंट्स हैं। वहीं, वनडे बैटर्स की रैंकिंग में शुभमन गिल टॉप पर बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश की ऐतिहासिक 9 विकेट की जीत का असर रैंकिंग में देखने को मिला है। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग में फिर नंबर-1 बन गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड खिसककर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। ब्रूक के बाद इंग्लैंड के जो रूट दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। टॉप 4 बल्लेबाजों के बीच केवल 33 रेटिंग पॉइंट्स का अंतर

वनडे में गिल टॉप बल्लेबाज टेस्ट में हैरी ब्रूक नंबर-1 बैटर

ट्रैविस हेड को खराब प्रदर्शन का नुकसान

डार्विन टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड केवल 22 और 17 रन ही बना सके। इस प्रदर्शन के कारण हेड पहले से चौथे स्थान पर आ गए हैं। उनके स्थान गंवाने का फायदा इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को मिला, जिन्होंने टॉप पर वापसी कर ली है।

डोप टेस्ट में फेल होने के बाद किर्गियोस टेनिस से निलंबित

एजेंसी, मेलबर्न। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार निक किर्गियोस के करियर को एक और बड़ा झटका लगा है। रॉयटर्स के मुताबिक, पूर्व विंबलडन फाइनलिस्ट किर्गियोस को कोकीन के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रोविजनल तौर पर टेनिस से निलंबित कर दिया गया है। इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने बुधवार को इस मामले की जानकारी दी।

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी निक किर्गियोस का 22 जून को मल्लोर्का ओपन के दौरान डोपिंग टेस्ट किया गया था। बाद में उनके सैंपल में बेंजोइलइक्गोनिन पाया गया, जो शरीर में कोकीन के टूटने से बनने वाला पदार्थ है। इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी (ITIA) ने चार अगस्त को किर्गियोस पर अस्थाई निलंबन लगाया।

संस्था ने कहा कि किर्गियोस को इस फैसले को चुनौती देने का अधिकार है, हालांकि घोषणा के समय तक उन्होंने इसके खिलाफ अपील नहीं की थी।

कोचिंग की विशिष्ट शैली ने छोटे लाल यादव को बनाया द्रोणाचार्य

एजेंसी, नई दिल्ली

दिग्गज एमसी मैरी कॉम के करियर को आगे बढ़ाने से लेकर जैस्मीन लैंबोरिया को विश्व चैंपियन में बदलने तक, छोटे लाल यादव ने प्रत्येक मुक्केबाज की जरूरतों को समझकर अपना कोचिंग करियर बनाया है, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसने उन्हें प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार दिलाया है।

सेना में कार्यरत 38 वर्षीय छोटे लाल काफी हद तक चर्चाओं से दूर रहे जबकि उनसे कोचिंग लेने वाले मुक्केबाज सुर्खियों में रहे। मैरी कॉम की वापसी, जैस्मीन का विश्व खिताब तथा साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक उस यात्रा के निर्णायक मील के पत्थर हैं जो तब शुरू हुई जब चोट ने यादव को रिंग से कोचिंग की तरफ मोड़ दिया।

यादव ने पीटीआई से कहा, 'मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे यहीं नहीं रुकना है। मुझे और मेहनत करनी होगी। मेरा लक्ष्य है कि मेरे मुक्केबाज लॉस एंजिलिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतें।' एक मुक्केबाज के रूप में यादव 2001 से 2012 तक राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रहे और वह सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग में भी खेले। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लिया। यादव ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और 2008 से 2010 तक लगातार तीन वर्षों तक फीदरवेट वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन रहे।

उन्हें 2000 में वाराणसी से पुणे स्थित सेना की 'ब्वॉयज स्पोर्ट्स कंपनी' में लाया गया था और वह 2005 में सेना में शामिल हो गए। लेकिन 2012 में पीठ की चोट ने मुक्केबाज के रूप में ओलंपिक में भाग लेने की उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद उन्होंने मुक्केबाजी तो नहीं छोड़ी, लेकिन अपनी भूमिका बदल ली। कोचिंग से उनका पहला गंभीर परिचय उसी साल हुआ जब उन्हें मैरी कॉम की मदद करने के लिए कहा गया। यह उनके कोचिंग करियर का महत्वपूर्ण मोड़ था। यादव ने 2014 में पटियाला स्थित राष्ट्रीय खेल संस्थान से कोचिंग डिप्लोमा पूरा किया और 2017 तक वह मैरी कॉम के साथ पूर्णकालिक रूप से काम करते रहे। उन्होंने कहा, 'मेरे प्रशिक्षण लेने से पहले ही वह चैंपियन थी। मेरी सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि एक दिग्गज खिलाड़ी और चैंपियन को चैंपियन कैसे बनाए रखा जाए।' उस समय तक मैरी कॉम पांच बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता बन चुकी थीं।

यादव का काम उन्हें चैंपियन बनना सिखाना नहीं, बल्कि उन्हें चैंपियन बनाए रखने के तरीके खोजना था।

सेंसेक्स 326 अंक गिरा, 76910 पर बंद

निफ्टी में 77 अंक की गिरावट, एनर्जी शेयर्स में ज्यादा बिकवाली

एजेंसी, मुंबई

शेयर बाजार में 19 अगस्त को गिरावट रही। सेंसेक्स 326 अंक की गिरावट के साथ 76,910 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 77 अंक की गिरावट रही, ये 24,078 पर बंद हुआ। स्त्रख्र्स्न, मीडिया और एनर्जी शेयर्स में आज ज्यादा बिकवाली रही।

शिपरॉकेट लिमिटेड का शेयर अपने 97 रुपए प्रति शेयर के IPO प्राइस से 35% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। NSE पर शिपरॉकेट का शेयर 131 रुपए पर खुला, जबकि BSE पर यह 33.51% प्रीमियम के साथ 129.50 रुपए पर लिस्ट हुआ। इसका मतलब है कि शिपरॉकेट के IPO ने शेयर पाने वाले निवेशकों को पहले ही दिन 35% का मुनाफा दिया है। वहीं गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का आईपीओ आज ओपन हो गया है।

कंपनी इसके जरिए 550 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इस आईपीओ में 21 अगस्त तक बोली लगा सकते हैं।

चांदी-सोने के दाम गिरे

नई दिल्ली। सोने-चांदी की कीमतों में 19 अगस्त को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, एक किलो चांदी की कीमत 5,772 रुपए गिरकर 2.27 लाख रुपए पर आ गई है। वहीं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,196 रुपए कम होकर 1.53 लाख रुपए पर है।

फेरारी की पहली इलेक्ट्रिक सुपरकार ने रचा इतिहास, 382 करोड़ में बिकी पहली यूनिट

एजेंसी, नई दिल्ली। फेरारी ने इलेक्ट्रिक सुपरकार के क्षेत्र में कदम रखते हुए अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक कार फेरारी ल्यूचे की पहली इकाई चेसिस शून्य के साथ इतिहास रच दिया है। मोंटेरे में आयोजित आरएम सोथबी की चैरिटी नीलामी में इस कार की बोली 40 मिलियन डॉलर यानी करीब 382 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। खास बात यह रही कि कार की शुरुआती अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख डॉलर थी। इस तरह अंतिम कीमत शुरुआती अनुमान से करीब 40 गुना अधिक रही। नीलामी से प्राप्त पूरी राशि फेरारी फाउंडेशन को दी जाएगी, जिसका उपयोग भविष्य की शैक्षणिक पहलों के लिए किया जाएगा।

फेरारी ल्यूचे की डिलीवरी 2027 की पहली तिमाही में होने की उम्मीद है। इससे पहले कार को मारानेलो स्थित फेरारी मुख्यालय ले जाकर अंतिम रूप देने और परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बिक्री ने 2025 में 2.6 करोड़ डॉलर में बिकने वाली फेरारी डेटोना एसपी3 का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है।

कार के डिजाइन में एप्पल के पूर्व डिजाइन प्रमुख जॉनी आइव के लवफ्रॉम स्टूडियो का योगदान है। इसमें चार इलेक्ट्रिक मोटर हैं, जो करीब 1035 हॉर्सपावर की ताकत देती हैं। कार महज 2.5 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम गति 310 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 122 किलोवाट-घंटे की बैटरी और करीब 530 किलोमीटर की अनुमानित दूरी तय करने की क्षमता है।

गोयल सिंगापुर दौरे पर, व्यापारिक संबंधों को मिलेगी नई गति

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 19 से 21 अगस्त तक सिंगापुर की यात्रा पर हैं। इस दौरान वह द्विपक्षीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और सिंगापुर के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग, बाजार पहुंच और कौशल विकास को और मजबूत करना है। उनके साथ भारतीय उद्योग और व्यापार क्षेत्र का करीब 70 वरिष्ठ प्रतिनिधियों वाला उच्चस्तरीय दल भी सिंगापुर पहुंचा है।

गोयल 20 अगस्त को चौथी भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मंच मानी जाती है। बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी और कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बैठक में भाग लेंगे।

यात्रा के दौरान गोयल सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग सहित कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वह वहां के प्रमुख उद्योग समूहों और निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य, कृषि, समुद्री क्षेत्र और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में संभावनाओं पर चर्चा करेगा।

निप्पो ने एयर प्यूरिफिकेशन बाजार में रखा कदम, पेश किया एयरव्यू

एयर प्यूरिफायर कारोबार 100 करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य

एजेंसी, नई दिल्ली

नयी दिल्ली में निप्पो ब्रांड नाम से कारोबार करने वाली इंडो नेशनल लिमिटेड ने एयर प्यूरिफिकेशन कारोबार में प्रवेश करते हुए निप्पो एयरव्यू पेश किया है। बैटरियों के लिए पहचान रखने वाली कंपनी ने पहली बार टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों की श्रेणी में कदम रखा है। कंपनी ने अलग-अलग आकार के कमरों के लिए चार एयर प्यूरिफायर और हवा की गुणवत्ता मापने के लिए दो मॉनिटर बाजार में उतारे हैं। इन उत्पादों के माध्यम से कंपनी का उद्देश्य घरों के अंदर की हवा को स्वच्छ रखने के साथ उसकी गुणवत्ता की लगातार निगरानी करना है।

पीएम 2.5 और सूक्ष्मजीवी प्रदूषण घटाने का दावा

एयरव्यू श्रृंखला में पीएम 2.5 को 99 प्रतिशत, फॉर्मल्डिहाइड को 99.9 प्रतिशत और सूक्ष्मजीवी प्रदूषण को 99.99 प्रतिशत तक कम करने का दावा किया गया है। उपकरणों को वाई-फाई और मोबाइल अनुप्रयोग के जरिए नियंत्रित किया जा सकेगा। फिल्टर छह से दस महीने में बदलने होंगे और उपभोक्ता इन्हें स्वयं बदल सकेंगे। कंपनी ने अगले तीन वर्षों में इस कारोबार को 100 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

कंपनी के अनुसार देश में एयर प्यूरिफायर का बाजार करीब 1,500 करोड़ रुपये का है और यह 30 से 35 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रहा है। दिल्ली-एनसीआर इस बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसलिए कंपनी ने शुरुआत इसी क्षेत्र से करने का निर्णय लिया है।

सलाह पीएम के सलाहकार बोले-महंगाई कंट्रोल करने पर ध्यान दे सरकार

रुपए को गिरने से बचाने की नहीं जरूरतः संजीव

एजेंसी, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा कि भारत को रुपए में गिरावट रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उसे मार्केट के हिसाब से अपना स्तर तय करने देना चाहिए। वहीं हमारा मुख्य फोकस महंगाई दर को कंट्रोल में रखने पर होना चाहिए। सान्याल ने कहा कि जब देश ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को अपनाया था, तब उसने करेंसी एक्सचेंज रेट के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी को चुना था। संजीव सान्याल ने बताया कि ओपन कैपिटल अकाउंट वाली अर्थव्यवस्थाओं में पॉलिसी मेकर्स के सामने कई चुनौतियां होती हैं। भारत का फ्रेमवर्क इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी देश एक साथ स्वतंत्र मॉनेटरी पॉलिसी चलाने और अपनी करेंसी की विनिमय दर को सख्ती से कंट्रोल करने का काम नहीं कर सकता। भारत जैसे बड़े और आंतरिक रूप से मजबूत देश के लिए रुपए की दर तय करने के बजाय महंगाई दर को लक्षित करना ही सही कदम है।

सान्याल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को रुपए के स्तर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग सिस्टम ने देश में बहुत अच्छा काम किया है। एक समय था जब भारत में महंगाई दर 8% से 12% के दायरे में रहती थी, जबकि पिछले एक दशक में यह सफलतापूर्वक घटकर 2% से 6% के दायरे में आ गई है। उन्होंने कहा कि यदि देश में महंगाई दर कंट्रोल रहती है, तो रुपए में गिरावट से भारतीय निर्यात को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। सान्याल के मुताबिक, मुख्य चिंता यह होनी चाहिए कि क्या करेंसी में आ रही गिरावट से देश के भीतर महंगाई बढ़ रही है। यदि महंगाई कंट्रोल में है और जरूरत पड़ने पर ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं, तो रुपए को बचाना सही तरीका नहीं है।

विदेशी मुद्रा भंडार का हो सही इस्तेमाल

संजीव सान्याल ने कहा कि फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करेंसी में होने वाले अचानक या तेज उतार-चढ़ाव की रफ्तार को धीमा करने और झटकों को संभालने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग रुपए को उसके स्वाभाविक स्तर पर पहुंचने से रोकने के लिए नहीं होना चाहिए।